फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 01:52 उपरांत द्वितीया विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

| हल्द्वानी |

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ ■ बरेली ■ कानपुर ■ मुरादाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

सोमवार, 2 फरवरी 2026, वर्ष 5, अंक 343, पृष्ठ 18 ■ मूल्य 6 रुपये

आम बजट 2026-27

अहम बातें

एमएसएमई : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान

एफएंडओ पर एसटीटी 0 .02 से 0 .05 फीसदी की गई

17 कैंसर की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप

नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टेक सपोर्ट देगी सरकार

बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस

इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

7,84,678	2,77,830	1,39,289	1,06,530	2,55,233
रक्षा	रेलवे	शिक्षा	स्वास्थ्य	गृह मंत्रालय

सभी राशि करोड़ रुपये में

टैक्स वही, सोच नई

53.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश

बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टैक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य

यह हुआ महंगा

- इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना : टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
- चल संपत्ति का खुलासा न करना : अब इस पर पेनल्टी लगेगी
- स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग : सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0 .02% से बढ़ाकर 0 .05% किया गया
- छाते और उनके पाट्र्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) ड्यूटी लगेगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7 .5 प्रतिशत कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

सस्ती हुई चीजें

- माइक्रोवेव ओवन के खास पाट्र्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं
- चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटी
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पाट्र्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5–20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर की गई
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगेगा।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ
- फ्रोजन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफल पर टैरिफ 30 से घटाकर 5 प्रतिशत
- आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बैगेज नियमों में ढील के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है।

वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।

- **आर्थिक ग्रोथ :** सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- **जनता की उम्मीद :** दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- **सबका साथ, सबका विकास :** सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार धराशायी, सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा

मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी बिकवाली के दबाव में निवेशकों के 9 .40 लाख करोड़ रुपये डूब गए। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370 .36 अंक यानी 2 .88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899 .42 अंक पर खिसक गया था।

- **सात साल में सबसे बड़ी गिरावट, वित्त मंत्री बोलीं- सट्टेबाजी को रोकना है मकसद, निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे**

हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546 .84 अंक यानी 1 .88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722 .94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 .20 अंक यानी 1 .96 प्रतिशत गिरकर 24,825 .45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748 .9 अंक यानी 2 .95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571 .75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पावधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घावधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

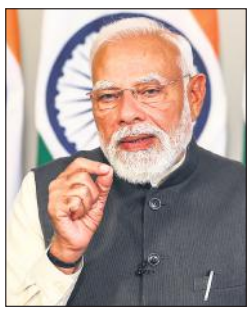

सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला बजट : धामी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और समावेशी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि किसानों, महिलाओं, वंचितों, युवाओं, छोटे उद्यमियों और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर के लिए पर्यावरण–अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना है।

वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 प्रतिशत से कम है। कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तांतरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

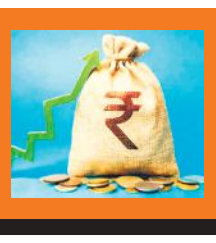

देश के बजट से ही हेल्थ-वेल्थ मजबूत कर लेगा उत्तराखंड

अजय दयाल, हल्द्वानी

- भारत की रिफार्म एक्सप्रेस से देवभूमि को भी मिलेगी रफ्तार
- विदेशी टूर पैकेज, कृषि, पर्यटन और मेडिकल क्षेत्र का होगा विकास

अमृत विचार: जब केन्द्रीय बजट पेश होता है तो देश के सभी राज्य बड़ी उत्सुकता से जानने-समझने को प्रयासरत होते हैं कि उन्हें क्या मिला? ठीक वैसे ही जैसे मुखिया अथवा अभिभावक पर आश्रित उसके अपने। ऐसे में रविवार को पेश हुए केन्द्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड राज्य में भी काफी उत्सुकता रही। हाल ही में उत्तराखंड ने अपने स्थापना की रजत जयंती मनायी है। ऐसे में 25 बरस के चिर युवा राज्य को कुछ ज्यादा पाने की लालसा तो रही ही होगी? हालांकि जो मिले-जितना मिले उसी में मस्त रहने का मिजाज भी यहां की मूल भावना है।

हकीकत यह है कि केंद्रीय बजट से पूरे देश के लिए जो रिफार्म एक्सप्रेस चलायी गई है, उसी से उत्तराखंड अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों मजबूत कर लेगा। ऐसे में जिन क्षेत्रों पर मोदी सरकार ने सर्वाधिक ज्यादा धन आवंटित किया है, उनसे उत्तराखंड में भी रेल, सड़क, पुल, टनल, रोपवे ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक की कनेक्टिविटी तेज होगी। इस कनेक्टिविटी से उत्तराखंड को चारधाम जैसे धार्मिक यात्राओं ही नहीं आपदा की स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों तक पर पहुंचने में सुगमता होगी। राज्य की कनेक्टिविटी को रफ्तार देने में राज्यों को दी जा रही पूंजीगत निवेश के लिए विशेष ऋण की व्यवस्था सहायक होगी। स्वाभाविक तौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए रेल, सड़क, पानी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण मार्ग और पर्यटन ही नहीं किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनजर खेती से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी हों तो बजट को सार्थक ही कहेंगे।

इतना ही नहीं, बजट में पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बायोफार्मा क्षेत्र में किए गए निवेश से देश के साथ-साथ उत्तराखंड का भी लाभ होना तय है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और अवसंरचना के लिए दीं गईं योजनाएं उत्तराखंड को लाभान्वित करेंगीऔर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। खासकर विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स रिफॉर्म से उत्तराखंड के भी पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा।

केन्द्रीय बजट में जिस तरह पहाड़ी राज्यों के लिए पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना दी गई है स्वाभाविक है उससे उत्तराखंड के संदर्भ में भी पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। वहीं, किसानों, पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि, पर्यटन और एमएसएमई के लिए किए प्रावधान यहां की ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बायोफार्मा क्षेत्र में किए गए निवेश से राज्य और देश दोनों का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होगा।

अगर बजट में प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया गया है और तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाने की योजना है तो इसका भी लाभ देवभूमि को मिलना तय है। इस राज्य को लेकर पहले ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, बजट में उच्च शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूती देने से आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वैज्ञानिक भी उत्साहित हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड उनमें से है जो अपने जैसे दूसरे पर्वतीय राज्यों के साथ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के समान भी विकास के अवसर तलाशने और निरंतर आगे बढ़ने का दमखम रखता है।

उत्तराखंड के लिए खुलीं रोजगार और विकास की नई संभावनाएं

उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणाएं सराहनीय

प्रमुख संवाददाता देहरादून

अमृत विचार: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणा की है। बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है। इन ट्रेल्स के बनने से ट्रेकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी जैसे प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा।

केन्द्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों के किसानों के लिए अधिक मूल्य वाली फसलों जैसे अखरोट और चिलगोजा की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इससे किसानों की जहां आय बढ़ेगी वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बजट में पर्यटन और कृषि से जुड़े ताजा कदम उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खोलेंगे।

मालधन चौड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टीवी पर बजट देखते रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट।

केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को फायदा मिलेगा। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में मुख्य घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुओं के लिए ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स का फायदा बाइकिंग के क्षेत्र में मिलेगा। सरकार मानना है कि खासकर उत्तराखंड जैसा पर्यटन राज्य आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा इंजन बनेगा। बजट का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह बजट न केवल देश की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को भी समान रूप से विकास के अवसर देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बजट में घोषित योजनाओं और प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी।

उत्तराखंड को बजट से लाभ

- टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को फायदा मिलेगा
- इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित होगा
- माउंटेन ट्रेल्स का फायदा बाइकिंग के क्षेत्र में मिलेगा
- क्षेत्रीय मेडिकल हब से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
- निजी क्षेत्र की सहभागिता से भी हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे
- आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र होंगे
- स्वास्थ्य पेशेवरों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान उत्तराखंड में बनने की संभावना

बजट पर प्रतिक्रिया

विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला है बजट

संवाददाता, देहरादून

अमृत विचार : भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को शानदार, दमदार, आम आदमी की सोच वाला और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला बताया।

डॉ. बंसल ने कहा कि डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में उल्लेख किया है कि भारत में वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग की जब भी चर्चा होगी, उत्तराखंड का नाम शीर्ष पर होगा। मोदी सरकार एवं राज्य सरकार का विजन दुर्गम मार्गों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने का है। यह केवल एडवेंचर टूरिज्म नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक आध्यात्मिक अनुभव भी है।

उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी इन चारों वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट में कई योजनाएं हैं।

उत्तराखंड को विशेष पैकेज नहीं मिलने से निराशा: सुमित हृदयेश

हल्द्वानी : स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश ने बजट पर अपना तर्क रखा है। कैसा है, इसका सबसे बड़ा मानक सेंसेक्स और निफ्टी जैसी मार्केट्स होती हैं। आज स्टॉक मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स में आई भारी गिरावट साफ दर्शाती है कि यह बजट पूरी तरह निराशाजनक है। सुमित हृदयेश के मुताबिक, उत्तराखंड जैसे आपदा-प्रभावित पहाड़ी राज्य के लिए किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज न दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और किसानों को इस बजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यह बजट आम जनता की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है।

कृषि और उद्योग को राहत नहीं: रावत

संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार: बजट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर करारा हमला बोला है. हरीश रावत ने कहा, निर्मला सीतारमण का यह जो 9वां बजट है। यह 2047 के विकसित भारत का नक्शा खींचते-खींचते ग्रामीण भारत को भूल गया है, कृषि को भूल गया है, लघु उद्योग को भूल गया है, यह तीनों सेक्टर्स के एलोकेशन को देखिए तो इनकी वृद्धि रक्षा, रक्षा राष्ट्रीय आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट या दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले बहुत कम दिखाई देती है इसका अर्थ है कि ग्रामीण रोजगार घटेंगे, छोटे उद्योग जिस स्थिति में थे उनके सामने और अपने को मजबूत करने का इस बजट में कोई प्रयास या कोई उनको प्रोत्साहन नहीं किया गया है।

आगे हरीश रावत ने कहा, हिमालयी क्षेत्रों के लिए भी उत्तराखंड, हिमाचल आदि के लिए ट्रैकिंग हब बनाने की बात कही गई है।

मगर ईको-टूरिज़्म के जो दूसरे पहलू हैं उन पर फोकस करने की बात और उसके लिए पूंजीगत निवेश की जरूरत थी, उस दिशा में इस बजट में कुछ कहा नहीं गया है तो इसका अर्थ है कि हिमालयी राज्यों को भी कुछ विशेष नहीं मिलने जा रहा है।

फार्मा क्षेत्र को मिलेगी गति दवा उत्पादन में होगी वृद्धि

संवाददाता, देहरादून

अमृत विचार: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा के लिये बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। देश में तीन नये एम्स की स्थापना, दो नये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तथा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थानों की स्थापना होगी।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिये बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत देश में बायोलॉजिक्स व बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपचार सस्ता और सुलभ हो सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्रीय बजट के अनुरूप राज्य स्तर पर ठोस प्रस्ताव तैयार किये जाएं, ताकि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह बजट नागरिकों को सशक्त बनाएगा और भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करेगा।

टीवी पर केन्द्रीय बजट देखते कृषि मंत्री गणेश जोशी व अन्य।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी

संवाददाता, देहरादून

अमृत विचार: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

लखपति दीदी योजना को और विस्तार देने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए देशभर में और अधिक रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे, जिससे महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ने, स्थायी आय के साधन विकसित करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

लखपति दीदी योजना को और विस्तार देने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए देशभर में और अधिक रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे, जिससे महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ने, स्थायी आय के साधन विकसित करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित भारत का संकल्प होगा साकार: अजय भट्ट

नैनीताल : पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ बजट है। श्री भट्ट ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की स्पष्ट, दृढ़ और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने नौवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को साकार करने वाला यह बजट वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को रेखांकित करता है। सात प्रतिशत से अधिक विकास दर, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और विकसित भारत 2047 की दिशा में उठाए गए ठोस कदम इसकी स्पष्ट झलक है।

किसानों और महिलाओं को मिली निराशा: आर्य

हल्द्वानी : केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बजट भारत की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता है। जारी बयान में कहा कि किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या इनकम सिक्योरिटी प्लान का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर से भी आगे निकल गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता नहीं दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे उन राज्य सरकारों को कोई राहत देंगी जो गंभीर वित्तीय संकट में हैं। कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पर कोई रिवाइवल रणनीति नहीं है और 13 प्रतिशत पर अटकी हुई है। सरकार बताए कि आज मेक इन इंडिया कहां है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार या वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई गंभीर योजना नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट, टैरिफ जोखिम, व्यापार घाटा, घटते वैश्विक हिस्से पर कोई जवाब नहीं। गिरते रुपये के लिए कोई प्लान नहीं है। इस तरह महंगाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी पर कोई महत्तवपूर्ण घोषणा नहीं है।

दिशाहीन और विकास अवरोधी बजट में आम आदमी के हितों का नहीं रखा गया है ध्यान : गणेश गोदियाल

हल्द्वानी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र के बजट को दिशाहीन और विकास अवरोधी बताया। कहा यह बजट अपने उद्योगपति मित्रों का पोषक और आम आदमी के हितों के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। उन्होंने केंद्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दिशाहीन विकास विरोधी महंगाई को बढ़ाने वाला और देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला बजट पेश किया है। कहा केंद्रीय बजट में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों और आम आदमी की घोर उपेक्षा की गई है. देश की वित्त मंत्री ने बजट में एक बार फिर से आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है. उन्होंने आम बजट में तीन कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि में तेजी, जन आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास जैसी कोरी बातें की है. केंद्रीय बजट में सात उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की बात 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने जैसे जुमले छोड़े गए।

समावेशी विकास और विकसित भारत का मजबूत संदेश देता है केन्द्र सरकार का बजट: बंशीधर भगत

हल्द्वानी : कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इसे युवाशक्ति पर केंद्रित, समावेशी और विकासपरक बजट करार दिया। 53 .5 लाख करोड़ रुपये के बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12 .2 लाख करोड़ करने से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निजी निवेश को जोर मिलेगा। बजट में गरीब, किसान, महिलाएं, युवा, एससी/एसटी और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण योजनाओं, दिव्यांग कौशल कार्यक्रम और खेलो इंडिया जैसी पहलों से सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और उभरते सेक्टर्स में युवाओं के लिए नए रोजगार के मौके बनेंगे। विधायक भगत ने निष्कर्ष में कहा कि यह बजट समावेशी विकास का मजबूत संदेश देता है, जिसमें विकास के लाभ समाज के हर वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचें। यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की ठोस नींव रखता है।

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

स्वस्थ भारत

• स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10% पिछली बार से ज्यादा

निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के तौर पर काम करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, बजट आवंटन को 45 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 में 21,901.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 22,343.97 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली स्थित एम्स के लिए आवंटन 5,238.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500.92 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के लिए 4,821.21 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्युटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।

दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एप्लाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एएचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एएचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे।

कैंसर के साथ सात अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें होंगी कम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के साथ सात और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रियायतों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी यानी इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सात और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं के आयात शुल्क में भारी छूट दी गई है। मूलभूत सीमा शुल्क वह टैक्स है जो भारत सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाती है और यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लिया जाता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के काम में आने वाली दवाओं की कीमत पर पड़ेगा।

- बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अच्छी गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।

पहला निमहांस बेंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तांत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

शिक्षित भारत

8.27% से ज्यादा वृद्धि

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक ''लॉजिस्टिक'' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोज़गार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।

15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार देश के युवाओं को कंटेंट क्रिएशन में अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है : प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नर्चरिंग इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार ने इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध,नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है।

2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

- 2025-26 में 2,52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025-26 की बात है, कमाई और खर्च के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारे मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।

बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावशाली ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020-21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई! इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

- रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत व्यय 1,86,454 करोड़ रुपये अनुमानित था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1.39 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा) वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा आवंटन अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत है और यह 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 15.19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

1.85 लाख करोड़ में सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रावधान

1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए व्यय करने का प्रावधान

17,250 करोड़ अनुसंधान व विकास पर होगा खर्च

12,100 करोड़ भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए

खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए है जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाने के सरकार के संकल्प को और सुदृढ़ किया है।

डीआरडीओ के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक

कोलकाता। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनॉय दास ने कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है। दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बिना शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है। दास के मुताबिक, डीआरडीओ से अगली पीढ़ी की ऐसी तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्होंने साइंस सिटी सभागार में कहा कि हमें ऐसे उपकरणों पर काम करना होगा, जिनका हमारे सशस्त्र बल सपना देख रहे हैं। हम ऐसे उपकरणों के आयात का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और युद्ध के परिदृश्यों में समीकरण बदल गए हैं। दास को विज्ञान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए जेआईएस महा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह बजट हमें उन प्रणालियों को साकार करने और सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिन्हें हम विकसित करते हैं। यह निर्यात के माध्यम से आर्थिक महाशक्ति बनने में सहायक होगा। पहले भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात से वंचित रखा गया था और आज हम आयात से इन्कार कर रहे हैं। भारत ने गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त की हैं और पूर्णत: आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है।

5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताते हुए कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं- शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों बेंगलुरु, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-ईरोड-तिरुप्पुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विधि मंत्रालय को ईपीआईसी के लिए मिले 250 करोड़

मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच बजट में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 500 करोड़ अलग से दिए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 99 करोड़ है। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-अदालत परियोजना को मिला 1,200 करोड़

सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना के तृतीय चरण के लिए केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमान के 1,500 करोड़ के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई-अदालत परियोजना क्रियान्वयन में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

2.5 लाख करोड़ में खुफिया तंत्र और मजबूत करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय

कुल धनराशि का 68% हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ पुलिस मद के लिए किए गए निर्धारित

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025-26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक है। बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ रुपये पुलिस मद के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को 2026-27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईबी के आवंटन में पिछले बजट की तुलना में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले बजट में आईबी के लिए 4,159.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है, जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों की जानकारी एकत्रित करके और उनकी पड़ताल करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।

एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि से रोकेंगे सट्टेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मकसद उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया, जो डेरिवेटिव बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा गंवा रहे थे। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, विकल्प सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। अब तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1% और विकल्प कारोबार पर 0.125% था।

बजट के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार वायदा-विकल्प कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा कि यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है। सेबी के अध्ययनों के अनुसार, एफएंडओ खंड में 90% से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस खंड में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह निकट अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।

12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4%

सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए घोषित 12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% है और अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में घोषित 11.11 लाख करोड़ के बजटीय पूंजीगत व्यय से 10% अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है कि 12.22 लाख करोड़ का सार्वजनिक व्यय किया जाएगा। इस बार यह जीडीपी का 4.4% है। यह कम से कम पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है और यदि आप पिछली अवधि के आंकड़ों को भी देखें तो यह संभवत: सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.5% और 2024-25 में 4.0% था। वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार का पूंजीगत व्यय 2.35 लाख करोड़ रुपये था। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यथार्थवादी है।

सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने को एसटीटी बढ़ाया : राजस्व सचिव

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना और प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। एफएंडओ में सट्टेबाजी से छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से वायदा-विकल्प बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को संभालने के लिए है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस वृद्धि के बाद भी एसटीटी की दरें होने वाले लेनदेन की मात्रा की तुलना में मामूली रहेंगी।

मौजूदा कीमतों पर 10% वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए जीडीपी में मौजूदा कीमतों पर 10% की वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण है। बजट दस्तावेज के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि को वास्तविक संदर्भ में 393 लाख करोड़ आंका गया है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में मुद्रास्फीति कम है और कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति अकेला मूल्य संशोधन कारक नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप इसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का अनुमान यथार्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 10% वृद्धि का अनुमान जीडीपी के मौजूदा आधार वर्ष और उपयोग की गई गणना पद्धति पर ही तय किया गया है। सरकार फरवरी में कई वृहद-आर्थिक संकेतकों, जैसे जीडीपी और खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने जा रही है।

एसटीटी वृद्धि से पूंजी बाजार पर बढ़ेगा दबाव, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार के लिए दबाव पैदा कर सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक धीरज रेल्ली ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीपल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तीव्र वृद्धि व्यापारियों, जोखिम प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य आमदनी अधिकतम करने से अधिक लेन-देन की मात्रा को नियंत्रित करना प्रतीत होता है, क्योंकि संभावित आय लाभ को वायदा विकल्पों की कम मात्रा से संतुलित किया जा सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि उच्च लेन-देन लागत से लेन-देन की मात्रा घटने, अल्पकालिक गति कमजोर होने और सक्रिय बाजार प्रतिभागियों के लिए लाभप्रदता कम हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी अनुसंधान प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि इक्विटी एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि से अल्पकालिक बाजार में असुविधा उत्पन्न हो सकती है। पुनर्खरीद (बायबैक) को पूंजीगत लाभ के रूप में मानने से एक सार्थक क्षतिपूर्ति मिलती है और दीर्घकालिक निवेशक विश्वास मजबूत होता है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने कहा कि बजट सट्टेबाजी पर रोक के लिए वायदा और विकल्प पर उच्च एसटीटी जैसे सुनियोजित उपायों से वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ बनाता है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा कि एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन-देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बाजार में डेरिवेटिव लेन-देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।

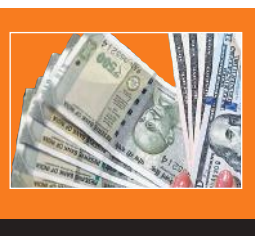

यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट -2026

● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायतित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी।

बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिली। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज़ इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कायाकल्प
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026-27) : 2.69 लाख करोड़ (2025-26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण : 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायतित योजनाएं : 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से : 10,000-12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि : 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026-27) : लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025-26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों की इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।

हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।

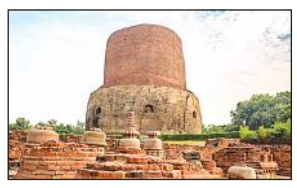

पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी से जुड़े कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आंका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी- इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इनपुट्स सस्ते होने से घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर
- एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इन प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत-विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि-तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी स्किल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य

अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक

अमृत विचार : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है

विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई-स्पीड रेल, आयुष, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

समझ से बाहर है बजट : अखिलेश

अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट-2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।

विश्लेषण बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

प्रो. अजय द्विवेदी
पूर्व डीन, प्रबंधन संकाय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मनःस्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य।

हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग कर राहत की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के ठोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बड़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसंरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसंरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की ठोस जमीन तैयार करती है।

उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसंरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसंरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।

मायावती ने बजट पर उठाए सवाल

अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।

बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय

अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बजट सवालों से भागने वाला बजट है और सरकार को अब देश की जनता को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बजट में बेरोज़गारी पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल

अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा।

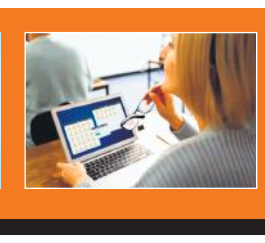

खेल विकास से सधेगी युवा शक्ति

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, खेलो इंडिया मिशन की शुरूआत

नई दिल्ली, एंजेंसी

यूनियन बजट 2026-27 भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोज़गार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीट के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहाः केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2025-26 3,346 करोड़

वर्ष 2026-27 4,479.88 करोड़

- 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न
- स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये

बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।

बैंकों के लिए उच्चस्तरीय समिति की हुई घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी

- बजट में इस प्रस्ताव से होगा बही खाता सुधार, बैंकों की गांवों की ओर पहुंच और तेजी से बढ़ेगी
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की हो सकेगी व्यापक समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के लिए तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत बही-खाते, लाभप्रदता के ऐतिहासिक उच्चस्तर, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता और देश के 98 प्रतिशत से अधिक गांवों को शामिल करने वाली पहुंच से लैस है।

उन्होंने आगे कहा, हम इस मोड़ पर इस क्षेत्र की सुधार आधारित वृद्धि जारी रखने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण देते हुए कहा, मैं वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के साथ जोड़ने के लिए ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति'' स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नजरिये को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी में पैमाना हासिल करने और दक्षता में सुधार करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, मैं भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से देश के बैंकिंग क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा।

बजट प्रतिक्रिया

वृद्धि, समावेशन का संयोजन वाला साहसिक बजट: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। मित्तल ने इसे विकास और समावेश को संयोजित करने वाला एक साहसिक बजट बताया और कहा कि कौशल विकास पर जोर के साथ विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में लगातार निवेश समय पर किया गया कदम है, जो घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात की जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। मित्तल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उपाय, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देना, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा।

यह बजट झुनझुना है दिखता है पर बजता नहीं : प्रमोद तिवारी

लखनऊ, एजेंसी। राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद प्रमोद तिवारी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ''मोना'' ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह "झुनझुने" की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन बजता नहीं। उन्होंने इसे किसान, बेरोजगार युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्योगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बजट से देश की जनता निराश हुई है। उनका दावा है कि बजट के बाद बाजार में गिरावट इसका संकेत है। नेता ने कहा कि पिछले एक वर्ष से पूंजी निवेश ठहरा हुआ है और न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न ही स्वदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में 78,086 करोड़ रुपये और शुद्ध कर संग्रह में 1,62,748 करोड़ रुपये की कमी आर्थिक सुस्ती का संकेत है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में बजटीय कटौती की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए कोई ठोस नई योजना या अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है और यह बजट केवल नारों तक सीमित है।

भारत बनेगा एआई में सबसे बड़ा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

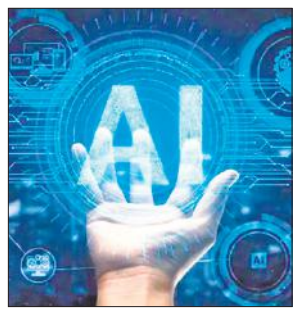

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत का एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों, सामग्री का घरेलू विनिर्माण और डिज़ाइन और प्रतिभा पारिस्थितकी तंत्र को मज़बूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मज़बूत समर्थन शामिल है-जिसे 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है-जो भारत को वैश्विक एआई हब के तौर पर स्थापित करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई और तकनीक को लेकर बजट में मिले प्रोत्साहन से देश में एआई -संबंधित बुनियादी ढांचे, डेटा-सेंटर, जीपीयू (ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्षमता और शोध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीति के साथ एक वास्तविक और व्यावहारिक एआई विकास मॉडल तैयार कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा इंजन है, और भारत की रणनीति इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार एआई का उपयोग, स्किलिंग, रिसर्च और निवेश को समान रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा, स्टार्टअप्स तथा उद्योग सभी इस तकनीक का लाभ उठा सकें।

पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि परिवर्तनों का उद्देश्य कामकाज को आसान बनाना है।

रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

- राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर-मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगे और इनके आसपास नए रियल एस्टेट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भरोसेमंद, निवेश-अनुकूल और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करता है, जो भारत के शहरी और आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।

म्यूचुअल फंड आय से जुड़े ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी। आम बजट 2026-27 के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। साथ ही, एक तय सीमा तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है।

यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। अब अगर निवेशक कर्ज लेकर निवेश करते हैं, तो उनके ऋण के ब्याज जैसे खर्चों को लाभांश या म्यूचुअल फंड आय से घटाया नहीं जाएगा। इससे ऐसी आय पर कर योग्य राशि प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी।

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय के मामले में मिलने वाली कटौतियों से संबंधित है।

विदेश में रहने वालों को निवेश की होगी अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

पीआरओआई निवेश

- भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा। साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है।

बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

सुधार बजट में प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 299 करोड़ खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी

देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

रविवार को पेश बजट के अनुसार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, 120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी ''मिशन कर्मयोगी'' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित की गई है। मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है। बजट दस्तावेज में कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा गया कि 120.8 करोड़ रुपये के प्रावधान में दिल्ली स्थित आईएसटीएम, मसूरी स्थित एलबीएसएनएए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से संबंधित स्थापना व्यय शामिल हैं। ये संगठन सचिवालय के सभी स्तरों तथा श्रेणियों के कर्मचारियों को नवीनतम नियमों एवं विनियमों और योग्यताओं से पर्याप्त रूप से अवगत कराने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम तथा मिड-करियर (कामकाज के दौरान) प्रशिक्षण सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस आवंटन में घरेलू या विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क भी शामिल होगा।

बजट दस्तावेज में कहा गया कि 52.2 करोड़ रुपये के आवंटन में सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। इसको आगामी वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी व्यय को 166.42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज में कहा गया कि इसमें सीएटी की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बजट समावेशी, वृद्धि और रोजगार बढ़ाने वालाः महेंद्र देव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस महेंद्र देव ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 समावेशी है और वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट कारोबारी सुगमता के साथ ही रहन-सहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। देव ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अगला कदम है। यह वृद्धि, समावेश और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट, और कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

दुर्घटना दावे से मिला हर्जाना अब आयकर से मुक्त होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

- कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ
- एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है।

दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हादसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को छूट दी जाएगी।

यह संशोधन एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा उसके बाद के कर वर्षों के संबंध में लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

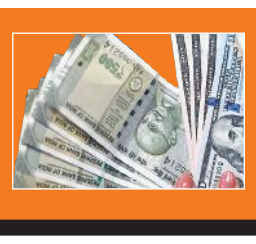

बजट न्यूज

निगम सभागार में देखा बजट का लाइव प्रसारण

हल्द्वानी: नगर निगम सभागार में मेयर गजराज बिष्ट सहित अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय बजट सत्र का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान दर्जा राज्यमंत्री नवीन वर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट में सर्वांगीण विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई बातें शामिल हैं। साथ ही आयकर नियमों में सरलीकरण के नियमों को 1 अप्रैल से लागू करने की बात भी रखी। कहा कि बजट की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज से 10 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष भाजपा प्रताप सिंह बिष्ट, विधायक लालकुआं मोहन सिंह बिष्ट, जिला महामंत्री विनीत अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री भाजयुमो दीपेंद्र कोश्यारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद गोयल, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल आदि रहे।

केंद्रीय बजट उत्तराखंड के लिए निराशाजनक

नैनीताल: केंद्रीय बजट को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव त्रिभुवन फर्त्याल ने उत्तराखंड के प्रति सौतेले व्यवहार बताया है। कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए निराशाजनक है। फर्त्याल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य की जनता को इस बजट से विशेष उम्मीदें थीं, लेकिन अधिकांश अपेक्षाएं अधूरी रहीं। प्रदेश की बहुप्रतीक्षित मांग ग्रीन बोनस को बजट में कोई स्थान नहीं मिला। सीमांत काश्तकारों की आय वृद्धि के लिए भी बजट में कोई ठोस पहल नहीं है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा को लेकर भी बजट में कोई स्पष्ट नीति या व्यवस्था नहीं की गई है। पर्यटन पर परोक्ष रूप से आधारित उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी बजट में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। रानीखेत, नैनीताल और मसूरी जैसे प्रमुख पर्वतीय पर्यटन नगरों में पार्किंग व जाम के समाधान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष पैकेज की घोषणा न होने से जनता ठगा महसूस कर रही है।

नगर निगम सभागार में बड़े पर्दे पर बजट देखते दर्जा मंत्री नवीन वर्मा, लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट व अन्य।

मोबाइल पर बजट देखते कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत व अन्य। ● अमृत विचार

माउंटेन ट्रेल: दुर्गम पहाड़ों में बहेगी विकास की बयार

नये बजट के प्रावधानों से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ेगा पर्यटन उद्योग, गाइडों को प्रशिक्षण देकर पलायन रोकने का होगा प्रयास

नरेन्द्र देव सिंह, हल्द्वानी

अमृत विचार: उत्तराखंड में पहाड़ों में ट्रेकिंग और हाइकिंग करने का पर्यटन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कई अब इस बार के केंद्रीय बजट में पहाड़ों में माउंटेन ट्रेल बनाने की बात हुई है। साथ ही 10 हजार गाइडों को प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की गई। हिमालयी राज्यों को दी गई सौगात में उत्तराखंड में शामिल है। राज्य के लिए यह घोषणा काफी लाभ पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। पहाड़ों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने से पलायन जैसी विकराल समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

साथ ही सरकार होमस्टे योजना पर भी काम कर रही है। राज्य में 690 होम स्टे पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा नैनीताल जिले में 164, पौड़ी जिले में 99, अल्मोड़ा जिले में 78, चमोली जिले में 66, टिहरी जिले में 65 और उत्तरकाशी जिले में 64 होमस्टे हैं। ट्रेकिंग और हाइकिंग की बात करें यहां पहले से ही कई ट्रेकिंग रूट हैं। नैनीताल, मसूरी, लैंसडॉन, रानीखेत जैसे आसान पहुंचे वाले हिल स्टेशनों के अलावा पर्यटक ट्रेकिंग करना भी पसंद करते हैं।

ट्रेकिंग करने के बाद जो स्थल मिलते हैं वह काफी शांत और दर्शनीय स्थल होते हैं। प्रसद्धि ट्रेकिंग स्थलों में सुविधाओं का विकास करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को काफी बल मिलेगा। केंद्र सरकार ने बजट में यह भी कहा है कि इन स्थानों का विकास करने के साथ ही यहां के पर्यावरण और मूल सौंदर्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

राज्य में मशहूर ट्रेकिंग स्थल: आदि कैलाश, पिंडारी ग्लेशियर, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, भविष्य बद्री मंदिर, केदारकांठा, फूलों की घाटी, छिपला केदार ट्रेक, दरमाघाटी, दयारा बुग्याल, गोमुख, गिदारा बुग्याल, कफनी ग्लेशियर, कागभुसंडी ताल, कालिंदी खाल ट्रेक, कनारी खाल ट्रेक, खोलिया टॉप, मसरताल झील, सुंदरढूंगा ग्लेशियर।

बजट में पर्यटन का योगदान कम

हल्द्वानी: अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड के अनुसार साल 2005-06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.73 प्रतिशत था जो साल 2023-24 में घटकर 0.38 प्रतिशत हो गया है। जीएसडीपी में पर्यटन विभाग का योगदान साल 2005-06 में 0.19 प्रतिशत था जो साल 2023-24 में घटकर 0.09 प्रतिशत है। यह पर्यटन राज्य के लिए चिंताजनक की स्थिति है।

माउंटेन ट्रेल के बारे में जानें

हल्द्वानी: माउंटेन ट्रेल पहाड़ों में संकरा और रास्ता होता है जिसका इस्तेमाल हाइकिंग, ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग और हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाता है। विकसित देशों के हिल स्टेशनों पर ऐसे माउंटेन ट्रेल बनाए जाते हैं। विकसित देशों में यहां काफी सुविधाएं भी दी गई हैं। सोशल मीडिया कल्चर ने इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया है।

नए ट्रैकिंग रूट व होम स्टे का हो सकेगा विस्तार

नैनीताल: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड के पर्यटन को बजट में शामिल किए जाने से नैनीताल ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में ट्रेकिंग और हाइकिंग के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी में सुधार आएगा। यह घोषणा वास्तव में सराहनीय है। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म का आकर्षण दिनों दिन बढ़ रहा है। ट्रैकिंग के लिए विदेशी सैलानी भी यहां आना चाहते हैं। जिसके चलते नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां अनेकों उच्च स्थान हैं, जो पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर हैं। जिन्हें विकसित करने के लिए बजट मिल पाएगा तो निश्चित ही कई अन्य दूरस्थ ग्रामीण स्थान पर्यटन में तब्दील हो जाएंगे। इकोलॉजिकल रूप विकसित किए जाने से यहां के पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। अभी भी ट्रैकिंग को लेकर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां क्षमता से अधिक सैलानी पहुंचते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लिहाजा इन्हें सस्टेनेबल किया जाना बेहद जरूरी है। इस बजट से लोकल कम्युनिटी की गाइडिंग की जा सकेंगी यानी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे ग्रामीणों का आर्थिक आधार बनेगा।

बजट देखने को टीवी व मोबाइल से चिपके रहे लोग

हल्द्वानी: आम बजट 2026 की प्रस्तुति शुरू होते ही देशभर के साथ-साथ हल्द्वानी में भी लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर टिक गईं। शनिवार को जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण देना शुरू किया, वैसे ही शहर के घरों, दुकानों, कार्यालयों और चाय की दुकानों में बजट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। डिजिटल युग का असर इस बार साफ नजर आया। जहां पहले लोग बजट सुनने के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते थे, वहीं इस बार बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन के जरिए लाइव प्रसारण देखते और सुनते दिखे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज ऐप्स पर भी बजट से जुड़ी हर बड़ी घोषणा को लोग तुरंत फॉलो करते नजर आए। बजट को लेकर केवल व्यापारी या नौकरीपेशा ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों से लेकर नवयुवाओं तक में खास दिलचस्पी देखी गई। कई लोगों ने साथ बैठकर बजट भाषण सुना और अपनी राय भी रखी।

बजट पर बोले

बजट स्वस्थ भारत की दिशा में ऐतिहासिक है, कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटने से इलाज सस्ता होगा और बायोफार्मा योजना से व्यापार व आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। देवभूमि के लिए आयुर्वेद एम्स की सौगात अत्यंत सराहनीय है। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर का विस्तार हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर, यह चिकित्सा सेवाओं को सस्ता, सुलभ और आधुनिक बनाने वाला एक जन-हितैषी बजट है। -**यमुना प्रसाद जोशी** प्रदेश सह संयोजक, चिकित्सा प्रकोष्ठ

केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है, जो गरीब, किसान, युवा और महिलाओं समेत हर वर्ग के उत्थान को समर्पित है। कृषि आधुनिकीकरण और कौशल विकास की घोषणाएं आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेंगी। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का एक ठोस रोडमैप है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र को सशक्त और खुशहाल बनाने का संकल्प पूरा करता है। -**विकास भगत**, भाजपा प्रवक्ता

बजट में कैंसर व शुगर की दवाओं पर राहत और पर्यटन-इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर स्वागत योग्य है, लेकिन मध्यम वर्ग और व्यापारियों की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी खलती है। रेल सुरक्षा, वेटिंग लिस्ट और जीएसटी सरलीकरण जैसे अहम मुद्दों पर ठोस पहल की कमी है, साथ ही होम व एजुकेशन लोन पर सब्सिडी की दरकार थी। अघोषित आय पर टैक्स का प्रावधान बेहतर है, वहीं आम आदमी को महंगाई से राहत और डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। - **डॉ. प्रमोद अग्रवाल 'गोल्डी'** प्रदेश प्रवक्ता, व्यापार मंडल, हल्द्वानी

उत्तराखंड एक आपदाग्रस्त व विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला हिमालयी राज्य है। संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड को बजट में एक विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी, जिससे यहां के सुदूर पर्वतीय जिलों में बुनियादी ढांचे का ठोस विकास हो सके। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन पर भी रोक लगती। राज्य को जब तक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, पर्वतीय विकास का सपना साकार नहीं होगा। -**ललित कर्नाटक**, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स के विकास की घोषणा को सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तराखंड को मिलने वाले हिस्से को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्य की जनता को पर्यटन क्षेत्र से विशेष उम्मीदें थीं, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार का सबसे बड़ा साधन पर्यटन ही है। इसके बावजूद इस क्षेत्र को अपेक्षित वित्तीय समर्थन नहीं मिल पाया। -**दिग्विजय सिंह बिष्ट**, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, नैनीताल

सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर पर दिए गए फोकस को रोजगार सृजन की दृष्टि से सराहनीय बताया, लेकिन मध्यम वर्ग को आयकर में कोई बड़ी राहत न मिलने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान पर्यटन के नाम पर केवल चारधाम यात्रा तक सीमित दिखाई देता है, जबकि नैनीताल, मसूरी जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की उपेक्षा की जा रही है। -**संजय नागपाल**, स्थानीय कारोबारी, नैनीताल

आयकर में छूट, कृषि क्षेत्र और परिवहन से जुड़े प्रावधान अच्छे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अच्छा बजट दिया गया है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए आवश्यक है। अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना जरूरी है। कुमाऊं क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं को सुगम बनाना जरूरी है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। - **अमनदीप सिंह आनंद** महासचिव, तल्लीताल व्यापार मंडल

बजट विकासोन्मुखी है। हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल सेक्टर और महिलाओं को राहत दी गई है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन सेवाओं की मांग की जा रही है, जिस पर बजट में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। राज्य को विशेष पैकेज की दरकार है। - **पुनीत टंडन**, अध्यक्ष, मां नयना देवी व्यापार मंडल नैनीताल

हल्द्वानी के एक शो रूम में टीवी पर बजट को देखते लोग। ● अमृत विचार

विकसित भारत का सर्वस्पर्शी बजट: मनोज भट्ट

संवाददाता, भीमताल

अमृत विचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। इसमें वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ आने वाले दशकों की सोच का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह बात भाजपा के जिला मंत्री मनोज भट्ट ने एक प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, युवा, नारी शक्ति और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हर वर्ग के उत्थान की ठोस योजनाएं शामिल हैं। रक्षा, कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान न केवल देश की आर्थिक गति को तेज करेंगे, बल्कि सामाजिक संतुलन और समावेशी विकास को भी मजबूती प्रदान करेंगे। विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग ट्रेल्स के विकास की घोषणा को उन्होंने दूरदर्शी पहल बताया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका सुदृढ़ होगी, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे।

बजट देश के विकास का संकल्प होता है, जिसमें अच्छाइयां और कुछ कमियां दोनों होती हैं। 2026-27 के बजट में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार आधारित वृद्धि को गति देना प्रमुख उद्देश्य है। -**डॉ. हेमंत जोशी**, शिक्षक, ओखलकांडा

इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दिए जाने से कर्मचारियों में निराशा है। टैक्स जमा करने की अवधि को तीन महीने बढ़ाना मात्र एक औपचारिक राहत साबित होती है। - **असलम अली**, जिलाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद नैनीताल

बजट पर प्रतिक्रिया

बजट उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बर्ड वॉचिंग, इको-टूरिज्म, योग और आयुष, विशेषकर औषधीय और जड़ी-बूटी उत्पादन, राज्य की भौगोलिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुकूल हैं, जो रोजगार सृजन में सहायक होंगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा हुआ केंद्रीय व्यय राज्य की कनेक्टिविटी और निवेश क्षमता को बढ़ाएगा। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास जैसी पहल उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाएगी। -**डॉ. हिमानी**, असि. प्रो. अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज

बजट से प्रदेश में पर्यटन, योग और आयुष-आधारित मेडिकल टूरिज्म से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय फाइबर योजना और रेशम, जूट और हस्तशिल्प से जुड़ी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के मौके पैदा करेंगे। उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास खोलने की योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। -**डॉ. रितुराज पंत**, असि. प्रो., वाणिज्य विभाग, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज

देश भर के पंद्रह हजार स्कूलों में एवीजीसी प्रयोगशाला बनाने का निर्णय, पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का निर्माण, शिक्षा से रोजगार व उद्यम का प्रस्ताव, छात्राओं के लिए नए छात्रावासों का निर्माण सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, स्टेम एजुकेशन, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर टैक्स की कमी किया जाना सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। -**डॉ. प्रवींद्र रौतेला**, प्रधानाचार्य, सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल

इनकम टैक्स में कर्मचारियों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट ने निराश किया। सरकारी फैसलों से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। महंगाई के दौर में कर्मचारियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर कर्मचारी वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। -**कमल पपनै**, प्रदेश अध्यक्ष उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन, उत्तराखंड परिवहन निगम

बजट में छोटे और मध्यम व्यापारियों को केवल निराशा हाथ लगी है। व्यापारियों के लिए कर, ऋण या लाइसेंसिंग में कोई ठोस राहत नहीं दी गई। जीएसटी सरलीकरण और अनुपालन बोझ कम करने पर चुप्पी रही। महंगाई और बढ़ती लागत से जूझ रहे व्यापारी को कोई सहारा नहीं मिला। स्थानीय उद्योग और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन नदारद है। यह बजट व्यापारी वर्ग की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। -**वीरेंद्र गुप्ता**, प्रदेश प्रभारी, प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल

मोटर वाहन दुर्घटना मुआवज़ा पर कोई आयकर नहीं लगेगा। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर घटाई गई। शिक्षा व चिकित्सा के लिए विदेश भेजी गई राशि पर टीसीएस कम किया गया है। धारा 194सी में मैनपावर सप्लाई को विशेष रूप से शामिल किया गया। शेयर से होने वाली आय पर फॉर्म 15जी/15एच की सुविधा लागू। बिजनेस और ट्रस्ट के आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक की गई है। डिमांड पर स्टे के लिए 10 प्रतिशत पेनल्टी निर्धारित की गई है और गलत रिपोर्टिंग पर पेनल्टी से छूट का प्रावधान रखा गया है। -**संजय पांडे**, एडवोकेट

बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में राहत देना सराहनीय कदम है। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और शुगर की दवाओं को सस्ता किया गया है। इससे आम लोगों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। विदेशों में शिक्षा के लिए टीसीएम को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सहायक है। मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक से लोन लेकर भेजी गई राशि पर विदेश में पढ़ाई के लिए टीसीएस से पूरी तरह छूट दी गई है। कुल मिलाकर यह बजट जनहित और भविष्य निर्माण को मजबूत करता है। -**हृदयेश गुप्ता**, एडवोकेट

बजट में डिफेंस बजट में बढ़ोतरी समय की आवश्यकता के अनुरूप है। इससे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूती मिलेगी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम को आयकर से छूट देना सराहनीय कदम है। यह पीड़ितों और उनके परिवारों को वास्तविक राहत प्रदान करेगा। आयकर मामलों में सजा की बजाय पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। इससे करदाताओं पर अनावश्यक कानूनी दबाव कम होगा। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का स्पष्ट प्रयास नजर आता है। कुल मिलाकर यह बजट व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण दर्शाता है। -**सुमित गुप्ता**, अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन हल्द्वानी

केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे आम करदाताओं को राहत नहीं मिली। इसके बावजूद, 1 अप्रैल से नए आयकर कानून के लागू होने की घोषणा कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में ईमानदार करदाताओं को सुविधा देने, अनावश्यक नोटिस, पेनल्टी और मुकदमों को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। कुल मिलाकर, आयकर के क्षेत्र में यह बजट अल्पकालिक की अपेक्षा दीर्घकालिक और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। - **मजहर अली अधिवक्ता**, टैक्स सलाहकार

शिक्षा बजट में युवाओं के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी। इससे शिक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हर जिले में छात्राओं के लिए एक हॉस्टल बनाकर उन्हें सशक्त किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया गया है। नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज नामक हाई-पावर समिति बनेगी। यह समिति एआई के प्रभाव, रोजगार, विकास की संभावनाओं पर काम करेगी। -**रवि शंकर शर्मा**, शिक्षाविद निदेशक अचीवर्स एकेडमी हल्द्वानी

बजट-2026 | आयकर कानून से जुड़े कई अहम संशोधनों का लाभ आम करदाताओं, व्यापारियों और निवेशकों को मिलेगा

किसी ने बजट को सराहा, किसी ने बताया निराशाजनक

संवाददाता, रामनगर

अमृत विचार: केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट को किसी ने संतुलित बताया, किसी ने सराहा तो किसी ने निराशास जनक बताया। टैक्स बार एसोसिएशन रामनगर अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे के अनुसार आयकर कानून से जुड़े कई अहम संशोधन लागू किए हैं, जिनका सीधा लाभ आम करदाताओं, व्यापारियों और निवेशकों को मिलेगा। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। अब सड़क दुर्घटनाओं में मिलने वाले मुआवज़े पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगाया जाएगा। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजी जाने वाली रकम पर टीसीएस की दर कम की गई है। धारा 194 सी में बड़ा संशोधन हुआ है। अब मैनपावर सप्लाई को विशेष रूप से धारा 194 सीके अंतर्गत शामिल किया गया है। शेयर बाजार से होने वाली आय पर अब फॉर्म 15 जी/15एच का लाभ लिया जा सकेगा। करदाताओं को राहत देते हुए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिजनेस एवं ट्रस्ट से जुड़े करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त होगी। विदेशी संपत्ति के खुलासे के लिए 6 माह की विशेष योजना लाई गई है, जिसमें एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गई है। सरकार ने पेनल्टी और असेसमेंट प्रक्रिया का युक्तिकरण किया है।

बजट 2026 पेश होने से ठीक पहले 1 फरवरी को ही एलपीजीगैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा सरकार ने सबको महंगाई का तोहफा दिया। कर्मचारी शिक्षकों की आस होती है कि बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न कर बजट ने निराश ही किया। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और 8वें पे कमीशन पर कोई घोषणा नहीं की गई। -**नवेंदु मठपाल**, प्रांतीय उपाध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संगठन

पर्यटन उद्योग देश को टैक्स के रूप में काफी राजस्व देता है साथ ही प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करता है। वर्तमान में उत्तराखंड का पर्यटन मौसम आपदा के अतिरिक्त कई अन्य कारणों से प्रभावित हुआ है। सरकार से अपेक्षा थी कि वह पर्यटन उद्यमियों को कर में राहत दे और राज्य की सड़क और रेल को सुधारे। पर्यटन को बढ़ावा देना स्वागत योग्य है मगर पर्यटन उद्यमियों को राहत दिया जाना समय का तकादा है। -**संजय छिम्वाल**, नेचर गाइड

बजट से न बहुत ज्यादा राहत मिली और न बहुत बोझ। आयकर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया जिसमें मिडल क्लास के लोगो में काफी उम्मीदें थी। देखा जाए तो मंहगाई के हिसाब से राहत कम लगी। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होगा बताया गया जोकि पहले से अधिक सरल होगा। जीएसटी दरों में भी कोई बड़ी कटौती नही की गई है। लेकिन सरलीकरण पर जोर दिया गया है। -**गौरव गोला**, सचिव, रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन

वर्तमान के बजट ने किसानो को निराश किया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि उपकरण से लेकर खाद व डीजल आदि में कोई भी महंगाई कम नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने बजट को लाकर दोबारा बजट पेश कर दिया है। सरकार द्वारा किसानों की दोगुनी आय करने का वादा साफतौर पर झूठा साबित हुआ। इस बजट से किसानों तथा आम आदमी पर महंगाई का बोझ और ज्यादा पड़ेगा। -**महेश चंद्र जोशी**, किसान सांवल्दे रामनगर

बजट दूरदर्शी, समावेशी और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला

अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को केंद्र में रखकर बजट किया पेश, भाजपा जिला कार्यालय में बजट की बारीकियों पर मंथन

रुद्रपुर के भाजपा कार्यालय में बजट कार्यक्रम को देखते विधायक व कार्यकर्ता। ● अमृत विचार

संवाददाता, रुद्रपुर

अमृत विचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 में 9वीं बार संसद में आम बजट पेश किया गया। इसको लेकर विधायक शिव अरोरा ने पार्टी कार्यालय पर बजट प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ बजट को सुना।

रविवार को बजट प्रस्तुतीकरण के बाद विधायक अरोरा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह बजट निर्णायक साबित होगा। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, युवा, महिला, किसान, वंचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुआ बनाया गया है। इसमें अंतिम पायदान पर बैठे गरीब को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाला यह बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को केंद्र में रखकर बजट पेश किया गया।

उन्होंने कहा कि इस बजट में राजकोषीय घाटा कम करने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। साथ ही नये इनकम टैक्स अधिनियम को लागू किया है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिसके बाद टैक्स के क्षेत्र में काफी सुधार जनता को देखने को मिलेंगे और देश के नागरिकों को इसका सीधा लाभ होगा। देश में 7 नये हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने, बायोफार्मा के लिये 10000 करोड़ का प्रावधान, कैंसर शुगर जैसी सात अन्य गंभीर बीमारियों के दवाई को सस्ता करना आम जनता को काफी राहत देने वाला होगा। साथ ही देश में 20 नये जलमार्ग बनाने की दिशा में काम होगा जिससे देश में जलमार्ग से व्यापार बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा रश्मि रस्तोगी, स्वाति शर्मा, रोशन अरोरा, प्रमोद मित्तल, धीरेंद्र मिश्रा, प्रीति धीर, राजेश बजाज, बिट्टू चौहान, रचित सिंह, विजय तोमर, जीतेंद्र संधू, सर्वेश मौर्य मौजूद रहे।

उत्तराखंड के विकास को मिलेगी नई गति

संवाददाता, काशीपुर

- उद्योगपतियों ने कहा, बजट अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण और सकारात्मक

अमृत विचार: देश के बजट को उद्योगपतियों ने अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण और सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि संतुलित एवं संवेदनशील बजट से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी।

पीएचडी चैंबर उत्तराखंड के को-चेयरमैन राजीव घई ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक संतुलित, संवेदनशील एवं दूरदर्शी बजट है, जो देश के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यटन को प्राथमिकता देते हुए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणाओं से उत्तराखंड को दीर्घकालीन लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि राज्य में प्राकृतिक वातावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बजट में

राजीव घई, को-चेयरमैन, पीएचडी चैंबर।

देवेंद्र अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, केवीएस।

मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोत्साहित करने की योजनाओं से उत्तराखंड के उद्योगपतियों एवं निवेशकों को बड़ा लाभ होगा। इससे राज्य में नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

लगभग 5.68 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस बजट से जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी, वहीं इससे जुड़ी सहायक इकाइयों एवं रोजगार के अवसरों का लाभ भी राज्यों को मिलेगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स प्रणाली को सरल बनाए जाने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी। बजट में कैपेक्स के माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में प्रस्तावित है, जिससे सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को मिलेगा। केवीएस फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बजट में एआई के महत्व को देखते हुए व्यवस्था की गई है। यह बजट अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण और सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त नए ट्रेनिंग सेंटर एवं स्किल डेवलपमेंट योजनाओं की घोषणा से उत्तराखंड के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह बजट लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक स्तर पर व्यापक लाभ होगा।

केंद्रीय बजट से कोई खुश तो कोई नाखुश

संवाददाता, रुद्रपुर

- किसी ने बजट को किसान, युवा, महिला वर्ग के लिए बताया लाभप्रद तो किसी ने निराशाजनक
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट पर रखी राय

अमृत विचार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2026-27 में 9वीं बार संसद में आम बजट पेश किया गया। इसमें वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। हालांकि इन घोषणाओं से कोई खुश नजर आया तो कोई नाखुश नजर आया। किसी बजट को किसान, युवा, महिला, वंचित वर्ग के लिए लाभप्रद बताया तो किसी ने कहा कि बजट में आमजन के लिए कोई खास नहीं है। बजट को लेकर जब लोगों से चर्चा की तो उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी।

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान, युवा, महिला, वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर बजट जारी किया है। इस बजट का सीधा लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड में विकास की नई संभावनाओं के अवसर पैदा होंगे।
> **-शिव अरोरा, विधायक,** रुद्रपुर विधानसभा

> यह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने, किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को गति देने और व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाला है। इस दूरदर्शी बजट नए भारत के निर्माण होगा। बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और देश की खुशहाली के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ब्लूप्रिंट है।
> **-विकास शर्मा,** महापौर, नगर निगम

> केंद्रीय बजट में शुगर और कैंसर की दवा सात अन्य गंभीर बीमारियों के दवाई को सस्ता करने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। कारण ये बीमारी जीवन भर चलती है। अगर कैंसर की शुरुआती चरण से लोगों को दवाएं सस्ती मिलेंगी तो आम जनता को काफी राहत मिलेगी।
> **-डॉ .केके अग्रवाल,** सीएमओ,यूएस नगर

> बजट में व्यापारी, किसान, गरीब, छात्रों, बेरोजगारों सहित सभी तबके को कुछ नहीं मिला है। यह बजट किसी को भी समझ नहीं आया है। बजट में महंगाई को रोकने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ फंड दिखाया गया है, मगर नजर नहीं आया।
> **-संजय जुनेजा,** अध्यक्ष व्यापार मंडल

भाजपाइयों ने 'विकसित भारत' का बजट बताया

संवाददाता, टनकपुर

डॉ . दिनेश कुमार गुप्ता, अर्थशास्त्री।

आनंद सिंह मेहरा, प्रदेश सचिव, कांग्रेस

अमृत विचार: रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर भाजपा ने चंपावत के गांधी चौक और टनकपुर के तुलसीराम चौराहे पर बड़ी स्क्रीन लगाकर आम जनता को बजट का सीधा प्रसारण दिखाया।

भाजपा नेताओं ने इसे 'विकसित भारत' का बजट बताते हुए कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी के अर्थशास्त्री डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 समग्र एवं समावेशी विकास की एक स्पष्ट और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इन तीन मूल विज़नों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने, युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज़ुअल इफेक्ट्स, एनीमेशन, गेमिंग और रचनात्मक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-विस्तार कार्यक्रम, करियर पाथवे योजनाएँ तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से युवाओं के लिए नए और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों के उन्नयन, ट्रॉमा केयर सेंटरों के विस्तार, एक लाख विशेषज्ञों और डेढ़ लाख देखभाल कर्मियों के प्रशिक्षण, आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी तथा एम्स स्तर के तीन नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना को उन्होंने जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और महिला सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, हथकरघा उद्योग और 'एक जिला–एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूती देता है। अवसंरचना विकास के अंतर्गत नए जलमार्गों और तीव्रगामी रेल गलियारों की घोषणा से देश की आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को गति मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को कर स्लैब में छूट की अपेक्षा थी, जिससे उनकी वास्तविक आय और क्रय शक्ति में और वृद्धि हो सकती थी। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आनंद सिंह मेहरा ने बजट को उत्तराखंड जैसे हिमालयी, सीमांत और आपदा-संवेदनशील राज्य के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट से पलायन कर रहे बेरोजगार युवाओं को भी कोई ठोस राहत नहीं मिली है।

- सुबह से ही आम बजट को लेकर लोगों में दिखी उत्सुकता
- बजट पर विभिन्न वर्गों के लोगों ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया

संवाददाता, अल्मोड़ा

अमृत विचार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को संसद में पेश किया गया बजट अल्मोड़ा में आम लोगों की कसौटी पर कहीं खरा उतरा, तो कई लोग उम्मीद के मुताबिक बजट में प्रावधान नहीं होने से काफी निराश भी दिखे।

अल्मोड़ा में आम बजट को लेकर सुबह से लोगों में उत्सुकता देखी गई। बजट को लेकर कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने बजट को आम जनता की उम्मीदों से जुड़ा बताते हुए विकास परक बताया, तो वहीं विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक घोषित करते हुए आम जनता की उम्मीदों से खिलवाड़ बताया। हालांकि इस बार बजट में सरकार की ओर से जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कमी समेत सोलर से जुड़ी चीजों की दरों को कम कर राहत दी है।

दवाओं और सोलर से जुड़ी चीजों की कीमतें कम: कपड़ा, कैंसर की 17 दवाएं समेत सोलर से जुड़ी जीजें कम होने से मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक तरफ जहां जीवन रक्षक दवाएं इन दिनों आसमान छू रही है। वहीं, बजट में इन दवाओं का शुल्क कम कर लोगों को राहत दी है। जिससे गरीब और मध्यवर्गीय अपना उपचार करा सकेंगे।

अल्मोड़ा में एक घर में टीवी पर बजट देखता परिवार। ● अमृत विचार

टीवी के सामने जुटे रहे लोग

अल्मोड़ा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी। ऐसे में लोग हर काम छोड़कर बजट देखने के लिये सुबह से ही टीवी के सामने बैठे रहे। वहीं बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों के सामने भी बजट देखने को लोगों की भीड़ जमा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने टीवी के अलावा मोबाइल से बजट की जानकारी ली।

बजट में महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं

आम बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी कई गृहिणियों ने कहा कि उन्हें निराशा मिली है, जबकि कई ने इसे सराहा। महिलाओं का कहना है महंगाई को रोकने के लिए भी सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिये बजट में कुछ भी खास नहीं है। कहा कि आम परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या किचन के बजट व निजी विद्यालयों की महंगी फीस है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि निजी विद्यालयों की फीस कम करने के लिए सरकार फैसला लेगी, लेकिन निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया।

> केंद्र सरकार का यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वित्त मंत्री से बजट को लेकर बहुत उम्मीदें जताई थी और उन्होंने सभी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया है।
> **-महेश नयाल,** जिलाध्यक्ष भाजपा।

> बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस राहत देने की बजाय केवल आंकड़ों का खेल खेला है।
> **-भूपेंद्र सिंह भोज,** जिलाध्यक्ष कांग्रेस।

> महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बजट से महंगाई कम होने की उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने बजट में गृहिणियों को राहत देने के लिए ठोस प्रयास नहीं किये हैं।
> **- प्रीति कनवाल,** गृहिणी, अल्मोड़ा।

> जीएसटी के स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना थोड़ा व्यापारियों के लिए निराशजनक है। आम व्यापारी की नजर से सोचा जाए तो व्यापारियों को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि बजट में उद्योग जगत को टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है।
> **-मनोज सिंह पवार,** जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल अल्मोड़ा।

> टैक्स कानूनों को सरल बनाने, जीएसटी और इनकम टैक्स में बढ़ती जटिलताओं और अनावश्यक नोटिस की समस्या पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। बजट का फोकस करदाताओं को सुविधा देने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर अधिक दिखाई देता है।
> **-वैभव पांडे,** अधिवक्ता, अल्मोड़ा।

> बजट देश के विकास की बात तो करता है, लेकिन आम जनमानस की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। जनता को उम्मीद थी कि इस बार बजट उनके रोजमर्रा के संघर्ष को कम करेगा, महंगाई से राहत देगा, आय बढ़ाएगा और टैक्स का बोझ घटाएगा। लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता।
> **-डॉ . गणेश उपाध्याय,** प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

> यह बजट रोजगार के अवसरों और मेहनतकश वर्ग के आय में वृद्धि नहीं करता है। मजदूरों, कृषि और किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता की उपेक्षा बजट में की गयी है। छोटे व सीमांत किसानों को कॉरपोरेट वर्चस्व से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। **- ललित मटियाली,** जिला सचिव, भाकपा (माले)

> यह बजट पहली नजर में सार्वजनिक और सभी के लिए लाभदायक नजर नहीं आता है। हर बार की तरह वन नेशन वन टैक्स की उम्मीद सैलरीड क्लास को थी। जिन पर इनकम टैक्स के अलावा और कई टैक्स के बोझ तले अभी और जीना होगा।
> **-श्रीकर सिन्हा, प्रेसिडेंट,** सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी, पंतनगर

> महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को जिस ठोस राहत की अपेक्षा थी, वह स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को यदि प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो इसका असर कार्यक्षमता और मनोबल दोनों पर पड़ेगा।
> **-रवि शंकर गुसाईं,** अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊ मंडल।

> इनकम टैक्स में आय से अधिक संपत्ति पर पहले सजा का प्रावधान था, लेकिन अब 30 फीसदी टैक्स देकर छूट सकते हैं। मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर में कोई बड़ी राहत नहीं मिली। अब नौकरीपेशा कर्मी रिवाईस रिटर्न 31 जुलाई तक भर सकते हैं। पहले यह तिथि 31 मार्च होती थी।
> **-भूपेश दुम्का,** पूर्व अध्यक्ष, जिला टैक्स बार एसोसिएशन

> अगर किसानों के लिए गेहूं, धान, गन्ना में एमएसपी बढ़ाने की बात होती तो यह किसान हित में होता। 80 फीसदी किसानों को एमएसपी का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों को समूह के माध्यम से कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। अगर किसानों को व्यक्ति रूप से 50 फीसदी सब्सिडी में मिलते तो यह किसान हित में होता। **-विक्रम जीत सिंह विर्क,** किसान नेता

बजट

काशीपुर में बजट को लेकर लोगों की रही मिली–जुली प्रतिक्रिया

जीएसटी प्रणाली में कुछ खास नहीं होने से व्यापारियों में निराशा

संवाददाता, काशीपुर

अमृत विचार: केंद्र सरकार के बजट को लेकर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी ने बजट को अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिये अच्छा बताया तो किसी ने बजट से लगाई की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने की बात कही।

रविवार को पेश किये गये बजट पर लोगों ने कहा कि बजट ने जीएसटी, बेरोजगारी और महंगाई तीनों मोर्चों पर आम जनता को गहरी निराशा दी है। सरकार बड़े आंकड़ों की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। जीएसटी लागू हुए सात साल से अधिक हो चुके हैं, फिर भी यह व्यवस्था आज भी सरल नहीं बन पाई है। छोटे और मध्यम व्यापारियों को साल में 20 से ज्यादा रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं। महंगाई की स्थिति भी चिंताजनक है। खुदरा महंगाई दर लगभग 5 से 6 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ चुका है। बजट में महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण का कोई स्पष्ट उपाय नहीं दिखता।

> केंद्र द्वारा प्रस्तुत 2027 बजट पूरी तरह से फेलियर है। इस बजट में पिछड़ों, दलितों, वंचितों आदिवासियों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए के लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं रखा गया है। उत्तराखंड के लिए किसी भी नई ट्रेन योजना को घोषित न कर उत्तराखंड विरोधी सोच को दर्शाया है।
> **– अलका पाल, अध्यक्ष,** महानगर कांग्रेस कमेटी, काशीपुर

> केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में पेश किया गया बजट पूरी तरह से समावेशी है और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देश के विकास में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस बजट में किसानों, व्यापारियों, उद्योगी और युवाओं सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। और इस बजट में मोदी सरकार की देश के विकास के प्रति दूरदर्शी सोच झलकती है।
> **-दीपक बाली,** महापौर, नगर निगम

> बजट से किसानों और मजदूरों को कोई फायदा नहीं। सरकार को सोचना चाहिए कि देश के विकास का मार्ग किसान के खेतों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। किसान और मजदूर खुशहाल होगा, तभी देश में खुशहाली आएगी। कृषि में उपयोग होने वाली खाद एवं दवाइयां महंगी है। किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। केंद्र सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए।
> **-प्रेम सिंह सहोता,** प्रदेश उपाध्यक्ष, भाकियू

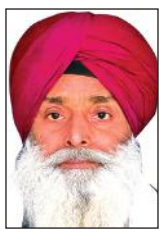

> केंद्र सरकार के बजट में रोजमर्रा की कुछ वस्तुएं सस्ती होने से व्यापारियों का निवेश कम होगा, साथ ही ग्राहकों का फायदा होगा। वहीं इस बजट से आम जनता को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन कुछ चीजों के रेट बढ़ने से संबंधित व्यापारियों पर बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सभी वर्गों का ध्यान रखे।
> **-हरिओम सिंह, अध्यक्ष,** व्यापार मंडल जसपुर।

> आयकर में छूट न देना, उचित नहीं है। कम से कम महंगाई दर के अनुसार तो हर वर्ष छूट बढ़नी चाहिए, मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए छूट न मिलने से उनकी क्रय शक्ति घट गई है। बजट से निराशा हाथ लगी है।
> **-डॉ . अमित अग्रवाल,** असिस्टेंट प्रोफेसर, कामर्स

> सामान्य किसानों के लिए बजट में सिर्फ इतना ही दिया है कि भारत विस्तार एआई टूल योजना से किसानों को सीधे मौसम एवं कृषि संबंधी नवीनतम जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा समुद्र के किनारे काजू नारियल के किसानों एवं मछुआरों को बढ़ावा देंगे।**-अरुण शर्मा,** प्रदेश अध्यक्ष, किसान विकास क्लब (उत्तराखंड)

> केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक अच्छा और सुव्यवस्थित बजट है। यह विकास को गति देने वाला बजट एवं प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है।
> **-त्रिलोक सिंह चीमा,** विधायक, काशीपुर।

रामनगर में बजट का सीधा प्रसारण देखते भाजपाई। ● अमृत विचार

भाजपाइयों ने सामूहिक रूप से देखा बजट का प्रसारण

रामनगर : भाजपा कार्यकर्ताओं ने खत्री सभा भवन सभागार में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान पार्टी नेताओं के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी और युवा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट सरकार के विकसित भारत संकल्प और गरीब कल्याण के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रम का अभिलेख होता है। इसलिए इसकी संपूर्ण जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, ताकि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का सही उत्तर दिया जा सके। कार्यक्रम में भगीरथ लाल चौधरी, गणेश रावत, जगमोहन बिष्ट, राकेश नैनवाल, इंदर रावत, मंडल अध्यक्ष बलदेव रावत, घनश्याम शर्मा, कपिल रावत, राकेश अग्रवाल, पीएस बिष्ट, डॉ . धनेश्वरी घिल्डियाल, भावना भट्ट, सीए शिवम अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन कांडपाल, मो . अदिल, विजयपाल रावत, गंगा राणा, इंदु ध्यानी आदि मौजूद रहे।

ब्रीफ न्यूज

अधेड़ की टैंकर ने कुचल कर मौत, मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी : घर के बाहर धूप सेंक रहे एक व्यक्ति की पानी के टैंकर से कुचलकर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में गोरापड़ाव अर्जुनपुर निवासी बसन्त कुमार ने लिखा है कि बीती 16 जनवरी को उनके पिता अम्बा राम अपने घर के बाहर धूप सेंक रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे पानी के टैंकर ने अम्बा राम को कुचल दिया। उन्हें डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यूओयू में अब 20 फरवरी तक होंगे प्रवेश

हल्द्वानी : उत्तराखंड मुक्त विवि ने शीतकालीन सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी है। अब इच्छुक शिक्षार्थी निर्धारित तिथि तक विवि में प्रवेश ले सकते हैं। कुलपति डॉ. नवीन चंद्र लोहनी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इस मौके का लाभ उठाते हुए अपने पसंदीदा विषय में समय रहते नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के लिए शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.uou.ac.in या onlineuou.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भारत बौद्धिक परीक्षा में 35 को दिए प्रमाण पत्र

हल्द्वानी : राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में रविवार को भारत बौद्धिक परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के बाद 35 प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाणपत्र दिए गए। प्राचार्य प्रो. आभा शर्मा और प्रभारी प्राचार्य डॉ. विजय कुमार बिष्ट ने बताया कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूक करने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में नोडल अधिकारी के रूप में डॉ. रश्मि पंत, डॉ. तनुजा बिष्ट, डॉ. नीता शाह, यशोधर नाथ रहे।

सीओ लालकुआं का एसपी विजिलेंस पद पर तबादला

हल्द्वानी : लालकुआं की सीओ रहीं एसपी दीपशिखा अग्रवाल का पदोन्नति के बाद एसपी विजिलेंस के पद पर तबादला हो गया है। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने एसपी दीपशिखा अग्रवाल को भावभीनी विदाई दी। दीपशिखा अक्टूबर 2024 से जिले में नियुक्ति के दौरान क्षेत्राधिकारी लालकुआं और भवाली के पद पर तैनात रहीं। विदाई समारोह में एसपी डॉ. जगदीश चन्द्रा, एसपी मनोज कत्याल, एसपी दूरसंचार रेवाधर मठपाल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, सीओ अमित कुमार सैनी, सीओ सुमित पांडे आदि मौजूद रहे।

कार्बेट की ढिकाला रेंज में पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया अनोखा दृश्य, आमतौर पर पेड़ पर नहीं चढ़ता है बाघ

दुर्लभः पेड़ पर चढ़ा जंगल का राजा बाघ, पर्यटक रोमांचित

संवाददाता, रामनगर

अमृत विचार: विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को कभी-कभी ऐसे दुर्लभ नजारे देखने को मिल जाते हैं, जो उनकी सफारी को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। इस बार ढिकाला रेंज में जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ पेड़ पर चढ़ा दिखाई दिया।

ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पेड़ पर चढ़कर अपने शिकार की तलाश कर रहा हो। सामान्यतः बाघों का पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। पेड़ों पर चढ़ने में आमतौर पर गुलदार अधिक दक्ष होते हैं। ऐसे में बाघ को पेड़ पर बैठे देख पर्यटकों में रोमांच का भर जाना स्वाभाविक था।

कार्बेट के ढिकाला रेनी रेंज में पेड़ पर दिखा बाघ।

ढिकाला पर्यटन जोन में सफारी कर रहे पर्यटकों की नजर जैसे ही साल के पेड़ पर बैठे बाघ पर पड़ी, वैसे ही गाड़ियों में बैठे लोग उत्साहित हो उठे। किसी ने कैमरा ऑन किया तो किसी ने मोबाइल, और देखते ही देखते यह दुर्लभ दृश्य वीडियो और तस्वीरों में कैद हो गया। पेड़ पर बैठा बाघ नीचे झांकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने शिकार पर नजर बनाए हुए हो। इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद करने वाले नेचर गाइड मोहम्मद नफीस ने बताया कि बाघों का पेड़ों पर चढ़ना अत्यंत दुर्लभ व्यवहार है।

> आमतौर पर गुलदार ही पेड़ों पर चढ़ते हैं। बाघ कभी-कभी कम ऊंचाई वाले पेड़ों पर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बाघ का पेड़ पर इस तरह दिखाई देना एक दुर्लभ संयोग कहा जा सकता है। -डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व

आमतौर पर तेंदुए इस तरह के दृश्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाघ का साल के पेड़ पर चढ़ना कार्बेट में कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि बाघ कुछ समय तक पेड़ पर रुका, इधर-उधर नजर दौड़ाता रहा और पर्यटकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहा। इसके बाद वह शांति से नीचे उतरा और घने जंगल की ओर ओझल हो गया।

कार्बेट टाइगर रिजर्व न केवल देश बल्कि दुनिया भर में बाघों की मजबूत उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाला हर पर्यटक बाघ के दर्शन की इच्छा रखता है, हालांकि यह हर किसी को नसीब नहीं होता।

इस अप्रत्याशित और दुर्लभ नजारे ने न केवल पर्यटकों को रोमांचित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वन्यजीव प्रेमियों के बीच खासा आकर्षण पैदा किया है।

टीपी नगर में ड्रेनेज की समस्या का हो समाधान

संवाददाता, हल्द्वानी

- ट्रांसपोर्टरों ने विधायक सुमित हृदयेश को बताईं समस्याएं

अमृत विचार: विधायक सुमित हृदयेश ने ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन से भेंट की। एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सबरवाल के कार्यालय में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया।

व्यापारियों ने वाहन पार्किंग, संचालन में आ रही कठिनाइयों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और ट्रांसपोर्ट नगर में लंबे समय से बनी गंभीर ड्रेनेज समस्या को प्रमुखता से विधायक के समक्ष रखा। बताया कि जलभराव एवं अव्यवस्थित नालियों के कारण आवागमन बाधित होता है, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विधायक सुमित हृदयेश ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर ड्रेनेज व अन्य समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनहित एवं व्यापार हित से जुड़े सभी मुद्दों का प्राथमिकतासे समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर खीमानंद शर्मा, इंदर भुटियानी, मंसूर खान, पंकज वोहरा, नफीस अहमद, चंद्रशेखर पांडेय, चंद्रशेखर भट्ट, शंकर भुटियानी, इमरान, संदीप महेश्वरी, लक्ष्मण नेगी, हरपाल सेठी, दया शर्मा आदि रहे।

तिब्बती मार्केट के अंडे खाकर नैनी झील में मारे थे छक्के

नैनीताल में खेले मैचों को याद किया भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने, दिल्ली नाइट्स टीम की कमान संभालेंगे

पवन सिंह कुंवर, हल्द्वानी

अमृत विचार: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज और बल्लेबाज प्रवीण कुमार सोमवार को हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल स्टेडियम की सुविधाओं का जायजा लिया, उन्होंने नैनीताल से जुड़े अपने पुराने दिनों को याद किया।

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रवीण कुमार काफी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि नैनीताल और हल्द्वानी उनके लिए नई जगह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहां से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। मैं बहुत पहले से यहां आता रहा हूं। मुझे आज भी वे दिन याद हैं जब हम नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान पर टूर्नामेंट खेलने आया करते थे। वहां तिब्बती मार्केट में अंडे खाना और झील के किनारे छक्के जड़ने की यादें आज भी मेरे दिल में ताजा हैं। प्रवीण कुमार कल यानी मंगलवार को फिर से क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे। गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले टी-20 मैच में वह दिल्ली नाइट्स टीम की कमान संभालेंगे। इस हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट में इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिससे खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।

गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार। ● अमृत विचार

अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पिच पर खेलते प्रवीण कुमार। ● अमृत विचार

पिच को लेकर जताई राय

स्टेडियम की पिच का निरीक्षण करने के बाद प्रवीण कुमार ने तकनीकी पक्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन पिच में अभी थोड़ी कमी नजर आ रही है। इसे पूरी तरह तैयार होने में अभी एक से दो दिन का समय और लगेगा। हालांकि, खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि कल होने वाले मुकाबले में चौकों-छक्कों की वैसी ही बरसात देखने को मिलेगी, जैसी प्रवीण कुमार कभी नैनी झील के किनारे किया करते थे।

मेरठ की मिट्टी में भविष्य के सितारे तराश रहे प्रवीण कुमार

पवन सिंह कुंवर, हल्द्वानी

अमृत विचार: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज, जिन्हें दुनिया स्विंग का जादूगर कहती है, प्रवीण कुमार आज भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चकाचौंध से दूर हों, लेकिन खेल के प्रति उनकी दीवानगी आज भी बरकरार है।

मेरठ के इस लाडले खिलाड़ी ने अब अपने गृह जनपद को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया है। प्रवीण यहां न केवल रह रहे हैं, बल्कि युवाओं की तकदीर संवारने के लिए खुद का क्रिकेट ग्राउंड तैयार कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। उभरते खिलाड़ियों से संवाद करते हुए प्रवीण कुमार ने सफलता का मूल मंत्र साझा किया।

उन्होंने कहा कि खेल हो या जीवन, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। टीम में चयन न होने पर खिलाड़ियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत जारी रखें और धैर्य बनाए रखें। अगर आज आपका चयन नहीं हुआ है, तो कल निश्चित रूप से होगा। शर्त यह है कि आप मैदान और मेहनत न छोड़ें।

क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलकर ही रहता है। कहा कि जो लोग निराश होकर मैदान छोड़ देते हैं वह असफलता के जिम्मेदार खुद होते हैं। प्रवीण कुमार ने बताया कि मेरठ के मैदानों पर 5 फरवरी से ऑल इंडिया टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। इस बड़े टूर्नामेंट के माध्यम से देश भर की छिपी हुई प्रतिभाओं को अपनी ताकत और हुनर दिखाने का मंच मिलेगा। प्रवीण खुद मैदान पर मौजूद रहकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि खेल न केवल करियर के लिए, बल्कि युवाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। मेरठ के खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन में यहां की मिट्टी से एक बार फिर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे, जो भारतीय टीम की नीली जर्सी पहन देश का नाम रोशन करेंगे।

युवक के चेहरे पर चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी : मामूली बात पर सरेबाजार एक का चेहरा चाकू से चीरने वाले चाकूबाज को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में मंगलपड़ाव घास मंडी निवासी रोहन राजपूत ने बताया कि उसका भाई विनय राजपूत पुत्र स्व.गंगा राम सब्जी मंडी स्थित गौतम मोंगा की दुकान में काम करता है। बीती 30 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे वह दुकान के सामने से अपनी स्कूटी हटा रहा था। तभी प्रमोद पुत्र रामदास निवासी राजपुर गाड़ी हटाने को लेकर बहस शुरू कर दी। प्रमोद के साथ दो से तीन लोग और थे। उक्त लोगों ने विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी।

विनय जान बचाकर दुकान के अंदर भागा तो आरोपी दुकान के अंदर घुस आए और दुकान से चाकू उठा कर विनय की नाक, मुंह और अंगूठे पर वार कर दिया। इलाज के दौरान विनय को 12 टांके लगाए गए। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पहाड़ों में सुरक्षित प्रसव भी चुनौती

संवाददाता, हल्द्वानी

- छह साल में 3682 बच्चों का जन्म 108 एम्बुलेंस में
- हर जिले में महिला अस्पताल से मिलेगी मदद

अमृत विचार: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्भवतियों का सुरक्षित प्रसव कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल ये हैं कि पहाड़ों में जो महिला अस्पताल या अन्य अस्पताल हैं, वे ज्यादातर रेफरल सेंटर बन गए हैं। ऐसे में कई बार गर्भवतियों को मैदानी इलाकों के हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय बजट में हर जिले में महिला अस्पताल बनाना राज्य के लिए संजीवनी का काम करेगा।

केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है और उसमें एक घोषणा की है कि अब हर जिले में महिला अस्पताल बनाया जाएगा। महिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी है। उत्तराखंड में पहाड़ों की बात करें तो यहां पर बीडी पांडे महिला चिकित्सालय-नैनीताल, महिला अस्पताल- पौड़ी गढ़वाल, महिला अस्पताल-अल्मोड़ा आदि हैं। इनके अलावा जिला अस्पतालों में भी महिला स्वास्थ्य सेवाओं की अलग से विंग है। इस सबके बावजूद सुविधाएं नहीं होने पर कई गर्भवतियों को रेफर करना पड़ता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 से अभी तक पिछले छह सालों में ही 3682 बच्चों ने 108 एम्बुलेंस में जन्म लिया है। पहाड़ों में पर्याप्त डॉक्टर व अन्य उपकरण नहीं होने की वजह से गंभीर मामलों में गर्भवतियों को रेफर करने के लिए अलावा कोई चारा ही नहीं होता है।

डॉक्टर नहीं चढ़ते पहाड़

हल्द्वानी : सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी जो मैदानी क्षेत्र में है वहां पर 50 प्रतिशत डॉक्टरों के पद खाली हैं। ऐसे में पहाड़ों में डॉक्टरों को भेजना और भी मुश्किल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अलग-अलग विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के कुल 1276 पद स्वीकृति हैं, जिसके सापेक्ष करीब 668 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ही तैनात हैं।

जन-जन के द्वार अभियान 20 फरवरी तक बढ़ाया

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को जन-जन के और निकट लाने के उद्देश्य से संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अभियान अब 20 फरवरी तक प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व यह अभियान 31 जनवरी तक निर्धारित था, जिसे जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं सुझावों के प्रभावी निस्तारण को देखते हुए 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।

सीओ सिटी ने ली पुलिस कर्मियों की क्लास

कार्यालय संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार : अर्धवार्षिक निरीक्षण पर सीओ सिटी अमित कुमार सैनी बनभूलपुरा कोतवाली पहुंचे तो पुलिस की चुस्ती और दुरुस्ती का राज खुल गया। पुलिस कर्मियों को असलहा खोलने और फिर जोड़ने का टास्क दिया गया। उन्होंने असलहों को खोला और जोड़ भी दिया, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं, जिसकी सीओ की उम्मीद थी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को नियमित अभ्यास की नसीहत दी। साथ ही मालखाना, हवालात, भोजनालय व कार्यालयों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत गार्द, कोतवाली भवन, कार्यालय, बैरिक और हवालात से हुई। सीओ सिटी ने साफ-सफाई को लेकर नाराजगी जताई और नियमित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। भोजनालय का निरीक्षण कर जवानों को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने को कहा। कोतवाली के दस्तावेज और लंबित मामलों की समीक्षा की। यहां भी रवैया संतोषजनक नहीं था। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण विवेचना और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

असलहे की नाल में झांक कर साफ-सफाई देखते सीओ सिटी अमित कुमार सैनी।

साथ ही कार्यालय स्टाफ को रिकॉर्ड का सही रख-रखाव करने की हिदायत दी। उन्होंने सीसीटीएनएस समेत सभी ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति जांची। प्रभारी निरीक्षक को सभी पोर्टल समय-समय पर अपडेट रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा। माल मुकदमाती के पुलिंदों का मालखाना रजिस्टर से मिलान कराया गया और लंबित मालों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। सीओ सिटी ने कहा, असलहा, एम्युनेशन की गिनती कराते हुए पुलिस कर्मियों से असलहा खोलने और जोड़ने का नियमित अभ्यास करने, हथियार हमेशा साफ-सुथरे और दुरुस्त हालत में होने चाहिए।

हेल्प डेस्क पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कोतवाल दिनेश सिंह फर्त्याल, एसआई मनोज यादव सहित कोतवाली का स्टाफ मौजूद रहा।

तस्करी

बरेली से भगाए जाने के बाद ड्रग सिंडिकेट ने बहेड़ी को बनाया अड्डा, यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बसा है बहेड़ी

पहाड़ की फिजा में घुला बहेड़ी का नशा, गांव-गांव में अरबों का धंधा

सर्वेश तिवारी, हल्द्वानी

अमृत विचार : एक वक्त था, जब बरेली से देश के कई राज्यों तक स्मैक की तस्करी होती थी, लेकिन योगी सरकार में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई और इन्हें बरेली से भाग कर बहेड़ी में छिपना पड़ा।

कुछ समय तक शांत रहे और इसी दरम्यान ड्रग सिंडिकेट ने नया नेटवर्क खड़ा कर दिया। हालांकि नया सिंडिकेट पहले की तरह दूर तक नहीं फैल सका। ऐसे में नए सिंडिकेट ने कुमाऊं को निशाने पर लिया, लेकिन अपने बिल में दुबक कर। अब ये सिंडिकेट स्मैक के साथ नशीले इंजेक्शन, कैप्सूल और टेबलेट्स भी सप्लाई कर रहा है।

बरेली में मीरगंज, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी और सिरौली, ये वो इलाके हैं जहां से कभी स्मैक की तस्करी हरियाणा, दिल्ली और मुम्बई तक की जाती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वर्ष 2021 में इन पर सख्ती शुरू हुई। बरेली पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति खंगालनी शुरू की तो शिकंजे में बरेली के पढ़ेरा गांव का तत्कालीन प्रधान छोटे खां और उसका भतीजा राजू फंसा। इनके पास से 20 किलो स्मैक बरामद की गई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रधान छोटे खां नशे का के तार दिल्ली के दो लाख के इनामी तैमूर उर्फ भोला से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस तैमूर की तलाश में है। तैमूर के जरिए छोटे खां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई और दिल्ली में ड्रग सप्लायर के तौर पर बड़ा नाम था। ऐसे कई लोगों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, लेकिन इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बहेड़ी में कारोबार जमा लिया है। पुलिस का कहना है कि बहेड़ी में बसा ड्रग सिंडिकेट अब गांव-गांव में स्मैक या फिर कैप्सूल, इंजेक्शन और टेबलेट्स बेचता है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल का कहना है कि इन्हें जड़ से मिटाने के लिए यूपी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की योजना बताई जा रही है।

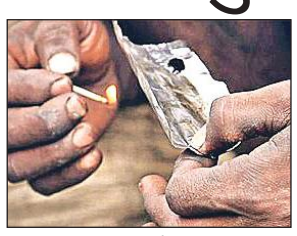

ये हैं वो ड्रग माफिया, जो बिगाड़ रहे फिजा

कुमाऊ में ड्रग्स सप्लाई करने वालों में बरेली के पूर्व प्रधान शहीद, तैमूर उर्फ भोला, नन्हे उर्फ लंगड़ा, उस्मान, इस्लाम, इरफान, फैय्याज, छोटे प्रधान और रिफाकत का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। बताया तो यह भी जाता है कि इनमें से कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ यूपी से बाहर जाकर धंधा कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर अब भी उत्तराखंड है। बड़ी बात यह है कि गैर राज्य में बैठे होने की वजह से उत्तराखंड पुलिस इन पर शिकंजा नहीं कस पा रही।

तीसरी बार चखा तो फिर नहीं छूटता नशा

स्मैक की लत एक बार में नहीं लगती और लग जाए तो फिर छूटती नहीं। स्मैक के काले कारोबार से जुड़े कारोबारियों की मानें तो अगर स्मैक की तीन डोज किसी को दे दी जाए तो फिर लत लग जाती है और फिर छूटती नहीं। ये तीन डोज तीन दिन तक लगातार दी जाती है। इसके बाद लोग स्मैक के आदी हो जाते हैं।

पैडलर बनाने के लिए देते हैं मुफ्त डोज

उत्तराखंड और इसके प्रवेश द्वार हल्द्वानी को स्मैक माफिया ने अपना डिपो बना लिया है। यहां स्मैक की सप्लाई को आसान बनाने के लिए ये माफिया युवाओं को स्मैक की लत लगा रहे हैं। पहले इन्हें स्मैक के मुफ्त डोज दिए जाते हैं और जब युवाओं को इसकी लत लग जाती है तो ये माफिया इन्हीं युवाओं को पैडलर बनाकर स्मैक तस्करी कराते हैं।

स्मैक से कहीं मुफीद हुआ नशीले इंजेक्शन का धंधा

स्मैक की तस्करी में गिरावट हुई है, लेकिन इसकी जगह नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल ने ले ली है। इनकी तस्करी स्मैक की अपेक्षा आसान है यानी खतरा कम है। पुलिस का कहना है कि स्मैक का लती आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन लेने वाले आसानी से समझ नहीं आते। इंजेक्शन, स्मैक से सस्ता भी है। इसी वजह से इसका बाजार तेजी से पनप रहा है।

झारखंड गैंग : एक ने चुराए जेवर तो दूसरे ने मोबाइल

कार्यालय संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार : हाल में मुखानी थाना क्षेत्र में झारखंड, महाराष्ट्र और नेपाल के गैंग ने मिलकर राधिका ज्वैर्ल्स में सेंधमारी कर सवा करोड़ रुपए का माल पार कर दिया। अब झारखंड के एक और गैंग ने शहर में दस्तक दी है। ये गैंग 13 सौ किमी दूर झारखंड से आकर हल्द्वानी मोबाइल चोरी करता था।

हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि बीती 30 जनवरी को मंगलपड़ाव की सब्जी मंडी और सदर बाजार में खरीदारी करने गईं बिठौरिया, ऊंचापुल निवासी दीक्षा और सावित्री कालोनी कालाढूंगी रोड निवासी दुर्गा भोसले के मोबाइल पार कर दिए थे। पुलिस ने मामले में सुजन मुखर्जी पुत्र रोहित मुखर्जी निवासी छोटा तितुलिया हाथीघर, तीन पहाड़ जिला साहिबगंज झारखण्ड व यहीं के मन्नी नोनिया पुत्र भुवन नोनिया को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी गौरव जोशी, एसआई रविन्द्र राणा रहे।

मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी।

अमृत विचार

सोमवार, 2 फरवरी 2026

सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है- असफलता का भय।

-पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिS आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीन का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलांकि केवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समाधान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र–राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।

प्रसंगवश

एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पदमश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है।

पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौंता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुआ। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीड़ित मानवता की पीड़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्ग्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प किया।

अमरपाल सिंह वर्मा

वरिष्ठ पत्रकार

अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोग और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा।

वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पीटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लगा देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वेश, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पदमश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।

आम बजट 2026 विकास व अनुशासन का संतुलन

रजत मेहरोत्रा

वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6 % के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को ब्याज भुगतान पर कम खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सरकार खर्च भी करेगी और कर्ज को भी नियंत्रण में रखेगी।

बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी के स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक सेहत मजबूत होती है। जब सरकार का घाटा घटता है, तो उसे कम उधार लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसंरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसंरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रावधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेश में अध्ययन करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभांश वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र देश में 11 करोड़ से अधिक रोजगार देता है, इसलिए इसमें निवेश सीधे रोजगार सृजन से जुड़ा है। एमएसएमई के डिजिटलीकरण और निर्यात क्षमता बढ़ाने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा। कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए बजट ने पूरी वैल्यू चेन- फाइबर से फैशन तक को मजबूत करने का रोडमैप दिया है। नई नेशनल फाइबर स्कीम से उत्पादन लागत घटेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। भारत का टेक्सटाइल निर्यात पहले ही लगभग 40 अरब डॉलर के स्तर पर है और इस नीति से इसमें और वृद्धि की संभावना बनेगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इससे पलायन कम होगा।

सरकार ने सात नए रेल कॉरिडोर और टियर-2 शहरों पर फोकस की घोषणा की है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। रेलवे में निवेश का गुणक प्रभाव स्टील, सीमेंट और निर्माण उद्योग पर पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। आईटी, एआई और डेटा सेंटर नीति बजट 2026 की सबसे रणनीतिक घोषणाओं में से एक है। सरकार ने एआई के लिए 'पिक एंड शोवेल' अप्रोच अपनाई है यानी सीधे एप्लिकेशन पर नहीं, बल्कि अवसंरचना पर निवेश। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की गई है, बशर्ते वे भारतीय रीसेलर्स का उपयोग करें। इससे भारत ग्लोबल डेटा हब बनने की दिशा में बढ़ेगा और आईटी सेक्टर में उच्च-मूल्य रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य और बायो-फार्मा सेक्टर को बजट में नई ऊर्जा मिली है। अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल से अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म, आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सेवाओं और पोस्ट-केयर सुविधाओं के विस्तार से भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 9-10 अरब डॉलर का है, जिसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता इस नीति में है। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर रणनीति बजट 2026 का सबसे भू-रणनीतिक पक्ष है। सरकार ने रेयर अर्थ खनिजों के घरेलू उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू-चेन विकास के लिए विशेष आवंटन किया है।

दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

आमने

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमे हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेटल करा लें सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा। कहीं नहीं जाएगा।

-गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस नेता, राजस्थान

सामने

कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

-मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात

रोहित माहेश्वरी

स्वतंत्र पत्रकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नही कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी हैं। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागज़ी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल अशिक्षा और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पड़ोस के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है।

अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

सोशल फोरम

जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक़ में थे, कुछ खिलाफ़। आख़िर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे।

हिस्ट्री अनफोल्ड

ब्लॉगर

'मैं गुनहगार, रिंद, सियाहकार, बदनसीब—और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।'

अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आख़िरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर ख़ामोश हो गए। सिरहाने बोतल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौक़ा मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुज़रा, दो दिन गुज़र गए। नात के मज़मून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आख़िर एक दिन नात का मतला हो गया।

फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक़ सूखा नहीं था। इधर तो यह हाल था, दूसरी तरफ़ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आख़िर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुतग़ज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!'

इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मजमे की ओर देखा और प्रेम से भरे स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रसूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?'

शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली-

एक रिंद है और मद्हत-ए-सुल्तान-ए-मदीना
हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी

बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं।

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रेप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं।

अंबिका अंबी

लेखिका

जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है।

वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना।

डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियों की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटी को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं मकान नं.197/1, समता आश्रम गली, रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक - अमित शर्मा*** 05946292618 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UTTHIN/2021/79698, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नैनीताल होगा)।

कार खरीदना कुछ लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, तो कुछ लोगों के लिए शानो-शौकत और रुतबे का प्रतीक, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह हमेशा से एक सपने के सच होने जैसा है। कार आज हम सभी के घरों का एक जरूरी और अहम हिस्सा बन चुकी है। इस मांग की वजह से ही हाल के वर्षों में पुरानी कारें खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है और देश में पुरानी कारों का बाजार एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यह तब हुआ है, जब लोगों को भरोसा हुआ है कि पुरानी कारें भी नई कारों जितनी ही अच्छी हो सकती हैं। एक और वजह यह भी है कि पसंदीदा नई कारें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, ऐसे में कम बजट में बेहतर ब्रांड, शानदार फीचर्स की उपलब्धता भी पुरानी कारों की मांग को शहरों से लेकर कस्बों तक आगे बढ़ा रही है। हालांकि काफी सारे लोग पुरानी कार खरीदने में जोखिम और धोखाधड़ी के कारण बचते हैं, लेकिन पुरानी कारों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद से चीजें काफी आसान भी हो गई हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर

नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वारंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रांसफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वॉलिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारें खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रिसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

इन कारों की मांग सबसे अधिक

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैगनआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेंड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।

खरीदने से पहले जरूरी बातें

- सबसे पहले अपना बजट बनाएं,फिर यह देखें कि पुरानी कार फर्स्ट हैंड है या फिर उसके पहले भी कई ऑनर रह चुके हैं। ऐसी कार लेना हमेशा बेहतर होता है, जो कम किलोमीटर चली हो। भारत में, एक कार औसतन सालाना 6 हजार से 12 हजार किलोमीटर चलती है। यह जरूरी है कि आप सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी की पूरी स्थिति के अनुसार चलाए गए किलोमीटर की जांच करें।
- आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच करें। ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री मिलाएं। कार को दिन की रोशनी में ध्यान से देखें।
- टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आवाज, ब्रेक, गियर पर ध्यान दें। किसी अच्छे मैकेनिक से पूरा इंस्पेक्शन करवा लें। इंश्योरेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया ठीक से समझें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से खरीदें

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म : ज्यादा विकल्प, पारदर्शी कीमत
- डीलरशिप : भरोसेमंद लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा
- डायरेक्ट ऑनर : सस्ता सौदा, पर जोखिम ज्यादा

Hero Vida Dirt.E K3 : बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt.EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।

दमदार बैटरी

Dirt.EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटर कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

इंटरनेशनल पहचान

Dirt.E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt.EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

कीमत और उपलब्धता

Vida Dirt.EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

बच्चे के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।

मॉय फर्स्ट राइड

सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा

जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई।

2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा।

कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना।

धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूं और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूं। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है।

इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया।

आज जब मैं कार चलाती हूं, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

काम की बात

सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक्स सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ठंड का बाइक पर असर

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लेड-एसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेंटेनेंस नियमित नहीं होता।

स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके

- **स्पार्क प्लग की भूमिका अहम-** ठंड और नमी के कारण स्पार्क प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पार्क कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट फ्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से जान पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड-** सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग-** कार्बोरेटर वाली बाइक्स में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है।
- **इग्निशन ऑफ रखकर प्री-किक तकनीक-** ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इग्निशन बंद रखकर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान-** बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मेंटेनेंस सलाह-** ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल-** ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कोसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मेंटेनेंस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अमृत विचार
हल्द्वानी, सोमवार, 2 फरवरी 2026

बिजीनेस ब्रीफ

शिव कथा में मना पार्वती जन्मोत्सव

हल्द्वानी : एमबी इंटर कॉलेज में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से आयोजित शिव कथा के चतुर्थ दिवस रविवार पर माता पार्वती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास डॉ. सर्वेश्वर ने कहा कि महाराज हिमवान ने 27 वर्षों की तपस्या से पुत्री रत्न प्राप्त किया था, जो बेटी के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण प्रदर्शन से नहीं, बल्कि आत्मदर्शन और ब्रह्मज्ञान से संभव है। नारी अबला नहीं, बल्कि शक्ति का पुंज है। इस अवसर पर नीरज शारदा, शशि भूषण अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, हेमंत द्विवेदी, जितेंद्र साहनी रहे।

तारबाड़ में फंसे घुरड़ को किया रेस्क्यू

नैनीताल : तल्लीताल लॉगव्यू कंपांउड क्षेत्र में तारबाड़ में फंसे एक घुरड़ को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर घुरड़ को चिड़ियाघर भेजकर उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम लॉगव्यू तल्लीताल क्षेत्र में एक घुरड़ आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया। लोगों को देख घुरड़ जंगल को भागने की कोशिश की तो वह तारबाड़ में फंस गया। इसकी सूचना लोगों ने तत्काल वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची विभागीय टीम ने जाल डालकर घुरड़ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी ललित कार्की ने बताया कि घुरड़ को चिड़ियाघर भिजवा दिया गया है। तार में फंसने के कारण उसे मामूली चोटे आई है। जिसे उपचार दिया जा रहा है। रेस्क्यू में निमिष दानू, नारायण चंद, चंदन, मनीष कुमार शामिल रहे।

रानीबाग में साढ़े छह घंटे गुल रही बिजली

हल्द्वानी : ऊर्जा निगम की ओर से लाइनों के आधुनिकीकरण और रखरखाव कार्य के चलते रविवार को रानीबाग क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। सुबह से शाम तक बिजली न होने से घरेलू कामकाज ठप रहे और पेयजल संकट ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। 33/11 केवी उपसंस्थान एचएमटी रानीबाग के गायत्री नगर फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सुबह 9 :30 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद रही। साढ़े छह घंटे की इस लंबी कटौती के कारण व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुईं। नलकूप फीडर बंद होने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। ऊर्जा निगम के ईई प्रदीप कुमार ने बताया आज सोमवार को 33/11 केवी उपसंस्थान गौलापार के अंतर्गत आने वाले नलकूप फीडर और दानीबंगर फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था रखने की अपील की है।

क्षेत्र से अब तक छह गुलदार वन विभाग के पिंजरे में हो चुके हैं कैद, घटनाओं में कमी आने से विभाग ने ली राहत की सांस

डर के साये में खुले स्कूल, गुलदार की दहशत में बच्चे और अभिभावक

संवाददाता, धानाचूली

अमृत विचार: नैनीताल जिले के धारी-ओखलकांडा क्षेत्र में गुलदार की लगातार घटनाओं ने आमजन के साथ-साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार से स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा है। घने जंगलों से घिरे गांवों में हालात सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं।

धारी और ओखलकांडा क्षेत्र में गुलदार द्वारा तीन महिलाओं को अपना शिकार बनाए जाने की घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इसी भय के बीच कई किलोमीटर दूर बसे गांवों से बच्चे जंगलों और सुनसान रास्तों से पैदल स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने धारी क्षेत्र के सभी स्कूलों और आसपास के इलाकों को संवेदनशील घोषित किया है।

विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़ने और लेने आएं। साथ ही शिक्षक संघ और अभिभावक संघ के साथ बैठक कर बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। वन विभाग द्वारा भी स्कूलों और जंगलों के आसपास लगातार गश्त की जा रही है।

अब तक छह गुलदार पकड़े जाने के बाद धारी क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। मवेशियों पर होने वाले हमलों में भी गिरावट आई है, जिससे ग्रामीणों को कुछ राहत मिली है। घटनाओं में कमी के बाद लोग फिर से जंगलों की ओर जाने लगे हैं, हालांकि महिलाएं अब एहतियातन झुंड में ही जंगल जा रही हैं। क्वैदल, तल्ली दीनी, खुटियाखाल, अघरिया, गुनियालेख, सरना सहित कई गांव घने जंगलों से घिरे हैं, जहां बच्चों को रोजाना जोखिम भरे रास्तों से होकर स्कूल आना-जाना पड़ता है।

सीमित संसाधनों के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा विभाग और वन विभाग के आपसी समन्वय से ही यह संभव है कि बच्चे डर के साये में नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें।

> कई गुलदार पकड़े जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में अभी भी खतरा बना रहेगा, वहां वन विभाग और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। **-अंशुल भट्ट**, उपजिलाधिकारी, धारी (नैनीताल)

> सभी प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि खतरा टलने तक बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने में सहयोग करें। **- शुभम वर्मा**, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी, धारी

> संवेदनशील क्षेत्रों में हमारा विभाग लगातार गश्त कर रहा है। मानव-वन्यजीव संघर्ष और मवेशियों पर हमलों में कमी आई है, फिर भी बच्चों और आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। **-ममता चंद**, एसडीओ, वन विभाग, नैनीताल

> मैनपावर की कमी के चलते अन्य रेंजों से अधिकारियों और वनकर्मियों को बुलाकर दिन-रात गश्त कराई जा रही है। कई स्कूलों के आसपास झाड़ियों को ग्रामीणों की मदद से साफ किया गया है। टीम लगातार जंगलों और स्कूल परिसरों के आसपास कॉम्बिंग कर रही है। **- विजय भट्ट**, रेंजर, उत्तरी गोला रेंज, नथुवाखान

होटल कर्मचारी व युवकों के बीच मारपीट, हंगामा

नैनीताल: नैनीताल के स्नोव्यू क्षेत्र में एक होटल में होटल कर्मियों औ स्थानीय युवकों का विवाद हुआ तो मारपीट हो गई। रविवार को हंगामा होने पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया।

जानकारी के अनुसार शनिवार की रात स्थानीय दो युवकों ने स्नोव्यू क्षेत्र के होटल में कमरा किराए पर लिया। रात को वहां ठहरने के दौरान होटल कर्मचारियों व युवकों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जिसके बाद युवक अन्य युवकों के साथ दोबारा होटल पहुंच गए। देर रात किसी तरह मामला शांत हुआ लेकिन सुबह दोबारा विवाद होने पर स्थानीय सभासदों व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। कोतवाल हेम पंत ने बताया कि मामले में किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

सरोवर नगरी नैनीताल में रिमझिम बारिश के बाद ठंड में हुआ इजाफा

नैनीताल में रविवार को रुक-रुक कर होती रही बारिश, आसमान में दिनभर छाये रहे बादल

संवाददाता, नैनीताल

अमृत विचार: नैनीताल में मौसम का मिजाज बदल चला है। रविवार को नगर में रिमझिम बारिश हुई। मौसम बदलने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ऊंची चोटियों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

नगर में प्रातः आठ बजे से हल्की बारिश शुरू हो गई, जो रुक रुक कर होते रही। इसके बाद दस बजे से 11 बजे तक रिमझिम बारिश जारी रही। इसके बाद वर्षा तो नहीं ही, लेकिन बादल पूरे दिन असमान में डेरा डाले रहे।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है। जिसका सर्वाधिक असर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में रहा, जबकि इसके बाद आ रहे दूसरे पश्चिमी का असर मंगलवार को नैनीताल, देहरादून और चंपावत में अधिक प्रभावी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं राज्य मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ से तीन हजार मीटर के आसपास की चोटियों में हिमपात की संभावना रहेगी। जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी।

जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आद्रता अधिकतम 90 व न्यूनतम 60 प्रतिशत रही।

नैनीताल में रविवार को आसमान में छाये बादल। ● अमृत विचार

सुबह हुई रिमझिम, दिन में निकली धूप

हल्द्वानी : हल्द्वानी में कुछ ही घंटे में दो तरह के मौसम देखने को मिले। तड़के तेज हवा चली और बारिश हुई और दोपहर तक रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इधर दोपहर बाद धूप निकल आयी और एकदम से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का अनुमान सही साबित हुआ और राज्य में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अनुमान है कि तीन फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। हल्द्वानी में सुबह पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद दिन में पारा चढ़ने से अधिकतम तापमान 22 .7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 .8 डिग्री रहा। मुक्तेश्वर में पारा 13 .4 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को नैनीताल जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

हर्जाना देने के बाद खाता कराया होल्ड

हल्द्वानी: सड़क हादसे में दो कारों के बीच हुई भिड़ंत के बाद एक ने व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली। उसने पीड़ित को हर्जाने के तौर पर 15 हजार रुपये का भुगतान किया और फिर इसके बाद बैंक में फोन कर खाता होल्ड करा दिया। पीड़ित ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।

तल्ला कांडा, ढोलीगांव, धारी नैनीताल निवासी राकेश गोस्वामी पुत्र पान गिरी गोस्वामी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी को बताया कि बीती 23 जनवरी को कोटला पट्टी पतलिया मुक्तेश्वर में एक कार ने गलत दिशा से आकर उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद टक्कर मारने वाले व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और 15 हजार रुपए बतौर हर्जाना उसके खाते में डाल दिए।

आरोप है कि इसके बाद भुगतान करने वाले अपने बैंक में शिकायत कर कहा कि गलती से उससे भुगतान हो गया है। जिसके बाद बैंक ने खाता होल्ड कर दिया और सारा पैसा फंस गया। पीड़ित ने यह आरोप भी लगाया कि इस मामले को लेकर वह पिछले लंबे समय से पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। जिसके बाद उसने एसएसपी से शिकायत की।

नाबार्ड ने 46.09 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी

संवाददाता, हल्द्वानी

- नैनीताल के ग्रामीण विकास को लगेंगे पंख

अमृत विचारः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने नैनीताल जनपद के ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की 31वीं किस्त के तहत 46.09 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

इस बजट से जिले में सड़कों का जाल बिछेगा, पुलों का निर्माण होगा और सिंचाई सुविधाओं में सुधार आएगा। कुल स्वीकृत राशि में 27.22 करोड़ की नई परियोजनाएं और 18.87 करोड़ की पूर्व में स्वीकृत राशि शामिल है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से किया जाएगा। कृषि और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई विभाग को धारी, भीमताल, रामगढ़ और बेतालघाट विकासखंडों के लिए 359.18 लाख आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत 25 नई परियोजनाओं में चेक डैम, पाइपलाइन और सोलर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्थापित की जाएंगी। सौर ऊर्जा आधारित इन योजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती और स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, सिंचाई विभाग बेतालघाट के लोहरी और धनियाकोट में 97.45 लाख की लागत से जल वितरण प्रणाली का विस्तार करेगा, जिससे कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। हल्द्वानी विकासखंड में रामनगर-सितारगंज मार्ग के किमी 36 पर 319.20 लाख की लागत से 24 मीटर स्पैन का आरसीसी पुल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण के तहत बेतालघाट-रातीघाट मार्ग से रींण मोटर मार्ग (10.15 किमी) के लिए 542.45 लाख, बेतालघाट-पडली स्टेज मोटर मार्ग (10.15 किमी) के लिए 1052.53 लाख और ओखलकांडा में भेड़ापानी-खुजेती मार्ग के सुधार हेतु 351.26 लाख स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड की इस पहल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार होगा। निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के नव निर्वाचित पदाधिकारी। ● अमृत विचार

मदन पांडे अध्यक्ष और हरीश ध्यानी बने मंत्री

रामनगर : वन विकास निगम के कर्मचारियों के हितों के लिए संगठन संघर्ष करता रहेगा, यह बात उत्तराखंड वन विकास निगम, पश्चिमी क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष मदन मोहन पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ आपसी सामंजस्य बनाते हुए संगठन को और मजबूत किया जाएगा। बताया गया कि वन विकास निगम कर्मचारी संगठन, पश्चिमी क्षेत्र की नई कार्यकारिणी का गठन प्रांतीय मंत्री प्रेम सिंह चौहान, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बुद्धि सिंह और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद बहुगुणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यकारिणी में नवीन चंद्र मिश्रा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, खीम सिंह अधिकारी को उपाध्यक्ष, हरीश चंद्र ध्यानी को मंत्री, संजय पांडे को कोषाध्यक्ष, दीपक सिंह को संयुक्त मंत्री, अरविंद पवार को संगठन मंत्री, दिगम्बर सिंह बिष्ट को संगठन मंत्री द्वितीय व विकास सिंह कठेत को प्रचार मंत्री चुना गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिलाई भाजपा की सदस्यता

संवाददाता, कालाढूंगी

अमृत विचारः कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत ने 50 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, ऐतिहासिक विकास कार्यों तथा विधायक बंशीधर भगत के मजबूत, अनुभवी और जनसमर्पित नेतृत्व से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। रविवार को आरके टेंट हाउस रोड स्थित भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक विनय सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, समाजसेवियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी नव-प्रवेशित सदस्यों का भाजपा परिवार में फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी समाज का वह वर्ग है, जिसने वर्षों तक राष्ट्र और व्यवस्था की सेवा की है। उनके अनुभव से संगठन को मजबूती मिलेगी। शक्ति केंद्र संयोजक विनय सिंह, मंडल अध्यक्ष सुरेश गौड़, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन उप्रेती, दीपक सनवाल, गीता तोमर, लीलाधर पंत, चंद्र सिंह नेगी रहे।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाते विधायक बंशीधर भगत।

नैनीताल में नियमों को तोड़ने वाले चुस्त, अधिकारी सुस्त

संवाददाता, नैनीताल

अमृत विचारः जिला मुख्यालय नैनीताल में हर रोज और हर कदम पर नियमों का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, मानो वे तमाशबीन बने हुए हैं।

बताया जाता है कि नैनीताल में जिला मुख्यालय के क्षेत्र में हाईकोर्ट, कमिश्नरी, आईजी कार्यालय, डीएम कार्यालय और एसएसपी कार्यालय मौजूद हैं। इसके बावजूद यहां नियमों को अक्सर ताक में रखा जाता है। नगर में प्रतिदिन कई बड़े अधिकारी इन सड़कों से गुजरते हैं, फिर भी लोग उनके सामने खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। विशेष रूप से देखा गया है कि लोग ट्रैफिक नियम, पार्किंग और अन्य स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ओर से किसी भी प्रकार की चेतावनी या कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे नागरिकों में कानून का भय धीरे-धीरे खत्म हो गया है और वे निडर होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नागरिक शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं, जिससे कानून की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता है, तो नगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है।

सरकारी प्यास बुझाते बुझाते खाली हुआ जल संस्थान का खजाना

हल्द्वानी : जल संस्थान के राजस्व पर इस समय सरकारी विभाग ही सेंध लगा रहे हैं। आम आदमी का कनेक्शन काटने में फुर्ती दिखाने वाला संस्थान खुद सरकारी विभागों की मेहरबानी का इंतजार कर रहा है। शहर के 11 प्रमुख विभागों ने करीब 10 करोड़ रुपये का पानी तो पी लिया, लेकिन उसका बिल चुकाना भूल गए। अब जल संस्थान ने इन बकायेदारों को नोटिस थमाना शुरू किया है। बकायेदारों की सूची में वन विभाग सबसे आगे है, जिस पर 3 .78 करोड़ रुपये का बिल लंबित है। सिंचाई विभाग भी पीछे नहीं है, उसे 3 .07 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसके अलावा शहर की सफाई का जिम्मा संभालने वाले नगर निगम पर 1 .15 करोड़ रुपये की देनदारी है। लोक निर्माण विभाग (82 .48 लाख) और शिक्षा विभाग (46 .57 लाख) भी संस्थान की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने में पीछे नहीं हैं। अब पुलिस, तहसील, रेलवे और विद्युत जैसे विभागों को नोटिस जारी कर भुगतान की अंतिम चेतावनी दी गई है।

मॉडलों से दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा

संवाददाता, रामनगर

अमृत विचारः पीएमश्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रामनगर में शनिवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में उभरती बाल वैज्ञानिकों ने शानदार मॉडल प्रस्तुत कर अपने भीतर छिपी वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दिया। छात्राओं ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में वे किसी से कम नहीं हैं।

विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं ने वर्षा जल संग्रहण, प्रकाश संश्लेषण, जल चक्र, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सोलर पंखा, पवन चक्की सहित अनेक वैज्ञानिक मॉडलों का निर्माण कर दर्शकों को चकित कर दिया। डॉ. बीनू पंवार, हेमा मेहरा, सुमन नेगी, भावना जोशी और मनीषा सक्सेना के संयुक्त संचालन में आयोजित इस प्रदर्शनी में 125 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी को जूनियर (कक्षा 6 से 8) और सीनियर (कक्षा 9 से 12) वर्गों में आयोजित किया गया। जूनियर वर्ग में सना ने प्रथम, निकिता रावत ने द्वितीय और वायजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में अर्शी प्रथम, खुशनुमा द्वितीय और गीतिशा बिष्ट तृतीय स्थान पर रहीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग में पांच छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विमला साह, दीक्षा जोशी और दीप्ति तिवारी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। विजेता छात्राओं को प्रधानाचार्या के.डी. माथुर ने पुरस्कार वितरित किए।

रामनगर में विज्ञान प्रदर्शनी में अपने मॉडल प्रस्तुत करतीं छात्राएं। ● अमृत विचार

भारी वाहनों को रोककर चेकिंग करती परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम।

176 वाहनों के चालान, 12 वाहन किए सीज

हल्द्वानी : परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने गौला खनन क्षेत्र में दो दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 7 टीमों ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 176 वाहनों के चालान किए गए और 12 वाहनों को सीज किया गया, जिनमें कई वाहन ओवरलोड पाए गए। टीम में एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र सिंगवान, परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार सहित, परिवहन विभाग के अधिकारी व उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में की गई। अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा और अवैध खनन परिवहन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। आरटीओ प्रवर्तन व सड़क सुरक्षा अरविंद पांडे के निर्देश पर अभियान चलाया गया।

भाजपा के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों का विधायक बिष्ट ने किया स्वागत

संवाददाता, रामनगर

अमृत विचारः भाजपा नगर मंडल एवं ग्रामीण मंडल के विभिन्न मोर्चों के नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत किया गया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता इंदर सिंह रावत ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी।

यहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट और इंदर सिंह रावत ने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य करें। इस दौरान अनुसूचित मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष इंद्रपाल, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष संजीव सैनी, रामनगर ग्रामीण मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित रावत, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपा पांडे, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा, अनुसूचित मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सौरभ कुमार, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष अनुज कश्यप, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष फईम कुरैशी तथा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूर अली खान व अन्य का स्वागत किया गया।

विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों का स्वागत करते विधायक दीवान सिंह बिष्ट । ● अमृत विचार

वर्ल्ड ब्रीफ

लाखों की चोरी प्रकरण में दर्ज हुआ मुकदमा

रुद्रपुर : थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में हुई लाखों की चोरी प्रकरण में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने खुलासे की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। आनंद विहार वार्ड-एक निवासी सन्नी जौहरी 22 जनवरी की रात्रि दस बजे अपने दोस्तों के साथ राजस्थान धार्मिक दर्शन के लिए गया था, जबकि पत्नी अपने मायके गई हुई थी। 24 जनवरी की शाम साढ़े चार बजे पड़ोसी का फोन आया कि घर की छत का जीना खुला हुआ है और छत पर सामान बिखरा पड़ा है। जब पड़ोसी घर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने पूरा घर खंगाल दिया है। चोरों ने अलमारी में रखी सोने व चांदी के आभूषण, दो मोबाइल के अलावा नगदी चोरी कर ली थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है।

छह उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर : यूपीसीएल और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बिजली चोरों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर की टीमों ने 30 जनवरी को अधिशासी अभियंता राजीव चक्रवर्ती के नेतृत्व में 201 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 41 लोग चोरी करते पकड़े गए। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने सहायक अभियंता पुनीत कुमार की तहरीर पर छह प्रमुख उपभोक्ताओं—सर्वेश रस्तोगी, सुमित राय, गौतम कुमार, गनपत राय, राम सिंह और कुलदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोटद्वार प्रकरण को लेकर जिम का घेराव

सोशल मीडिया पर मोहित चोपड़ा ने दिया था बयान, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिम ट्रेनर के यहां काटा हंगामा

संवाददाता, रुद्रपुर

अमृत विचार: कोटद्वार मोहम्मद दीपक प्रकरण की चिंगारी आवास विकास स्थित जिम ट्रेनर के यहां पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा खुद जिम संचालक मोहित चोपड़ा को नहीं था। सोशल मीडिया पर जैसे ही ट्रेनर ने तीन फरवरी को सभी जिम संचालकों को कोटद्वार पहुंचने का आह्वान किया, वैसे ही बजरंग दल भड़क गया और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जिम संचालक के यहां हंगामा काटा। पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने का मुद्दा उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।

बताते चलें कि 31 जनवरी को कोटद्वार में बजरंग दल द्वारा एक दुकान पर जाकर वास्तविक नाम लिखने का मामला उठाया था। तीस वर्षों से दुकान का संचालन करने वाले मुस्लिम बुजुर्ग के समर्थन में कोटद्वार के रहने वाले बॉडी बिल्डर दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बोल कर विरोध किया था। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। इसी दौरान एक जनवरी को आवास विकास के रहने वाले बॉडी बिल्डर एवं जिम संचालक मोहित चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर दीपक का समर्थन करते हुए तीन जनवरी को कोटद्वार कूच करने करने का आह्वान किया। बस क्या था रविवार की दोपहर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित जिम ट्रेनर मोहित चोपड़ा के जिम पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा काटा। आरोप था कि हिंदू होने के बाद भी कोटद्वार के दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बताया। जिसका समर्थन मोहित ने किया। आरोप था कि मोहित ने टीआरपी लेने के लिए हिंदुओं का अपमान किया। कहना था कि बजरंग दल ने महज दुकानों पर वास्तविक जाति व नाम का मुद्दा उठाया है, ताकि किसी समाज की भावनाएं आहत नहीं हों। उन्होंने जिम ट्रेनर के खिलाफ तहरीर देने का मुद्दा उठाया। इस मौके पर सचिन शर्मा, गौरव मिश्रा, सुल्तान सिंह, रमेश बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, अंकित श्रीवास्तव, प्रिंस कोली, यश चौहान, जितेंद्र विश्व कर्मा, सचिन मलिक, विवेक कश्यप, प्रदीप ठाकुर आदि मौजूद रहे।

चौकी के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं को समझाते थाना प्रभारी मोहन चंद्र पांडेय। ● अमृत विचार

चौकी घेराव की खबर सुनकर दौड़े चले आए थाना प्रभारी

रुद्रपुर : जिम पर हंगामा काटने के दौरान जैसे ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भनक लगी कि ट्रेनर मोहित आवास विकास चौकी में बैठा है। वैसे ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आवास विकास चौकी की ओर कूच डाला और हाथों में डंडे लेकर बदला लेने जैसी चेतावनी देनी शुरू कर दी। चौकी घेरने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ट्रांजिट कैंप मोहन चंद्र पांडेय फौरन पुलिस फोर्स के साथ चौकी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। गनीमत यह रही कि जिम ट्रेनर चौकी में नहीं था, वरना बवाल बड़ा हो सकता था।

जिम ट्रेनर ने 112 पर दी सूचना

रुद्रपुर : आवास विकास स्थित अपने जिम पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने की सूचना मिलते ही जिम संचालक मोहित चोपड़ा ने 112 पर पुलिस को सूचना देकर बताया कि वह बदायूं में होने वाली प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने गया है। उसकी गैरमौजूदगी में कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा और तोड़फोड़ करने की प्रबल संभावना है और परिवार भी भयभीत है। जिसके बाद पुलिस ने आवास विकास स्थित जिम जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। जिम ट्रेनर की सूचना को पुलिस ने रजिस्टर में भी अंकित कर लिया है।

स्लोगन के साथ पोस्टर पर लिखा नारा

रुद्रपुर : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से भड़के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जहां जिम संचालक के जिम पर जाकर हंगामा काटा। वहीं फोटोयुक्त जिम ट्रेनर के पोस्टर पर देश का बल, बजरंग दल का स्लोगन लिखकर चुनौती दी कि कार्यकर्ता अब ट्रेनर से बदला लेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आरोपी हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ भरे मैसेज भेज रहा है और बहरूपिया जैसा किरदार निभा रहा है। जिसको सबक सिखाना जरुरी है और विहिप के प्रखंड मंत्री सुदेव दास गुप्ता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की।

युवक पर किया हमला व्यापारियों का प्रदर्शन

किच्छा में कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते स्थानीय लोग एवं व्यापारी।

संवाददाता, किच्छा

अमृत विचार : कोतवाली क्षेत्र की फास्ट फूड मार्केट में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने वार्ड संख्या 14 निवासी प्रदीप कबीर पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना से आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते नशे के खिलाफ मौके पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मार्केट में असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन मारपीट और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने की मांग की। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। मौके पर विजय अरोड़ा, अमन मदान, नितिन फुटेला, रोहित अरोड़ा, सतीश गुप्ता, सन्नी अरोरा, चेतन गंगवार, सन्नी गंगवार आदि मौजूद रहे।

दरऊ चौक से दिनदहाड़े क्रेटा कार चोरी

किच्छा : कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम दरऊ चौक पर चोरों ने दिनदहाड़े एक क्रेटा कार चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना रविवार दोपहर करीब ढाई बजे की है, जब आजाद नगर निवासी लक्ष्मण दास अरोड़ा कार सड़क किनारे खड़ी कर फल खरीद रहे थे। मात्र 5 मिनट के भीतर चोर कार लेकर चंपत हो गए। बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण पुलिस के सीसीटीवी कैमरे बंद थे।

प्राथमिकता से होगा नगर का विकास

● वार्ड- तीन निवासियों ने सड़क व नाली निर्माण की उठाई मांग

संवाददाता, दिनेशपुर

अमृत विचार: नगर पंचायत के वार्ड-तीन निवासियों ने सड़क एवं नाली निर्माण की मांग को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पूर्व अध्यक्ष काबल सिंह विर्क को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी सड़क व नाली की मांग लंबे समय से चल रही है।

वार्ड-3 निवासी संगीता चंद ने बताया कि सभासद नारायण मंडल द्वारा वार्ड निवासियों को नगर पंचायत कार्यालय में बुलाया गया था। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही।

जबकि इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सूचना पर अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष काबल सिंह विर्क मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं।

विर्क ने कहा कि नगर की अन्य सड़कों और नालियों एवं विकास कार्यों के साथ वार्ड-तीन में सड़क व नाली का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित करने के बाद शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस अवसर पर ललित जोशी, मीना चंद, कमला गोस्वामी, मंजू मेहता, कलावती चंद, लीला देवी, सुशीला चंद, बलदेव सिंह, बलिहार सिंह लाडी आदि मौजूद रहे।

नपं पूर्व अध्यक्ष काबल सिंह विर्क को ज्ञापन सौंपते वार्डवासी। ● अमृत विचार

प्रेमी के साथ फरार हुई किशोरी

सितारगंज: 17 वर्षीय किशोरी घर से रुपये लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

वार्ड नंबर 9 निवासी महिला ने बताया कि ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर निवासी आदर्श उसकी नाबालिग पुत्री से फोन पर बात करता था। कई बार मना करने के बाद भी वह नहीं माना। बताया कि 29 जनवरी को उसकी पुत्री किसी काम से सितारगंज बाजार गई थी। काफी देर तक भी वापस घर न लौटने पर परिजनों को उसकी चिंता हुई तो आस-पड़ोस, नाते-रिश्तेदारों में उसकी खोजबीन शुरू की। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बताया कि घर में रखे तीस हजार रुपये भी गायब हैं।

सेवानिवृत्त कमांडेंट को जवानों ने दी विदाई

संवाददाता सितारगंज

अमृत विचार : 57वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल 40 वर्षों की विशिष्ट, अनुकरणीय और समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर महानिदेशक संजय सिंघल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया।

रविवार को वाहिनी में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बल के अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। बतातें चले कि साल 1986 में मनोहर लाल ने एसएसबी में प्रवेश किया था। प्रारंभिक वर्षों से ही उन्होंने अनुशासन, कर्मठता एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। फिर, साल 1986 से 1993 तक उन्होंने सशस्त्र सीमा बल की केंद्रीय वॉलीबॉल टीम का नेतृत्व किया। बल का खेल जगत में राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद साल 2014 में राष्ट्रपति ने उन्हें विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया। साल 2023 में उन्हें 57वीं वाहिनी के कमांडेंट की जिम्मेदारी मिली। यहां उन्होंने सीमित संसाधनों में प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सीमा चौकियों के विकास, संचार व्यवस्था, सुरक्षा फेंसिंग तथा जवानों के कल्याण से जुड़े अनेक उल्लेखनीय कार्य किया। वह बिना किसी औपचारिकता के जवानों के बीच उपलब्ध रहें। उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना तथा त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया। इस मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी (चिकित्सा) डॉ. बीबी. सिंह, उप कमांडेंट दीपक सिंह जायडा, उप कमांडेंट अनिल कुमार, सहायक कमांडेंट (संचार) अरविंद कुमार आदि उपस्थित रहे।

सितारगंज में कमांडेंट मनोहर लाल को विदाई देते एसएसबी जवान। ● अमृत विचार

मजदूर परिवारों को आशियाना बनाने को टिन व अन्य समान देते जिपं सदस्य प्रेम आर्या।

अग्निकांड पीड़ित छह मजदूरों के आशियाने बनाने में की मदद

शांतिपुरी : जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्या व समाजसेवी चंचल कोरंगा ने सेंचुरी पेपर मिल के माध्यम से बीते दिनों गडरिया ग्राम सभा के पीको में अग्निकांड से प्रभावित छह मजदूरों के आशियाने बनाने के लिये सेंचुरी मिल के माध्यम से 42 टिन, आर्थिक सहायता राशि, राशन, कपड़े मदद रूप में दिए। इसके साथ ही शांतिपुरी नंबर 4 के ग्रामीणों ने बच्चों के लिये कॉपी किताब व पेन भी दिये। जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्या ने बताया कि उन्होंने सेंचुरी पेपर मिल लालकुआं अधिकारी नरेश चंद्रा से सम्पर्क कर मजदूरों की झोपड़ी जलने व उनकी आर्थिक स्थिति से अवगत किया। जिस पर नरेश चंद्रा ने मजदूरों की झोपड़ी के लिये 42 टिन की व्यवस्था हेतु आर्थिक मदद की।

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला

सितारगंज : बाइक की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं, मामले में पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

छिनकी फार्म, खटीमा निवासी जगजीत सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर को वह पत्नी गुरविंदर कौर के साथ सितारगंज आया था। रामलीला मैदान से खरीदारी करने के बाद जब वह सड़क पार कर रहा था। तभी पीछे से आए एक बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जगजीत सिंह ने बताया कि उसे उप जिला अस्पताल सितारगंज में भर्ती कराया गया है।

ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग सदैव अहम

संवाददाता, खटीमा

अमृत विचार: खटीमा रेंज मुख्यालय में माह के अंतिम शनिवार को आयोजित मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम एवं प्रचार के लिए ' प्रभाग दिवस कार्यशाला' का आयोजन किया गया। जिसमें खटीमा रेंज के आज पास के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि आजकल बढ़ रहा मानव वन्य जीव संघर्ष चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि वन विभाग इसमें तभी पूर्ण सफलता हासिल कर सकता है जब जनप्रतिनिधि और जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का सहयोग मिले। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। वहीं जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षु वन क्षेत्राधिकारी डॉली डोभाल, उप वन क्षेत्राधिकारी खीम सिंह सम्भल, वन दरोगा अमर सिंह, अनीता, हिमांशु पंत, सभासद दौलत सिंह, जोगेंद्र लाल, रंजना धामी आदि मौजूद रहे।

6 कुमाऊं जंगी पल्टन, नाम इसका न्यारा..

संवाददाता, खटीमा

अमृत विचार: पूर्व सैनिकों द्वारा 6-कुमाऊं रेजीमेंट का 86वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

टनकपुर रोड अमाऊं में स्थित एक निजी प्रतिष्ठान के सभागार में छह कुमाऊं रेजीमेंट के 86वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवानिवृत्ति कैप्टन पुष्कर सिंह सामंत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कै. गंभीर सिंह धामी ने कालिका माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पल्टन गीत " 6 कुमाऊं जंगी पल्टन, नाम इसका न्यारा है...! गाया गया। वहीं कार्यक्रम में " बेडू पाको बारो मासा...." पर भी लोग जमकर झूमे। अध्यक्षता कर रहे सामंत ने 1962 के चीन और 1965 व 1971 के पाकिस्तान से हुए युद्ध में बटालियन के जवानों के शौर्य का बखान किया। उन्होंने कहा कि अपने शौर्य पर बटालियन के जवानों ने महावीर चक्र, वीर चक्र, विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि हासिल किए। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह, दीवानी चंद, महेश जोशी, गोपाल सिंह, आनंद सिंह, जगत सिंह, मोहन चंद, दीपक जोशी, राजेंद्र सिंह, मनोज सिंह, बिशन सिंह आदि मौजूद रहे।

खटीमा में उपस्थित पूर्व सैनिक और अतिथि। ● अमृत विचार

सनसनी

धर्मांतरण लेटर बम पर छिड़ी बहस, एक युवती ने आपबीती का आरएसएस कार्यालय में फेंका था खत

रुद्रपुर शहर में दोहरायी जा रही है द केरला फिल्म की कहानी

संवाददाता, रुद्रपुर

अमृत विचार : कोतवाली इलाके में द केरला स्टोरी फिल्म को दोहराए जाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा एक युवती ने आरएसएस कार्यालय में धर्मांतरण पत्र फेंक कर किया है। जिसके बाद लेटर बम पर बहस छिड़ गई है। धर्मांतरण लेटर में एक युवती का यह कहना था कि तराई भावर में धर्मांतरण गिरोह सक्रिय है और जिसमें विशेष समुदाय की कुछ युवतियां बेहद सक्रिय हैं, जो दूसरे समुदाय की युवतियों से दोस्ती कर विशेष समुदाय के युवकों से मिलवाती हैं और फिर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। युवती ने हिंदूवादी संगठनों से खत को गंभीरता से लेते हुए खुलासा करने का मुद्दा उठाया।

भोली भाली युवतियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का दबाव बनाना, कोई जाति-समुदाय या फिर राजनीति का मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार एक युवती ने अपने धर्मांतरण पत्र में द केरला फिल्म स्टोरी का जाल बिछाने का खेल खेला है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार युवती ने भयभीत होकर पत्र लिखा है। उससे साफ है कि यह विशेष समुदाय की एक युवती का गिरोह नहीं है, इसके पीछे बड़ा गिरोह सक्रिय है। लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही एसएसपी से मुलाकात कर पर्दाफाश किए जाने का मुद्दा उठाया जाएगा।

-शिव अरोरा, विधायक रुद्रपुर।

प्रदेश की धामी सरकार ने लैंड जिहाद हो या फिर लव जिहाद का मुद्दा, इसे गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि लैंड जिहाद व लव जिहाद पर सख्त कानून भी बनाया है। जिसका जिक्र यूजीसी में भी किया है। यदि धर्मांतरण गिरोह के सक्रिय होने का मामला सत्य है तो इस मुद्दे को लेकर जल्द ही सीएम से वार्ता की जाएगी। किसी भी जाति-धर्म की बहन बेटियां हों, उसे धर्मांतरण के मकड़जाल में फंसने नहीं दिया जाएगा और ऐसे गिरोह पर कठोर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया में खबर आने के बाद एसएसपी से वार्ता कर कार्रवाई की बातचीत हुई है। जिसके लिए एक टीम का गठन कर दिया है।

-विकास शर्मा, मेयर

धर्मांतरण लेटर प्रकरण की होगी जांच

रुद्रपुर : सोशल मीडिया पर धर्मांतरण गिरोह सक्रिय होने का मामला संज्ञान में आया है। जिसको लेकर कोतवाली पुलिस की एक टीम का गठन कर दिया गया है। जो लेटर की जांच कर उसकी युवती की खोजबीन करेगी। जिसने आपबीती या फिर खुलासा किया है। गठित टीम सीडीआर के माध्यम से मोबाइल नंबरों और लोकेशन खोजेगी। यदि प्रकरण सही पाया जाता है तो पुलिस गिरोह का पर्दाफाश कर कठोर कार्रवाई के लिए संकल्पित है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी।

बताते चलें कि काशीपुर हाईवे स्थित धार्मिक संगठन के कार्यालय में एक लेटर मिला था। जिसमें एक हिंदू युवती ने लिखा था कि कोतवाली इलाके की रहने वाली एक विशेष समुदाय की युवती ने उसके साथ दोस्ती की और फिर रामपुर यूपी ले जाकर अपने ही समुदाय के युवकों के साथ दोस्ती कराई। जहां उसके साथ घिनौनी हरकत हुई और फिर युवती ने धर्मांतरण नहीं करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। युवती का यह भी कहना था कि गिरोह की संचालिका का रिश्तेदार यूपी में धर्म की आड़ में शैक्षिक संस्था संचालित करता है। गिरोह में कई युवतियां हैं, जो भोली भाली युवतियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल रचती हैं। गिरोह के जाल में 40 युवतियां फंस चुकी हैं। युवती ने अपने हस्तलिखित पत्र में यह भी बताया कि धर्मांतरण का खेल रुद्रपुर, रामपुर यूपी, गदरपुर के अलावा कई स्थानों पर खेला जाता है और गिरोह में शामिल युवक युवतियों के साथ दोस्ती की आड़ में अवैध संबंध भी बनाते हैं। धर्मांतरण लेटर में यह जिक्र किया है कि उस पर अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। जिस कारण उसकी जान खतरे में है।

खत में युवती ने आरएसएस सहित हिंदूवादी संगठनों से मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही पूरे गिरोह को बेनकाब करने की गुहार लगाई। प्रकरण को लेकर बहस छिड़ चुकी है और जल्द ही बड़ा एक्शन होने की संभावना भी है।

किसान को सम्मानित करते पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह। ● अमृत विचार

गुलाब सिंह की भैंस व गाय ने जीती प्रतियोगिता

सितारगंज : पशुपालन विभाग की ओर से रविवार को अंजनियां गांव में ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारम्भ पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा ने दीप जलाकर शुभारम्भ किया। प्रदर्शनी में 80 पशुओं ने विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग किया। ग्राम मलपुरी के गुलाब सिंह की भैंस को चैम्पियन पशु के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दुधारू भैंस में भी गुलाब सिंह की भैंस ने प्रतियोगिता जीती। गाय दुधारू वर्ग में गुलाब चंद की गाय प्रथम, दीप सिंह अंजनिया की गाय द्वितीय रही। इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह ने पशुपालकों को योजनाओं, पशुओं के स्वास्थ्य व उपचार की जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह राणा, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी रुद्रपुर डॉ. पीके पाठक, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी खटीमा डॉ. राजेन्द्र राम, विजय कुमार मौजूद रहे।

अमृत विचार

हल्द्वानी , सोमवार,2 फरवरी 2026

काशीपुर

हाईलाइट

संकटमोचन श्री बालाजी घाटा मंदिर में माघ पूर्णिमा पर हुआ भव्य हवन

बाजपुर : माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर मोहल्ला बांकेनगर स्थित संकटमोचन श्री बालाजी घाटा मंदिर में विधि-विधान के साथ हवन-पूजन का आयोजन किया गया। पंडित अभिषेक शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराए गए इस अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की हवन के मुख्य यजमान धर्मेंद्र मौर्य एवं उनकी पत्नी मुस्कान मौर्य रहे। पंडित शर्मा ने माघ पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मुख्य सेवादार कुलदीप सैनी, हरी सिंह यादव, देवेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

कांग्रेसी नेता सहगल के पिता के निधन पर जताया शोक

काशीपुर : जनजीवन उत्थान समिति द्वारा रविवार को एक शोकसभा समिति के सभागार स्व .सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मार्ग पर स्थित श्री जगदीश प्रेरणा भवन में की गई। जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप सहगल के पिता समाजसेवी रमेश चंद्र सहगल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर शोक जताया गया। शोक सभा में समिति अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा, विवेक कुमार मिश्रा, भास्कर त्यागी एडवोकेट, देवांग मिश्रा, राम शर्मा, शालिनी मिश्रा आदि मौजूद रहे।

लूट का फरार आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार

किच्छा : पुलभट्टा पुलिस ने बीते 22 जनवरी को ग्राम बरा में हुई डकैती का खुलासा करते हुए दूसरे फरार आरोपी अबरार हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली निवासी आरोपी को पुलिस ने बहेड़ी-किच्छा मार्ग से अवैध तमंचे और कारतूस के साथ दबोचा। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूटे गए सोने-चांदी के जेवर और 20 हजार रुपये की नगदी भी बरामद की है। थानाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया कि अबरार ने अपने भाई इस्लाम और साथी शकील के साथ मिलकर परिजनों को बंधक बनाकर लूट की थी। आरोपी पर बरेली और पीलीभीत में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब तीसरे फरार आरोपी शकील की तलाश में जुटी है।

जसपुर में गुलदार की दस्तक

जसपुर : स्थानीय एक पेट्रोल पंप पर देर रात गुलदार की दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गुलदार के आने की खबर सुन आसपास के लोग सकते में हैं। जानकारी के मुताबिक काशीपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात करीब 12 बजे गुलदार पहुंच गया।

जसपुर में कलश यात्रा निकालते श्रद्धालु। ● अमृत विचार

जसपुर में निकली कलश यात्रा

जसपुर : ठाकुर मंदिर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले नगर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह-जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। रविवार की सुबह रिमझिम बारिश के बीच ठाकुर मंदिर परिसर में महिलाएं एवं श्रद्धालु एकत्रित हुए। मंदिर में पहले विधि विधान के साथ पूजा की गई। इसके बाद 108 कलशों की आचार्य खीमानंद भट्ट ने मंत्रोच्चारण कर पूजा की। सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने कलश के साथ यात्रा प्रारंभ की। मंदिर के महंत बाबा भागवत दास महाराज के नेतृत्व में यात्रा बारी चौक, लकड़ी मंडी होते हुए पतरामपुर रोड स्थित बड़ा शिव मंदिर पहुंची। यहां कलश यात्रा का स्वागत किया गया। बड़ा शिव मंदिर से पूजा कर कलशों में जल भरकर यात्रा ने वापस ठाकुर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान दीप भट्ट, कुसुमपाल नाथ, सतपाल, विमल अग्रवाल, सौरभ, नितिन कुमार, विनोद अरोरा, गौरव वशिष्ठ, गोलू, आयुष, मुकुल, स्वाति, अनु, लक्ष्मी, प्रीति, सारिका आदि मौजूद रहे।

सैनिक कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन, जाति के भेदभाव से ऊपर उठने की अपील

हिंदू समाज को संगठित करने का किया गया आह्वान

संवाददाता, काशीपुर

अमृत विचार: सैनिक कॉलोनी स्थित मंगल बाजार शिवालिक बस्ती में ''विराट हिंदू सम्मेलन'' का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सनातन संस्कारों को मजबूत बनाना और जाति-भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जगाना रहा।

रविवार को वार्ड संख्या 1 एवं 35 के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एक निजी अस्पताल के निदेशक डॉ. अभिषेक दुबे और मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रांतीय कार्यवाह डॉ. दिनेश सेमवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अपने संबोधन में डॉ. सेमवाल ने संघ के शताब्दी वर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमालय से सागर तक फैली हमारी प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है। उन्होंने जोर दिया कि नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने के लिए घरों में वेद, पुराण, रामायण और गीता पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और कुटुंब प्रबोधन जैसे ''पंच परिवर्तन'' विषयों पर भी विस्तार से मार्गदर्शन किया। उदासीन आश्रम के संत सुखपाल सिंह ने श्री गुरुनानक देव और गुरु तेग बहादुर जी के विचारों को साझा किया। वहीं महिला वक्ता सुरभि बंसल ने महिलाओं से सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें जातियों को भुलाकर अपनी पहचान केवल ''हिंदू'' के रूप में उजागर करनी चाहिए।

जसपुर में हिंदू सम्मेलन में उपस्थित अतिथि एवं संयोजक। ● अमृत विचार

जसपुर में हुआ विराट हिन्दू सम्मेलन

जसपुर : विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहां बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को भूतपुरी रोड स्थित महादेव नगर कॉलोनी में आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे संस्कार भारती मंचीय कला विभाग के अखिल भारतीय संयोज क देवेंद्र सिंह एवं माधवी सिंघल, कीर्ति बल्लभ मंदोलिया का कार्यक्रम संयोजक खड़क सिंह तथा सहसंयोजकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई तथा आरती का गायन हुआ। गायिका पुनीता ने श्री राम नाम के गीत सुनाये। रामलाल इंका के हर्ष ने आपसी सद्भाव से रहने को कहा, अभिनव ने श्रोताओं को लवकुश प्रसंग सुनाया। माधवी सिंघल ने परिवार में एकजुट रहने एवं कुटुंब की परिभाषा को समझाया। कीर्ति बल्लभ मंडोलिया ने सनातन धर्म का सम्मान करने, धार्मिक बनने पर जोर दिया। देवेंद्र सिंह ने आरएसएस की 100वीं जयंती पर प्रकाश डाला।

इस दौरान गुरुकुल शास्त्रीय संगीत विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सह प्रचार प्रमुख प्रेम सिंह ने किया। सम्मेलन में जिला संयोजक संजय अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका पार्षद बीना नेगी, पार्षद मयंक मेहता, ज्योतिर्मय बिष्ट, राजेंद्र सिंह रावत, प्रकाश नेगी, पार्षद दीपा पाठक, सूरज पटवाल मौजूद रहे।

दबिश देने गई एएनटीएफ टीम पर पथराव

सिपाही घायल, एएनटीएफ ने सुभाष कॉलोनी में भारी मात्रा में स्मैक की सूचना पर माफिया के घर दी थी दबिश

संवाददाता, रुद्रपुर

अमृत विचार : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम पर उस समय जानलेवा हमला हो गया, जब स्मैक की सूचना पर टीम ने एक नशा माफिया के घर दबिश दी। घनी आबादी वाली सुभाष कॉलोनी में हुई इस कार्रवाई के दौरान जैसे ही टीम आरोपी को पकड़कर बाहर निकली, परिजनों और स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में एक सिपाही के सिर पर ईंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य जवानों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई।

रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे एएनटीएफ को सूचना मिली कि सुभाष कॉलोनी निवासी कल्लू के बेटे भारी मात्रा में स्मैक की खेप खपाने की फिराक में हैं। सूचना पर पांच जवानों की टीम संकरी गली में स्थित संदिग्ध के घर पहुंची। टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर स्मैक की पुड़िया बरामद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे बाहर लाया गया, भीड़ ने ईंट-पत्थरों से हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में एएनटीएफ सिपाही भुवन पांडेय के सिर पर ईंट लगने से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। हमले का फायदा उठाकर पत्थरबाज आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर फरार हो गए। घायल सिपाही को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल सिपाही भुवन पांडेय।

घटनास्थल पर तैनात पुलिस बल। ● अमृत विचार

टूटी पड़ीं कुर्सियां। ● अमृत विचार

पिस्टल छीनने का प्रयास, फायरिंग की है चर्चा

रुद्रपुर : चश्मदीदों का कहना था कि जिस वक्त पत्थरबाज एएनटी एफ जवानों पर पथराव कर रहे थे। उस वक्त जवानों ने अपनी सरकारी पिस्टल निकालकर माफिया और पत्थरबाजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्थरबाजों ने पथराव करते हुए एक सिपाही का पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया। जब कामयाबी नहीं मिली। तो जवानों को भयभीत करने के लिए भीड़ के बीच किसी शख्स ने तमंचे से दो राउंड हवाई फायरिंग की। गोली की आवाज सुनते ही जवानों ने खुद को बचाने लगे और पत्थरबाजों ने जवानों का ध्यान भटकाते हुए माफिया को छुड़वा लिया। पुलिस गोलीबारी की चर्चा की पुष्टि में जुट गई है।

कबाड़ से स्मैक माफिया बना आरोपी

रुद्रपुर : सुभाष कॉलोनी के रहने वाले कल्लू नाम के व्यक्ति के चार बेटे हैं। चारों बेटे संकरी गली में अपना मकान बनाकर रहते है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के बेटे पहले कबाड़ का कारोबार करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से स्मैक का धंधा करने लगे। यही कारण है कि एएनटीएफ को सटीक सूचना थी कि नशा माफिया के घर में स्मैक की बड़ी खेप आई है और माफिया जल्द ही स्मैक को ठिकाने लगा सकता है। जिस को लेकर एएनटीएफ की टीम ने दबिश दी और पत्थरबाजी का शिकार हो गई।

बेहद संकरी गली मुसीबत की वजह

रुद्रपुर : नशा माफिया का घर जिस गली में बना है, वह बेहद ही संकरी है। हालात यह है कि गली में प्रवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर जाना ही संभव है। जैसे ही एएनटी एफ माफिया को हिरासत में लेकर लौट रही थी। उसी दौरान मुख्य द्वार और चारों ओर से बने घरों की छतों से पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी करने वाले माफिया के करीबी हैं। पथराव होने के बाद सकरी गली जवानों की मुसीबत की वजह बनी, क्योंकि सकरी गली होने के कारण एएनटीएफ के जवान खुद को संभाल नहीं पाए और मोर्चा बंदी करने की पर्याप्त जगह भी नहीं मिली। यही कारण है कि जवान बेबस हो गए और माफिया चंगुल से छूट कर फरार हो गया।

नशा माफिया द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम पर पथराव करने की घटना की जानकारी मिली है, क्योंकि वह देहरादून में हैं, लेकिन पथराव में एक सिपाही को घायल करना दुस्साहसिक वारदात है। अधीनस्थों को आदेशित किया है कि नशा माफिया के अलावा पत्थरबाजों को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और लगातार घायल सिपाही के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई जा रही है।

-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी।

सूचना मिलते ही सीओ प्रशांत कुमार, कोतवाल मनोज रतूड़ी और बाजार चौकी प्रभारी सुरेंद्र बिष्ट भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया।

जसपुर में प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करते कार्यकर्ता। ● अमृत विचार

एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत

जसपुर : एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नय्यर काजमी का जसपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस जिले में जब तक बूथ लेवल तक गठन नहीं होगा, तब तक पार्टी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के उत्तराखंड में आने का दावा किया। रविवार को लोनिवि गेस्ट हाउस पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नय्यर काजमी का जिलाध्यक्ष सादिक, नगराध्यक्ष शाने इलाही आदि ने स्वागत किया। डॉ. काजमी ने कहा कि पार्टी ने गढ़वाल प्रभारी बना दिया है। कुमाऊं में प्रभारी बनाना बाकी है। पार्टी तेजी से सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश में काम कर रही है। ईद के बाद विस चुनाव का बिगुल बजा दिया जायेगा।

खटीमा के शाहजी पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता में शिरकत करते बच्चे।

शाहजी स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी स्पेल बी प्रतियोगिता

खटीमा : शाहजी पब्लिक स्कूल में भाषा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिंदी और अंग्रेज़ी स्पेल बी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी स्पेल बी प्रतियोगिता में अनाबिया, अरशी, साबिया, अरमान, जुनेरा, अहमद, इकरा, ईशाना, शैज़ल, आलिया, शाज़िया, आशु, ज़मन और मैशर तथा अंग्रेज़ी स्पेल बी प्रतियोगिता में अनाबिया, अलवीरा, साबिया, अरमान, अलीना, माहीन, इकरा और मेहशर ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य रविन्द्र मिश्रा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि व्यक्तित्व विकास भी होता है। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक मोहम्मद फैज अली सिद्दीकी ने भी सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई दीं।

गांव में बिक रही कच्ची शराब पर रोक लगाने की मांग करतीं ग्राम कनौरा की महिलाएं।

अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

बाजपुर : ग्राम कनौरा की महिलाओं ने रविवार को अवैध कच्ची शराब के कारोबार के विरोध में कोतवाली पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ लोग धड़ल्ले से कच्ची शराब बेच रहे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। शराबियों द्वारा आए दिन होने वाली गाली-गलौज और मारपीट से महिलाओं व बच्चों में भय व्याप्त है।महिलाओं ने महिला उपनिरीक्षक रजनी गोस्वामी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस धंधे पर रोक नहीं लगी, तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगी। उन्होंने कहा कि शराब की लत युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। पुलिस ने महिलाओं को मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

एनएसएस शिविर में बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए

संवाददाता, बाजपुर

अमृत विचार: पीएमश्री राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह का शुभारंभ जिला समन्वयक धर्मेंद्र बसेड़ा ने किया। इस अवसर पर बालिकाओं ने सात दिवसीय कार्ययोजना की जानकारी साझा की और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

मुख्य अतिथि धर्मेंद्र बसेड़ा ने राष्ट्रीय सेवा योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए छात्राओं से स्वयंसेवक बनकर राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। विद्यालय की पूर्व उपप्रधानाचार्या इंदिरा पांडेय ने स्वयंसेविका की भूमिका में पूर्व में किए गए कार्यों का अनुभव साझा किया।

समारोह को जीवन सिंह सैनी, परमजीत कौर एवं अंजलि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व स्वयंसेविकाओं द्वारा कुमाऊंनी एवं पंजाबी नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम अधिकारी विमला रावत ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन रेनू चंद्रा सहित अर्चना सिंह, गीतांजलि, शिवराज सिंह, सागर आदि मौजूद रहे।

एनएसएस शिविर के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्य अतिथि धर्मेंद्र बसेड़ा।

धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

काशीपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत ने धोखाधड़ी से मकान बेचने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जसपुर के ग्राम मेघावाला निवासी रुबीना ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोडिया के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि उसने अपने गांव के ही निवासी अर्जुन सिंह से 29 नवंबर 2024 को 5.90 लाख रुपये में मकान खरीदा। अर्जुन सिंह ने 11 महीने के लिए रुबीना से मकान किराए पर ले लिया। अक्टूबर 2025 में जब रुबीना ने अर्जुन सिंह से मकान खाली करने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा। जानकारी करने पर पता चला कि अर्जुन सिंह ने अपना मकान वर्ष 2013 में जसवीर कौर नामक महिला को बेच दिया था।

प्रोफेसर रविंद्र कुमार को सम्मानित करते प्रधानाचार्य व अन्य। ● अमृत विचार

बेहतर भविष्य के लिए स्किल एजुकेशन से जुड़ें छात्र

शक्तिफार्म : पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा रविंद्र कुमार ने छात्रों को स्किल एजुकेशन से जुड़कर भविष्य बेहतर बनाने की सलाह दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार पाना नहीं वरन रोजगार मुहैया कराना होना चाहिए। ऐसा स्किल एजुकेशन से ही संभव है। उन्होंने घरेलू स्तर पर स्टार्टअप शुरुआत करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। कहा कि आसपास पाए जाने वाले अनेकों औषधीय पौधों की पहचान कर उनसे बनने वाली मेडिसिन का पेटेंट कर स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते है। ऐसा कर रोजगार के अवसर बढ़ा सकते है और दूसरों को रोजगार भी दे सकते है।

उत्साह

जन्मदिवस के अवसर पर कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने किया विधायक बेहड़ का गर्मजोशी से स्वागत

किच्छा में समर्थकों ने धूमधाम से मनाया विधायक बेहड़ का जन्मदिन

संवाददाता, किच्छा

अमृत विचार: पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का जन्म दिवस कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के बीच सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में विधायक बेहड़ ने केक काटा। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के आवास विकास स्थित कार्यालय पर विशाल पंडाल लगाकर जलपान की व्यवस्था की गई। किच्छा पहुंचने पर सर्वप्रथम व्यापारी नेता गुलशन सिंधी के नेतृत्व में सिंधी समाज द्वारा उनके आवास विकास स्थित आवास पर ढोल नगाड़ों के बीच जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सिंधी समाज के तमाम गणमान्य लोगों ने विधायक बेहड़ को फूल मालाएं पहनाकर तथा महिलाओं ने आरती उतारकर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। महिलाओं द्वारा फूलों की वर्षा कर विधायक बेहड़ का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात विधायक बेहड़ आवास विकास स्थित कार्यालय पहुंचे। विधायक बेहड़ ने अपनी पत्नी बीना बेहड़ एवं परिजनों व समर्थकों की मौजूदगी में विशाल केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस के अवसर पर किच्छा विधानसभा की जनता एवं समर्थकों का अपार स्नेह उन्हें मिला है, यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला है। मौके पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी सरवर यार खान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बबलू, विजय पाल यादव, मेजर सिंह, सतपाल गाबा, सुनीता कश्यप, किन्नू शुक्ला, मिसवाल कुरैशी, राजेश प्रताप सिंह, गुलशन सिंधी, विजय प्रकाश यादव, राजीव जग्गी, नजाकत खान, छोटे लाल कोली, हाजी भूरा कुरैशी, भूपेंद्र पपनेजा बंटी, निर्मल सिंह हंसपाल, पुष्कर जैन, राजू खुराना, शरद यादव, अरुण तनेजा, गौरव चावला, हरभजन सिंह मौजूद रहे।

किच्छा में विधायक बेहड़ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते समर्थक। ● अमृत विचार

गदरपुर में शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

गदरपुर : किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ का 69वां जन्मदिवस गदरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस नगराध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक ने शहीद ऊधम सिंह कंबोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात समर्थकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विधायक बेहड़ ने जनता का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास और जनसेवा का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रेमानन्द महाजन, सुभाष बेहड़, भीम ठुकराल, आर पी सिंह, राजकुमार भुल्ली, अजय गाबा, कृष्ण लाल अनेजा, सुमित्तर भूल्लर, कृष्ण सुधा, जगदीश भुल्ली, किशोर हलदार, मोहनीश चौधरी, किशोर सामंत आदि मौजूद रहे।

शांतिपुरी में काटा केक

शांतिपुरी : शांतिपुरी एवं जवाहरनगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने रविवार को कामधेनु दुग्ध समिति शांतिपुरी नंबर दो में विधायक तिलक राज बेहड़ का 69वां जन्मदिवस केक काट कर मनाया। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा, युवा कांग्रेसी नेता बिशन सिंह कोरंगा तथा वरिष्ठ कांग्रेसी जय दत्त जोशी ने तिलक राज बेहड़ की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्या, हेम सिंह नेगी, सैनिक संगठन अध्यक्ष लाल सिंह कोरंगा, देवेंद्र सिंह कोरंगा, कल्याण सिंह मटियानी, कविदत पांडे, बंसी मिश्रा, गांधी स्मारक निधि के प्रबंधक राज किरन तिवारी, मोहन प्रसाद, ओमप्रकाश आर्य मौजूद रहे।

बाजपुर गांव रोड स्थित पं .दलीप चंद्र शर्मा के खेत में बिछी लाही की फसल।

बारिश और तेज हवा से खेतों में बिछी लाही की फसल

बाजपुर : क्षेत्र में अचानक बदले मौसम, तेज बारिश और सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त करने के साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पकने को तैयार खड़ी लाही की फसल तेज हवा के कारण जमीन पर गिरकर बिछ गई है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। किसानों का कहना है कि फसल गिरने और नमी बढ़ने से पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा।मौसम में आए इस बदलाव से ठिठुरन बढ़ गई है और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से खराब हुई फसल का तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है।

तड़के सुबह हुई बारिश तो दिन में खिली धूप

काशीपुर : रविवार तड़के आई बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि सुबह 11 बजे से बारिश बंद हो गई और धूप दोपहर 12 बजे धूप खिलने के बाद लोगों को राहत मिली। तड़के चार बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जो करीब सुबह आठ बजे तक कई इलाकों में लगातार होती रही है।

अमृत विचार

हल्द्वानी , सोमवार,2 फरवरी 2026

स्टेट ब्रीफ

चंदन भगत बने जिला प्रकोष्ठ संयोजक

रानीखेत : भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर जिला इकाई तक आने पर दायित्व निभा चुके चंदन भगत को जिला प्रकोष्ठ संयोजक का दायित्व सौंपे जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी रानीखेत के जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने चंदन भगत को उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा व समर्पण को देखते हुए उन्हें जिला प्रकोष्ठ संयोजक का दायित्व सौंपा है। जिला प्रकोष्ठ संयोजक बनाए जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष दीप भगत, पूर्व जिला महामंत्री प्रेम शर्मा, छावनी परिषद सदस्य मोहन नेगी, पूर्व नगर अध्यक्ष राजेंद्र जसवाल, नगर अध्यक्ष ललित मेहरा, उमेश पंत आदि ने उन्हें बधाई दी है।

40 लीटर कच्ची शराब के साथ एक तस्कर दबोचा

बाजपुर : दोराहा चौकी पुलिस ने हरलालपुर स्थित ट्यूबवेल के पास छापेमारी कर रामनगर निवासी गुरमेल सिंह को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से एक कट्टे में भरे 88 पाउच बरामद हुए, जिसमें लगभग 40 लीटर अवैध कच्ची शराब थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उप निरीक्षक जगदीश तिवारी समेत सुनील कुमार, विजय पाल रहे।

हिंदू समाज की एकजुटता से ही राष्ट्र का उत्थान संभव: वतन

टनकपुर के छीनीगोठ स्थित देवभूमि रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित

- गो माता पूजन एवं दीप जलाकर के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन

संवाददाता, टनकपुर

छीनीगोठ गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ मौजूद छात्राएं। ● अमृत विचार

अमृत विचार: छीनीगोठ के देवभूमि रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वामी इस्कान मन्दिर रुद्रपुर के सर्वमंगल गौर दास ने गो माता पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। जाति भेद को दूर कर समरस समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। कहा कि सभी हिंदू आपस में भाई-भाई हैं।

मुख्य वक्ता आरएसएस के पिथौरागढ़ विभाग प्रचारक वतन ने आरएसएस के इतिहास पर प्रकाश डाला। कहा कि हिंदू समाज की एकजुटता से ही भारत को सशक्त बनाया जा सकता है। काला झाला सैलानी गोठ के महंत संध्या गिरि महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संचालन दिनेश चन्द्र भट्ट एवं अम्बा दत्त पंत ने किया। विनेकानन्द विद्या मन्दिर टनकपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर व शारदा विद्या मन्दिर की बालिकाओं ने सरस्वती वन्दना, स्वागत गीत, लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सफल आयोजन में जितेंद्र, जगदीश चन्द्र जोशी, दिवाकर परिहार, जिलाध्यक्ष मुकेश जोशी, नारायण चिल्कोटी, हरीश कांडपाल, हरीश जोशी आदि ने सहयोग दिया। बाद में साधु-सन्तों की उपस्थिति में प्रसाद -वितरण एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पुष्पा विश्वकर्मा, ललिता सिंह, राधिका चन्द, इन्द्रदेव विश्वकर्मा, सोमवती, निर्मला जोशी, गीता जोशी, कमला चन्द,हेमराज, हरीश जोशी, सुनील नरियाल, गोविंद चौड़ाकोटी, कुबेर सिंह, नवीन जोशी, प्रवीण सिंह, नवीन भट्ट सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

ऋषिकेश एम्स में कार्यरत तलाकशुदा महिला की पुरुष मित्र ने की हत्या

देहरादून: ऋषिकेश में एक तलाकशुदा महिला की कथित तौर पर उसके पुरूष मित्र ने गोली मारकर हत्या कर दी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में किराए के घर में अकेली रहने वाली प्रीति रावत (32) को कथित तौर पर गोली मार दी गयी। उन्होंने बताया कि एम्स अस्पताल में सहायिका के पद पर कार्यरत प्रीति के परिजनों ने हत्या का आरोप उसके पुरूष मित्र सुरेश गुप्ता पर लगाया है।

एसएसपी के अनुसार मृतका के पिता बच्चन सिंह रावत द्वारा घटना के संबंध में दी गयी तहरीर के आधार पर पुलिस कोतवाली ऋषिकेश में गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि प्रीति के साथ विवाह के लिए अपनी पत्नी से तलाक लेने, अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी ऋषिकेश में मकान न ले पाने और प्रीति के साथ शादी न कर पाने के कारण अवसाद में आरोपी ने उक्त घटना को अंजाम दिया है।

महिला को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद

संवाददाता, बागेश्वर

- बागेश्वर रेंज के मनकोट में वृद्ध महिला को बनाया था शिकार
- गुलदार को अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेजा गया

अमृत विचार: बीते 7 जनवरी को बागेश्वर रेंज के अंतर्गत मनकोट में वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाने वाला नरभक्षी गुलदार रविवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया। इससे ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वन अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए गुलदार की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच है तथा उसका ऊपरी दांत नहीं है, जिस कारण वह नरभक्षी बना है। गुलदार को अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सात जनवरी की सायं छाती मनकोट निवासी 65 वर्षीय देवकी देवी पर उस समय हमला किया था जब वह जंगल में लगी आग को अपने घास के ढेर में आने से रोक रही थी। ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद मध्य रात्रि में महिला का शव बरामद हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों व जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रभागीय वनाधिकारी का घेराव किया था तथा गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। तब से वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था परंतु गुलदार पिंजरे के बाहर चक्कर लगाकर चला गया था तथा रात में अन्य गांवों में दिखाई दे रहा था। इस पर वन विभाग ने ट्रैप कैमरा तथा पिंजरा लगाया था। जिस स्थान पर गुलदार कैमरे में कैद हुआ था शनिवार को विभाग ने उसी स्थान पर कैमरा लगाया और रविवार तड़के गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वन क्षेत्राधिकारी केएन पांडे के अनुसार रविवार सुबह लगभग चार बजे गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में पहुंचाया। बाद में उसे यहां से अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेज दिया गया। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र दस से बारह साल है तथा उसका ऊपरी एक दांत निकला हुआ है। संभवतः इसी कारण जानवरों का शिकार न कर पाने से वह नरभक्षी बना है।

स्व. रोहित वाणी मेमोरियल कप पर गोल्डन बॉयज ने किया कब्जा

संवाददाता, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता टीम को ट्राफी प्रदान करते अतिथि।

अमृत विचार: स्व. रोहित वाणी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। रविवार को प्रतियोगिता के तहत गोल्डन बॉयज और कसार वॉरियर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। जिसमें गोल्डन बॉयज ने शानदार जीत दर्ज कर ट्राफी पर अपना कब्जा जमाया।

नगर के जीआईसी खेल मैदान में आयोजित फाइनल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी और मेयर अजय वर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोल्डन बॉयज की टीम ने निर्धारित 15 ओवरों ने 110 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी कसार वॉरियर्स की टीम 67 रनों में सिमट गई। अतिथियों की ओर से विजेता और उपविजेता टीमों को ट्राफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर यहां पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोविंद पिलख्वाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, धमेंद्र बिष्ट, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पवार, पार्षद वंदना वर्मा, सूरज वाणी, अवनी अवस्थी, पवन नगरकोटी, राहुल कनवाल, धमेंद्र बिष्ट समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।

जीवित को मृत दिखाकर संपत्ति हड़पने का आरोप

संवाददाता, अल्मोड़ा

- मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
- गांव के ही एक व्यक्ति पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप

अमृत विचार: जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर लाखों रुपये की संपत्ति हड़पने का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार लाल सिंह, निवासी शिवलालपुर लामाचौड़, हल्द्वानी निवासी ने सोमेश्वर थाने में एक तहरीर सौंपी। तहरीर में कहा कि उनका भाई किशन सिंह बोरा 1994 से मुंबई में रहता था। वर्ष 2005 में वह संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। इस संबंध उनकी ओर से थाना बीपी रोड मुंबई में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच अब भी जारी है। कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनका भाई जिंदा है और दुर्गम स्थल के मंदिर में साधु बनकर रह रहा है। आरोप लगाया कि गांव के ही महेश बोरा ने वर्ष 2022 में भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर कैनरा बैंक चनौदा से लाखों रुपये और भाई संपत्ति को हड़प लिया। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर, कोतवाल मदन मोहन जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वैज्ञानिकों ने पर्वतीय खेती को लाभकारी बनाने के गुर सिखाए

संवाददाता, अल्मोड़ा

वीपीकेएएस में किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। ● अमृत विचार

अमृत विचार: विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने पर्वतीय क्षेत्रों की खेती को लाभकारी बनाने के गुर सिखाए।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कटाई उपरांत अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी की अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 'कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकी व कृषि उद्यम विकास' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें अल्मोड़ा व बागेश्वर के अनुसूचित जाति के 17 किसानों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मी कांत के निर्देशन में हुए प्रशिक्षण में कृषि को उद्यमिता से जोड़कर आय बढ़ाने को प्रेरित किया गया। वैज्ञानिक भंडारण, कीट प्रबंधन, कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकी, कठिन श्रम प्रबंधन के गुर सिखाए। मंडुआ थ्रेशिंग तकनीक, सोयाबीन व भट से टोफू और दूध बनाने, आटा चक्की के संचालन, मशीनों की सफाई व रख-रखाव का भी प्रशिक्षण दिया। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, विपणन, ब्रांडिंग व सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया। यहां डॉ. मनोज कुमार, डॉ. कुशाग्रा जोशी रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाई दीं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कामना की।

भारत बौद्धिक परीक्षा में विद्यार्थियों ने दिखाया अपनी प्रतिभा का दम

संवाददाता, खटीमा

- विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान व दिल्ली विवि का आयोजन
- विजेताओं को जयपुर में किया जाएगा पुरस्कृत

अमृत विचार : हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत बौद्धिक परीक्षा आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य युवाओं के समग्र बौद्धिक विकास के साथ-साथ उन्हें प्राचीन भारत की समृद्ध वैदिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना है।

महाविद्यालय के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र विक्रम सिंह पड़ियार की मौजूदगी में आयोजित परीक्षा में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, योग, खगोल विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों पर आधारित 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से प्रतिभागियों को 80 प्रश्नों के उत्तर देने थे।

डॉ. पड़ियार ने बताया कि परीक्षा के लिए 85 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था जिनमें से 65 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में सहभागिता की। प्राचार्य प्रो. पंकज कुमार पांडे ने प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को सफलता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 16-17 फरवरी को जयपुर में पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ. पड़ियार ने कहा कि प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, संगीत, नाट्यकला, योग, खगोल विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र एवं भाषा विज्ञान जैसे विषय अत्यंत उच्च स्तर पर विकसित थे। भारत की इसी गौरवशाली ज्ञान परंपरा के कारण विश्व के विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहां अध्ययन एवं शोध के लिए आते थे। नई पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में आब्जर्वर के रूप में राम कुमारी अग्रवाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रतिनिधि त्रिलोक जोशी मौजूद रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

घर के बाहर से स्कूटी व बाइक चोरी, रिपोर्ट दर्ज

काशीपुर: घर के बाहर से पहले स्कूटी व ढाई माह बाद बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जिसमें चोर बाइक ले जाता हुआ नजर जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की है।

पुलिस को दी तहरीर में मोटेश्वर मंदिर के पीछे, उज्जैन कॉलोनी, जसपुर खुर्द निवासी राकेश मदान ने बताया कि उसने रोजाना की तरह बीती 13 जनवरी को भी अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ी की थी। जिसे चोर चोरी कर ले गये। चोरी की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर मास्क लगाकर बाइक चोरी करने आया था। उसने बताया कि इससे पूर्व 29 नवंबर 2025 को भी उसी जगह से उसकी स्कूटी भी चोरी हुई है।

शिव महापुराण में भगवान शंकर की महिमा का बखान

प्राचीन शिव मंदिर चांदनी चौक बल्यूटिया में आयोजित कथा के दौरान मौजूद श्रद्धालु।

संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार : प्राचीन शिव मंदिर चांदनी चौक बल्यूटिया में 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है।

पांचवें दिन कथावाचक डॉ. नवीन चंद्र उपाध्याय शास्त्री ने भगवान शिव की महिमा बताई। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मनीष कुल्याल, हरीश चंद्र गुप्ता, लक्ष्मण सिंह मेहरा, राजेंद्र सिंह दरम्वाल, मनोज बोरा, हुकुम सिंह अधिकारी, कुंदन बोहरा आदि मौजूद रहे।

बिना सुरक्षा के खंभों पर चढ़ रहे श्रमिक

बाजपुर: नगर के वार्ड-13 स्थित इंदिरा कॉलोनी को 11 हजार केवी विद्युत लाइन से जोड़ने का कार्य सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। घनी आबादी और व्यस्त सड़कों पर श्रमिक बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के बिजली के खंभों पर चढ़कर काम कर रहे हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

स्थानीय लोगों ने ऊर्जा निगम और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा किट की मांग की है। मामले में ऊर्जा निगम के ईई विवेक कांडपाल ने कहा कि ठेकेदार को सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्य में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

हर्षोल्लास से मनाई गई रविदास जयंती

- कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में चला सफाई अभियान

संवाददाता, टनकपुर

टनकपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राएं।

अमृत विचार: संत शिरोमणि रविदास की जयंती जनपद चम्पावत में विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों, नगर निकायों एवं कार्यालयों में श्रद्धा, उल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाई गई। प्रातः सीडीओ डॉ. जीएस खाती सहित जनपद के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों द्वारा कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। सभी ने साफ-सफाई बनाए रखने तथा संत रविदास जी के संदेशों को व्यवहार में उतारने का संकल्प लिया। इसी क्रम में राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास टनकपुर में वार्डन प्रेमा ठाकुर के निर्देशन में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान परिसर भक्तिमय एवं प्रेरणादायी वातावरण से ओतप्रोत रहा।

सीडीओ डॉ. जीएस खाती ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन सामाजिक समरसता और समान अवसरों की प्रेरणा देता है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक और जागरूक समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र प्रकाश ने संत रविदास के जीवन, विचारों एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज को समरसता, समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं तथा युवाओं को नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में सफाई करते एनएसएस स्वयंसेवी। ● अमृत विचार

एनएसएस शिविर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

बागेश्वर : सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अवधेश तिवारी के नेतृत्व में शिविरार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में सफ़ाई अभियान चलाया जिसमें उन्होंने कंटीली झाड़ियां काटीं तथा महाविद्यालय परिसर के चारों ओर कूड़े को साफ किया। इसके बाद बौद्धिक सत्र में महाविद्यालय के इतिहास विभाग के डॉ. दिवाकर टम्टा ने राष्ट्रीय सेवा योजना की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए शिविर से होने वाले लाभ के बारे में बताया। इस अवसर पर अंकिता पांडे, पूजा साह, पूजा फुलर, भास्कर पांडे, आफ़रीन खातून, रिया रावत, प्रशांत, हिमानी, संजना आदि शिविरार्थी मौजूद रहे।

राजा युवा मोर्चा, मीनाक्षी महिला मोर्चा की अध्यक्ष

शक्तिफार्म : भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल की सहमति पर, मंडल अध्यक्ष गोविंद तालुकदार ने शक्तिफार्म मंडल में संगठन मजबूती के लिए राजा हालदार को युवा मोर्चा अध्यक्ष, मीनाक्षी विश्वास महिला मोर्चा अध्यक्ष, शंकर गोलदार किसान मोर्चा अध्यक्ष, सेवा सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष, मुकेश कुमार अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष एवं मनजीत सिंह को अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मनोनीत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद तालुकदार ने कहा कि सभी नव मनोनीत मोर्चा अध्यक्ष, संगठन के प्रति समर्पित रहे हैं। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें नए दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं अध्यक्ष राजा हालदार ने भाजपा जिला अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष का आभार जताया।

न्यूज ब्रीफ

जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा के साथ 10 लोग गिरफ्तार

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से 25 लाख 18 हजार 5 सौ की जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की गयी है। इस मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल बार्डर क्षेत्र के रक्सौल में जाली मुद्रा के बड़े कारोबारी नेटवर्क का खुलासा किया है। सीमावर्ती क्षेत्र हरैया थाना की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने बड़ी कर्रवाई करते हुए 25 लाख की जाली नेपाली मुद्रा और 18,500 की जाली भारतीय मुद्रा के साथ 4 नेपाली नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गांजा तस्करों के हमले में आबकारी कांस्टेबल की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हाल में कथित रूप से गांजा तस्करों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 23 वर्षीय महिला आबकारी कांस्टेबल की यहां सरकारी निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी सौम्या को 23 जनवरी को गांजा तस्करों ने उस वक्त कार से टक्कर मार दी थी जब सौम्या ने कार को रुकने का इशारा किया था। टक्कर मारे जाने से सौम्या गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सौम्या को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें ''निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज'' (निम्स) में स्थानांतरित कर दिया गया जहां शनिवार रात को उन्होंने दम तोड़ दिया।

रांची में अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर छह बसें जलकर राख

रांची। रविवार दोपहर रांची के एक अंतरराज्यीय टर्मिनल पर लगी भीषण आग में वहां खड़ी कम से कम छह बसें जलकर नष्ट हो गईं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खादगढ़ा में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग एक खराब बस में लगी और उसने जल्द बस के अगल बगल खड़ी अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। खादगढ़ा पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि आग लगने के समय किसी भी वाहन में कोई भी मौजूद नहीं था।

राकांपा राजग में बनी रहेगी, विलय की अटकलों पर बोले सुनील तटकरे

कहा-संगठन दिवंगत अजित पवार की विचारधारा और मार्ग पर आगे बढ़ेगा

मुंबई, एजेंसी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा नीत राजग का हिस्सा बनी रहेगी और संगठन दिवंगत अजित पवार द्वारा निर्धारित विचारधारा एवं मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यह दावा किया जा रहा था कि राकांपा और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विलय की घोषणा की तारीख 12 फरवरी तय कर दी गई थी। राकांपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तटकरे ने कहा कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा रुख स्पष्ट है। हम पार्टी और अजित दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस रुख पर अडिग हैं। रायगड के सांसद ने कहा कि हम राजग के साथ हैं और राजग के साथ ही रहेंगे। अजित दादा ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया था।

तटकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ तालमेल का निर्णय अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की जल्दबाजी पर आलोचना का जिक्र करते हुए तटकरे ने कहा कि संविधान सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय महाराष्ट्र के हित में और राकांपा को मजबूत करने के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिरता और अजित पवार के विकसित राज्य के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए उनके शपथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है।

मैं राकांपा अध्यक्ष नहीं, खबरें निराधार : पटेल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी। पटेल ने एक्स पर कहा कि मैंने राकांपा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के संबंध में मीडिया में प्रसारित हो रही कुछ खबरों पर गौर किया है। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल का यह बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतना बड़ा फैसला हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और विधायकों से परामर्श करने, हमारे समर्पित पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने और हमारे सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं और सामूहिक इच्छा का सम्मान करने के बाद ही लिया जाएगा।

तटरक्षक बल राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभः राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बहु-स्तरीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट अंतर-सेवा समन्वय देखने को मिला। सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि संवेदनशील समुद्री परिस्थितियों के दौरान बल ने त्वरित और सशक्त प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिमी तट पर निगरानी बढ़ाई और उच्च सतर्कता बनाए रखी।

रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल को भारत की समुद्री सीमाओं पर विश्वास की दीवार बताते हुए कहा कि आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री प्रदूषण से निपटने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने कहा कि तटरक्षक बल राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ हैं।

गुरु रविदास के नाम का हुआ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम

- **प्रधानमंत्री ने हलवारा हवाई अड्डे पर किया टर्मिनल का उद्घाटन**
- **औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद**

जालंधर, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लां भी गए। इस बीच, मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे पंजाब में बुनियादी विमानन ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। रायकोट उपखंड के हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन परियोजना को पंजाब सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 54.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के जालंधर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर गोलीबारी

- **पांच गोलियां चलाईं, पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया**

मुंबई, एजेंसी

मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर शनिवार देर रात हुई गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी के समय शेट्टी अपने घर पर थे या नहीं। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने रात करीब पौने एक बजे नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की।

अधिकारी ने बताया कि कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे पर लगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद इमारत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी ने इमारत पर गोली चलाई। क्षेत्रीय पुलिस और अपराध शाखा की टीम मामले की जांच कर रही हैं।

अधिकारी ने कहा कि वारजे मालवाड़ी थाने के कर्मियों द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान पुणे शहर के कारवेनगर और धायरी इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि जुहू पुलिस और अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंचीं तथा जांच शुरू कर दी। घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस इमारत के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल कर रही है। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची। निर्माता एवं निर्देशक शेट्टी गोलमाल, सिंघम और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

पलामू में पति-पत्नी और बेटे की हत्या बहु-पोती गंभीर

रांची, एजेंसी: झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसडी गांव में पति-पत्नी और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान विजय भुइयां, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। इस हमले में विजय भुइयां की बहु नीलू देवी और पोती ममता कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को तीन लोगों की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

बलूचिस्तान में हुई हिंसा में भारत का हाथ नहीं पाकिस्तान के आरोप को निराधार बताया

- **विदेश मंत्रालय ने कहा-ध्यान भटकाने का काम कर रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान**

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हुई हिंसा में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें ''निराधार'' बताया और कहा कि ऐसा कहकर पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाता है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को ''बेतुके दावे'' करने की बजाय अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की उसकी सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हर बार जब कोई हिंसक घटना होती है, तो ऐसे दावों को दोहराने की बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

यह बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा हमलों में भारत पर शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। भारत ने पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे दमन को उजागर करके पलटवार किया।

बलूचिस्तान में 16 जगहों पर हुए हमले

गौरतलब है कि शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 16 जगहों पर हमले हुए। क्वेटा, ग्वादर, कल्लात, खारान, मस्तुंग, पसनी, दलबांदिन, नोशकी, बुलाइदा, टंप, मच और आसपास के इलाकों में विस्फोट और सशस्त्र हमलों की सूचना मिली। बलूचिस्तान में हुई हिंसा की जिम्मेदारी शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ''ऑपरेशन हेरोफ फेज दो'' के हिस्से के रूप में ली। बीएलए के अनुसार दस घंटे की अवधि में 14 शहरों में हुए हमलों में सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

हमलों में मारे गए थे 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी

बलूच समूह ने दावा किया कि हिंसा में 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, 18 को जिंदा पकड़ा गया, 30 सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया या जब्त कर लिया गया और 23 दुश्मन वाहनों में आग लगा दी गई। बीएलए ने यह भी कहा कि उसने केंद्रीय सैन्य मुख्यालय सहित कई दुश्मन चौकियों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे कई शहरों में आवाजाही प्रतिबंधित हो गई। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में हमलों की पुष्टि हुई।

बजट पर प्रतिक्रियाएं

एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार

आम आदमी के लिए खास नहीं उद्यमियों को तमाम सुविधाएं

केंद्रीय बजट 2026-27

- **आईआईए लखनऊ में बजट देखने और चर्चा सत्र का हुआ आयोजन**
- **उद्योग जगत ने बताया भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित बजट**

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ में आम बजट पर चर्चा करते आईआईए के पदाधिकारी। ● अमृत विचार

अमृत विचार: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने रविवार को आईआईए भवन, लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर चर्चा सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नीति विशेषज्ञ बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर पर आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमित कुमार सिंह, डिविज़नल चेयरमैन विकास खन्ना, एसके चेयरमैन (अयोध्या) कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, लखनऊ चैप्टर चेयरमैन गुप्ता, अविरल कुमार, अक्षय कुमार सहित अनेक पदाधिकारी/उद्योगपति मौजूद रहे।

नॉन-पॉपुलिस्ट लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमईज के विकास के प्रति सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट स्पष्ट रूप से भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित है। इसके साथ उन्होंने बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े आवंटन, साथ ही सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रस्तावित एसएमई ग्रोथ फंड, भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सशक्त करने के साथ एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ देने की बात कही। उन्होंने इक्विटी स्पोर्ट, एसएमई ग्रोथ फंड, ट्रेंड्स प्राप्तियों को एसेट-बैक्ड सिक्योरिटी के रूप में मान्यता, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस, कॉर्पोरेट मित्र पहल और सेक्टर-स्पेसिफिक संरचनात्मक समर्थन को उत्साहजनक बताया।

हाई-टेक टूल रूम और जलमार्गों पर फोकस का स्वागत

आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने कहा कि हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए हाई-टेक टूल रूम की स्थापना, चैंपियन एमएसएमईज का निर्माण और रेयर अर्थ मैग्नेट पर नए सिरे से फोकस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 22 नए जलमार्गों और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की घोषणा को दूरदर्शी कदम बताया।

एमएसएमई के लिए तत्काल उपायों की कमी

आईआईए के पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए अपेक्षित स्तर का तात्कालिक समर्थन नहीं दिखता। कई घोषणाएं लंबी अवधि की हैं, जबकि वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए एक-वर्षीय तत्काल उपायों की ज़रूरत थी।

जेम-ट्रेंड्स इंटीग्रेशन से सुधरेगी एमएसएमईज की लिक्विडिटी

आईआईए की बैंकिंग समिति के चेयरमैन केके अग्रवाल ने जेम को ट्रेड से जोड़ने की घोषणा को अहम सुधार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमईज की लिक्विडिटी समस्याएं कम होंगी, अधिक सरकारी संस्थान और पीएसयू ट्रेड्स के दायरे में आएंगे और पेमेंट साइकिल तेज़ होगी।

एफटीए अनुरूप कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर से स्वदेशीकरण को बढ़ावा

आईआईए की जीएसटी समिति के चेयरमैन कपिल वैश्य ने कहा कि तैयार माल के बजाय कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करना, हाल ही में घोषित ईयू-एफटीए के अनुरूप है। यह नीति लंबे समय में स्वदेशीकरण को मज़बूत करेगी और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाएगी।

चैंपियन एमएसएमईज और इंडस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा पर ज़ोर

आईआईए के चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां, फाइनेंस और टैक्सेशन शशांक शेखर गुप्ता ने कहा कि बजट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पर दिया गया है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने की सरकार की यह मंशा को स्पष्ट करता है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को बल मिलेगा।

कैश फ्लो को मिलेगी मदद

सीए अशोक सेठ ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस में कमी से कारोबारियों के हाथों में अधिक नकदी आएगी, जिससे कैश फ्लो मैनेजमेंट और व्यवसाय विस्तार में मदद मिलेगी।

एक कार्यालय में बजट देखते लोग। ● अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार : उद्यमियों सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार का बजट दूरगामी बताया है, जबकि विपक्षी बजट को दमदार नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार के 9वें आम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि विदेश यात्रा, कैंसर की 17 दवाओं समेत, लिथियम बैटरी, कपड़ा, सीएनजी, माइक्रोवेव ओवन को सस्ता किया है। जबकि खनिज, स्क्रैप और शराब महंगी हुई है। डिफाल्टर आयकर करदाताओं के लिए सजा नहीं, बल्कि जुर्माने का प्रावधान किया है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं।

बजट में व्यवसाय क्षेत्र के लिए राहत है। छोटे उद्यमियों के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 10 लाख क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपये की सीमा तक जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई है। टीडीएस और टीसीएस दरों में राहत दी गई है। छोटे-मझोले आयकरदाताओं की सरलता के लिए आईटीआर रिवाइज की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। किसान आस लगा रहे थे कि किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ जाएगी जो पूरी नहीं हुई। हालांकि, आयात में टैरिफ 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के 40 हजार करोड़ का प्रावधान व बायोगैस के दामों में कमी की गई है। चमड़ा, वस्त्र परिधान और लिथियम पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। गृहणियों को भी कोई राहत नहीं है। गैस के दाम, गरम मसाले, आटा, दाल के भाव जस के तस हैं। पेश है सीए, उद्यमियों, नौकरीपेशा, किसानों और गृहणियों से हुई बातचीत के मुख्य अंश...

उद्यमीबोले बड़े उद्योगों पर टैक्स वृद्धि से व्यापार पर पड़ेगा असर: उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के आवास पर व्यापारियों ने बजट का लाइव प्रसारण देखा। व्यापारियों जिसमें बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की इस बजट में सात हाई स्पीड ट्रेन,सड़क, पुल व ई बस के संचालन के लिए विशेष पैकेज दिया है। उप्र उद्योग व्यापार मंडल के जिला मंत्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में चिकित्सा के लिए अधिक धन की व्यवस्था रखी गई तथा 17 मुख्य गंभीर बीमारियों की दवाओं के मूल्य कम किए हैं। परंतु व्यापार मंडल की मांग थी कि पंजीकृत व्यापारियों को चिकित्सा बीमा मिले परंतु वित्त मंत्री ने निराश किया। किसानों को विशेष पैकेज देते हुए लोन की सीमा तीन लाख से बड़ा कर पांच लाख कर दी। साथ ही कोको, काजू और चंदन की लकड़ी की खेती को बढ़ावा दिया है।

केन्द्रीय आम बजट

बजट सुधारों को अपनाया गया है

केंद्र सरकार का युवा शक्ति ड्राइवर बजट है जो कि गरीबों, वंचित और पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित बजट है। चैंपियन एमएसएमई की कल्पना करते हुए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके अंतर्गत इक्विटी समर्थन जिसमें 10 करोड़ रुपये का फंड, व्यावसायिक सहायता एवं ट्रेंडस के माध्यम से तरलता सहायता के प्रावधान के साथ विनिर्माण क्षेत्र को अग्रिम क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर 2.0, टेक्सटाइल प्रमोशन, इलेक्ट्रॉनिक घटक योजना, किफायती रेल सामग्री योजना एवं उच्च मूल्य और तकनीकी रूप में उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना सम्मिलित है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार के द्वारा बजट सुधारों को अपनाया गया है चाहे वह एनआरआई, निर्माण क्षेत्र या फिर घरेलू क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर यह बजट इस वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिवेशों को ध्यान में रखते हुए देश में सभी क्षेत्रों के आंतरिक विकास उन्नयन एवं संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योगों में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जाना प्रशंसनीय है। यह बजट सरकार का कम राजकोषीय घाटे हेतु एक संतुलित बजट है।

-डॉ. राहुल कुमार मिश्रा, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

'रेवड़ी संस्कृति' की जगह तकनीकी सशक्तीकरण पर दिया गया जोर

महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये तक के उद्यमिता ऋण और हर जिले में 'गर्ल्स हॉस्टल' के साथ-साथ, दिव्यांगजनों के लिए 'सहारा योजना' और 'दिव्यांगजन कौशल योजना' की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 'मेंटल हेल्थ केयर' केंद्रों के विस्तार और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बुनियादी ढांचे में 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक निवेश, सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और रक्षा क्षेत्र में 'ड्रोन शक्ति 2.0' भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़े कदम हैं। शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के 'बोलबाले' का साक्षी है। यह बजट 'रेवड़ी संस्कृति' के स्थान पर तकनीकी सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। **-प्रो. अनामिका चौधरी,** अर्थशास्त्र विभाग। **-डॉ. शकुंतला मिश्रा** राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार केंद्रित बजट

बजट में व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के रूप में स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और मध्यम मुद्रास्फीति को शामिल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन, हरित ऊर्जा, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष कर संरचना के सरलीकरण और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे जैव-फार्मा, मत्स्य पालन और अन्य अनौपचारिक कृषि क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों पर दीर्घकाल में रोजगार सृजन और आय वृद्धि के दृष्टिकोण से विशेष बल दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में उच्च और सतत विकास के लिए नए उपक्रमों तथा उपयुक्त बजट आवंटन की घोषणा की गई है, जैसे दुर्लभ खनिज खनन पर अनुसंधान, सेमीकंडक्टर मिशन, समर्पित रासायनिक पार्क, वस्त्रों के लिए एकीकृत कार्यक्रम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड दिया गया है। परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया है। **-प्रो. सनातन नायक,** अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहब आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

बजट में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई, अवसंरचना, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक पहल है। बुनकरों, ग्रामोद्योग, ओडीओपी उत्पादों और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। कपड़ा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें मशीनरी के लिए कैपिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर के ज़रिए पारंपरिक क्लस्टर का मॉडर्नाइज़ेशन शामिल है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की गई है। **- डा. नीरज खन्ना,** अध्यक्ष हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)-मुरादाबाद

बजट में किसान, मजदूर, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इतना दूरगामी बजट से आम आदमी को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। सरकार वर्ष 2047 के सापेक्ष यदि 2026-27 पर फोकस करते हुए बजट पेश करती तब लोगों का भला हो सकता था। **- अजय सागर,** जिलाध्यक्ष सपा-रामपुर

केंद्र सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे समान है, युवाओं, किसानों और सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। आम जनता को राहत देने वाला बजट होना चाहिए था।

-मोहिब्बुल्लाह नदवी, सांसद रामपुर

जेफरी एपस्टीन फाइल : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू से पूछताछ का बढ़ा दबाव

लंदन, एजेंसी

- पूर्व प्रिंस पर महिला ने लगाया है यौन संबंध बनाने का आरोप

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के अपराधों के स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। विंडसर की शाही स्थिति उनके भाई और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने रद्द कर दी थी।

मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। महिला का दावा है कि वह विंडसर कैसल एस्टेट स्थित एंड्रयू के शाही निवास में गई थी। ब्रिटिश राजपरिवार के पूर्व सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाली यह दूसरी महिला है।

एंड्रयू लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, नवीनतम मामले में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जापान की यात्रा पर गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने हमेशा एपस्टीन के कृत्यों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता देते हुए मामले पर विचार किया है।

एपस्टीन के पत्राचार में मैक्रों का भी जिक्र

वाशिंगटन। जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर अपने पत्राचार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र किया था, जो एक प्रगतिशील एजेंडा को बढ़ावा देने की संभावनाओं में रुचि रखते थे। नए दस्तावेज़ों में रविवार को यह दावा किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एपस्टीन मामले में एक ई-मेल की कॉपी में यह कहा गया है। यह पत्र सितंबर 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे को एक ऐसी ई-मेल से भेजा गया था।

चिकित्सकों ने तलाश ली घातक सल्फास विषाक्तता की काट

- चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता

चंडीगढ़, एजेंसी

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एंव अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किये गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है। बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है। पीजीआईएमईआर के मुताबिक अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज में अहम बदलाव आ सकता है। इसमें कहा गया कि अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

कम लागत में अब आसानी से मिलेगा उपचार

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।

गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए था चुनौती

इसमें कहा गया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी, किफायती और साक्ष्य-आधारित उपचार की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

वर्ल्ड ब्रीफ

सिंगापुर में हिंदुओं ने मनाया थाईपुसम

सिंगापुर। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। मंत्री ने रविवार को थाईपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से श्री थेंदायुतुपानी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3 .2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ पालकुडम (दूध के पात्र) लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड (एचईबी) ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। शोभायात्रा में सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा एवं श्रमशक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रथीगा वेलाइथन भी शामिल थीं।

आइवरी कोस्ट में हादसे में 14 की मौत

अबिजान। आइवरी कोस्ट में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हादसा सुबह करीब पांच बजे कबाडूगू इलाके में हुआ और इसमें एक ट्रक शामिल था जो अनाज ले जा रहा था और जिसमें अवैध रूप से 69 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री अमादौ कोन ने कबाडूगू क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों को हादसे की शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया है।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को शुरू हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 500 सदस्य चुनेंगे।

एयर इंडिया की शंघाई दिल्ली उड़ान शुरू

बीजिंग। एयर इंडिया ने रविवार को शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। इसी के साथ लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद दोनों शहरों के बीच विमानन कंपनी की सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक, शंघाई और नई दिल्ली के बीच उड़ान शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान में 230 से अधिक यात्री सवार थे। लगभग छह वर्षों के बाद एयर इंडिया की उड़ानों की बहाली, 2020 की शुरुआत में सेवाओं के निलंबन के बाद महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आएगा

ट्रंप की जंग की धमकी पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दी चेतावनी

- खामेनेई ने दोहराया, ईरान पर हमलावरों को देंगे कड़ा जवाब

दुबई, एजेंसी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं।

उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दे सकता है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की ढुलाई होती है। खामेनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने कहा, हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

ईयू सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर क़ालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यत: प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

हालिया प्रदर्शन तख्तापलट जैसा

दुबई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक तख्तापलट से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ईरान में 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरानी मुद्रा रियाल के पतन के विरोध में हुए थे। जल्द ही ये खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गए।

फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम से पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येर्रावल्ली स्थित अपने फार्म हाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी बीआरएस अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनीतिक उत्पीड़न के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

सरकारों के हाथ से निजी कंपनियों को जा रही सत्ता

- संरा महासचिव ने किया शांति, न्याय, सतत विकास का आह्वान

न्यूयॉर्क, एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच शांति, न्याय और सतत विकास के लिए नए प्रयासों का आह्वान किया है। गुटेरेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया शायद हमारे समय के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण से गुजर रही है। सत्ता सरकारों से निजी तकनीकी कंपनियों के हाथों में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यवहार, चुनाव, बाजार और यहां तक कि संघर्षों को आकार देने वाली तकनीकें बिना किसी सुरक्षा घेरे के काम करती हैं, तो प्रतिक्रिया नवाचार नहीं, अस्थिरता होती है।

महासचिव ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानि 2026 की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2026 'अभी से निरंतर आश्चर्य और उथल-पुथल वाले वर्ष के रूप में आकार ले रहा है।' उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव के समय में वह उन सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, जो बताते हैं कि ताकतें कैसे काम करती हैं। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुटेरेस ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में, हम ऐसी कार्रवाइयों को चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो ठोस और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करें। हमारे संकटपूर्ण समय में शांति, न्याय, जिम्मेदारी और प्रगति की प्रतिक्रियाएं। महासचिव ने चैन रिएक्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दंड न मिलने का भाव संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, अविश्वास गहरा रहा है और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, मूल्य नहीं

संयुक्त राष्ट्र की ओर इशारा करते हुए गुटेरेस ने कहा कि संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने वाले लोग समझते थे कि हमारे संस्थापक दस्तावेजों में निहित मूल्य केवल ऊंचे विचार नहीं थे बल्कि स्थायी शांति और न्याय के लिए अनिवार्य शर्त थे।

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत

इस्तांबुल। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डोसेमेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

धोखाधड़ी में 36 भारतीयों सहित दो हजार गिरफ्तार

नोम पेन्ह, एजेंसी

- कंबोडिया में कैसिनो में छापामारी के दौरान की गई कार्रवाई

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने कहा कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पिछले सात महीनों में 23 देशों के कुल 5,106 धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इजराइल ने रफाह सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोला

काहिरा। इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है।

ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

न्यूयॉर्क, एजेंसी

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तेल के लिए चीन भी कर सकता है सौदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

आज का भविष्यफल

-पं.मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 2 फरवरी, सोमवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा 3 फरवरी 01 .52 तक तत्पश्चात द्वितीया।

आज का पंचांग

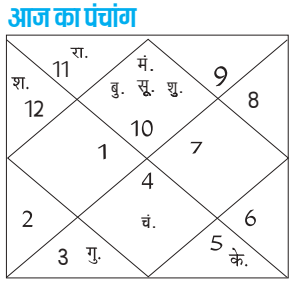

दिशाशूल- पूर्व, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-अश्लेशा 22 .47 तक तत्पश्चात मघा।

मेष — आज आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आएगी। अधिकारी वर्ग आपकी अनदेखी कर सकते हैं। विरोधियों को हल्के में न लें। अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

वृष — आज तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी योजनाओं को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें।

मिथुन — आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करने के लिए दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा।

कर्क — आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है।

सिंह — आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यवसाय में आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जॉब के अवसर मिलने की संभावना है। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

कन्या — आज दिन का शुरुआती भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखने को लेकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके ऊपर पुराने ऋण को चुकाने का दबाव हो सकता है। संपत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत होगी।

तुला — आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

वृश्चिक — आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

धनु — आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जॉब में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

मकर — आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दें। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी व्यक्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

कुंभ — आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

मीन — आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जॉब की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

सुडोकू-49

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

			6				8	
	8	9			4			5
3			2			7		
	2			8	9			6
		7				3	9	
9				1			4	
		1			7			8
4			1			9	5	
	9				5			

सुडोकू - 48 का हल

7	6	5	9	3	1	2	4	8
9	4	3	6	2	8	1	5	7
8	2	1	5	7	4	3	9	6
5	9	6	8	1	3	7	2	4
3	7	4	2	5	9	8	6	1
1	8	2	7	4	6	9	3	5
4	3	7	1	6	2	5	8	9
6	1	9	3	8	5	4	7	2
2	5	8	4	9	7	6	1	3

मुझे लगता है कि हमारी टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चेन्नई में हम तीन मैच खेलेंगे और हो सकता है कि वहां की पिच यहां की पिच की तुलना में अलग हो या फिर वैसी ही हो। और अगर ऐसा होता है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है।
-मिचेल सैंटनर

स्टेडियम

हल्द्वानी, सोमवार, 2 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

हाईलाइट

लवलीना, पूजा करेंगी भारतीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई

ला नुसिया (स्पेन)। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और ओलंपियन पूजा रानी मंगलवार को स्पेन के एलिकांटे के ला नुसिया में होने वाले बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत की 33 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता हितेश गुलिया और सचिन सिवाच भी इस टीम का हिस्सा हैं। निकहत ज़रीन (51 किग्रा) ने मार्च के आखिर में होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते में एक अहम कदम है - की तैयारी पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका

विक आन जी (नीदरलैंड्स)। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को यहां हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियास ब्लूबाउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंदा के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया।

अर्शदीप सिंह 'इम्पैक्ट प्लेयर' चुने गए

तिरुवनंतपुरम। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के पेसर अर्शदीप सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। बीसीसीआई ने रविवार को ड्रेसिंग रूम का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया। बीसीसीआई टीवी पर शेयर किए गए वीडियो में, ट्रेनिंग असिस्टेंट उडेनेका नेवान ने अर्शदीप सिंह को मेडल जीतने वाले के तौर पर अनाउंस किया, और पूरी सीरीज में लगातार इम्पैक्ट दिखाने के लिए बाएं हाथ के पेसर की तारीफ की। अर्शदीप ने यह सम्मान लेते हुए, सपोर्ट स्टाफ और फैंस को धन्यवाद दिया और सीरीज के दौरान टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ की।

दो अभ्यास मैच खेलेंगे तिलक वर्मा

मुंबई। भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई) से खेलने की मंज़ूरी मिल गई है और वह 2026 टी20 विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे। जनवरी की शुरुआत में रणजी ट्रॉफ़ी के दौरान लगी चोट के बाद अंडकोष की सर्ज़री कराने के चलते वे लगभग एक महीने से मैदान से बाहर थे। तिलक पहले 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के ख़िलाफ इंडिया ए टीम की ओर से खेलेंगे और इसके बाद 4 फरवरी को दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ भारत के अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे।

देविका सिहाग ने जीता पहला सुपर 300 खिताब

बैंकॉक, एजेंसी

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने रविवार को यहां 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा मैंने शुरुआत से ही अच्छी गति बनाने की योजना बनाई थी और वह कारगर रही। मेरा मानना है कि वह थकी हुई थीं और उन्हें ऐंठन भी थी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देविका इस जीत के साथ सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने हासिल की थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में कोच उमेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं। भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मैश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। गोह को देविका ने उन्हें कोर्ट पर खूब दौड़ाया।

प्रतिद्वंद्वी मलेशिया की गोह जिन वेई बीच से हटीं

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया। बाद में उन्होंने मुकाबला बीच में छोड़ दिया।

देविका ने चैंपियन बनने के बाद कहा आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि यह मेरा पहला सुपर 300 खिताब है। मैं भविष्य में और टूर्नामेंट खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। उन्होंने कहा मैंने यहां बहुत अच्छे मुकाबले खेले। मैंने काफी कुछ सीखा है। यहां मिली सीख को मैं अपने खेल में लागू कर गलतियों को सुधारूंगी। मैच में उतरते समय मैंने जीत या हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान रखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला।
-देविका सिहाग

थाईलैंड मास्टर्स

कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई ओपन : करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले बने सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी

मेलबर्न, एजेंसी

- नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया

कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लैंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, 'काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए।'

बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा। पिछले सत्र के आखिर में अल्कारेज अपने पुराने कोच जुआन कार्लोस फरेरो से अलग हो गए थे और सैमुअल लोपेज उनकी कोचिंग टीम के प्रमख बने।

जोकोविच ने मजाक में कहा कि यह मुकाबला अगले 10 वर्षों के लिए अल्कारेज के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत करेगा। उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि नए चैंपियन को आगे आने देना ही सही था। दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके।

> कोई नहीं जानता कि मैं यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने इस पल का बहुत पीछा किया। हमने बस सही काम किया, आप मुझे हर दिन सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो अभी मेरे साथ हैं।
> -कालोस अल्कारेज

> सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दो हफ्तों के लिए बधाई। आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इसलिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
> -नोवाक जोकोविच

करियर ग्रैंडस्लैम

जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब का इंतजार बढ़ा

नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जोकोविच और स्पेन के रफेल नडाल ने कुछ जबरदस्त मैच खेले जिसमें 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का अब तक का सबसे लंबा मैच भी शामिल है जो पांच सेट का फाइनल था और लगभग छह घंटे तक चला था।

अंडर-19 में शॉट लगाते वेदांत त्रिवेदी। एजेंसी

पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

बुलावायो, एजेंसी

अंडर-19 विश्वकप

- भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन
- पाक को सेमीफाइनल के लिए 33.3 ओवर में हासिल करना था लक्ष्य

वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगबाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गए।

17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

उत्तर प्रदेश की कप्तान मेग लानिंग का विकेट लेने के बाद जश्न मनातीं शिनेल हेनरी। एजेंसी

दिल्ली ने यूपी को 122 रनों पर रोका

वडोदरा, एजेंसी

महिला प्रीमियर लीग

मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में रविवार को यहां यूपी वारियर्स को आठ विकेट पर 122 रन के स्कोर पर रोक दिया। कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वारियर्स ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम कभी बड़े स्कोर की ओर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी।

वारियर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज दीप्ति शर्मा (24), शिखा पांडे (नाबाद 23) और सिमरन शेख (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। दिल्ली की टीम अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो मुंबई इंडियन्स को पछाड़कर गुजरात जाइंट्स के खिलाफ होने वाले एलिमिनेटर में जगह बना लेगी।

जेमिमा ने टॉस जीतकर वारियर्स को बल्लेबाजी का न्यौता दिया जिसे उनकी गेंदबाजों ने सही साबित करते हुए पावर प्ले में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन कर दिया। हेनरी ने मैच की पहली ही गेंद पर कप्तान मेग लेनिंग (00) को पगबाधा किया। दीप्ति शर्मा (24) ने हेनरी और कैप पर दो-दो चौके मारे। चार्ली नॉट (12) ने भी कैप पर चौका मारा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर विकेटकीपर लिजेल ली को कैच दे बैठी। दीप्ति ने कैप पर पारी का पहला छक्का मारा लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को निक्की प्रसाद के हाथों में खेल गईं। हरलीन देओल भी 11 गेंद में सिर्फ तीन रन बनाने के बाद श्री चरणी की गेंद पर पगबाधा हो गईं।

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, एजेंसी

टी-20 विश्व कप

5 दिन शेष

- लेकिन टूर्नामेंट में भाग लेगा बांग्लादेश का ले रहा पक्ष

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है।

यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।

विदर्भ से हारकर उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी से बाहर

नागपुर। गत चैंपियन विदर्भ ने रविवार को यहां उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे। दानिश मालेवार ने भी 54 रन की पारी खेली। उप्र की तरफ से स्पिनर शिवम शर्मा ने 55 रन देकर चार विकेट चटकाए।

बढ़ा मनोबल न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बना बनाकर टी-20 विश्व कप के लिए जता दिए अपने इरादे

ब्रेक और बल्लेबाजी में कुछ बदलाव से फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। उन्होंने कहा नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया।

सूर्यकुमार ने कहा मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करता था और मेरा स्ट्राइक रेट 200-250 रहता था। अब मैं शुरुआती पांच-सात गेंदों पर संभलकर खेलता हूं और उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट दोगुना कर लेता हूं। नागपुर में खेले गए पहले ही मैच से यह रणनीति कारगर साबित हुई, जिससे मुझे लय मिली और मेरी फॉर्म में सुधार हुआ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार को कप्तानी संभालने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने 2025 में 21 मैचों में केवल 218 रन बनाए। उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पांच मैचों में 80.66 के औसत और 196.74 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए। भारत की निगाहें अब लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर टिकी हैं।

टीम संयोजन को बनाया गया है बेहतर

सूर्यकुमार ने कहा कि गेंदबाजी से समझौता किए बिना बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए टीम संयोजन को भी बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी अपनी अनूठी पहचान लेकर आता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सभी राज्य और फ्रेंचाइजी स्तर पर अपनी शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। मैंने उन्हें अपनी शैली पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।